MR. DEPUTY SPEAKER : Taen you can continue tomorrow.

16.01 hrs.

I MOTION *RE* SITUATION ARISING OUT OF ANNUAL FLOODS AND DROUGHT IN VARIOUS PARTS OF THE COUNTRY

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, we are taking up the discussion under Rule 184 on floods and drought, for which no time has been allotted. We have to decide as t o how much time we would allow. For your information if the discussion goes on upto 9 or 100 clock, then it does not find place where it should be, the next day. So, I would like all hon. Members to be brief so that the Minister call be called at 7 0' clock. I think the House agrees with this

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (मैदपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि यह सभा देश के विभिन्न भागों में प्रतिवर्ष बाढ़ों तथा सूखे, जिनके कारण, जान, माल और फसलों को अत्यधिक हानि होती है तथा देश की अर्थ व्यवस्था पर गम्भीर रूप से कुप्रभाव पड़ता है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस स्थिति से निपटने के लिए तत्काल दीर्घकालिक और अल्पकालिक कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर विचार करती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं निश्चय ही यह बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है । इसका एक व्यक्ति या एक राज्य के साथ सम्बन्ध नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र से इसका सम्बन्ध है । हमारे देश में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, करोड़ों रुपये की फसल बरबाद होती है, हजारों आदमियों की मृत्यु हो जाती है, लाखों पशुओं को हानि होती है।

अकाल पड़ता है, उसके बाद भुखमरी होती है । इस सभा में भी इस विषय पर हर वर्ष चर्चा होती है, बहुत तेजी से हम शून्यकाल में भी बातें करते हैं । मंत्री जी भी बहुत अच्छे ढंग से जवाब देते हैं । तरह-तरह की योजनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन हम समझते हैं कि इसका कोई निष्कर्ष कम्पलीट रूप से नहीं निकलता है ।

प्राय: जब जुलाई, अगस्त और सितम्बर का महीना आता है तो बाढ़ की चर्चा होती है । क्योंकि ये महीने बाढ़ के महीने होते हैं । बाढ़ आने के पहले बराबर अखबारों, देश की अन्य संस्थाओं, सरकार की कमेटियों और राज्य सरकारों के माध्यम से चर्चा की जाती है कि बाढ़ आ रही है, आ गई है और इससे बचने के लिये उपाय करने चाहिये ।

सूखे का महीना दिसम्बर, जनवरी, फरवरी में आता है । इन महीनों के आते ही हम लोग बेचैन हो जाते हैं इनसे देश के किसी न किसी भाग में अवश्य सूखा होता है । दुर्भाग्य से हमारे मुल्क की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रतिवर्ष कहीं सूखा पड़ता है और कहीं बाढ़ आती है । जब बाढ़ आती है तो हमें राहत कार्य की चिन्ता होती है । राहत कार्यों को लेकर सब दौड़ते हैं, राज्य सरकारें राहत-कार्य में लग जाती हैं । बाढ़ के दिनों में बाढ़ तो आती ही है लेकिन राहत कार्यों की बाढ़ भी आ जाती है । इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में निरन्तर यह समस्या बनी हुई है और बाढ़ सूखे का हमको हर वर्ष सामना करना पड़ता है ।

प्रात: ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के जिम्मेदार लोग सब राहत कार्यों में लग जाते हैं । इस देश में एक कहावत चली आ रही है कि देश का किसान रबी और खरीफ की फसल काटता है और सरकारी लोग व नेता लोग राहत की फसल काटते हैं । हमारे यहां राहत कार्यों में धांधली होती है ।

1979-80 में हमारे देश में 11 राज्य सूखे से प्रभावित हुए थे । इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर और हिमाचल प्रदेश पूरी तरह सूखे से प्रभावित हुए थे ।

इस सूखे में 22 करोड़ मनुष्य, साड़े12 करोड़ पशु प्रभावित हुए। 4 करोड़ हैक्टेयर क्षेत्र की फसल देश में सूख गई। सूखे के कारण उत्तर प्रदेश, में 1980 में 1 हजार करोड़ रुपये मूल्य की फसल खरीफ की बर्बाद हुई। राजस्थान में 35,795 कुल गांव हैं। इनमें 1980 में 31,095 गांव सूखे से प्रभावित हुए और 12,060 गांव अभाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये। राजस्थान के अकेले प्रदेश में ही 2 करोड़ 40 लाख जनता सूखे से प्रभावित हुई।

उड़ीसा में 51,639 गांव हैं जिसमें 26,258 सूखे की चपेट में आ गये। बिहार में कुल 43,796 गांव हैं इसमें 3 करोड़ 28 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए। यहां 387 विकास खंड हैं इनमें से 320 विकासखंड सूखे की चपेट में आये। 6767 गांव में एक बूंद भी पानी नहीं मिला।

हरियाणा में 10 लाख लोग सूखे की चपेट में आये। बंगाल में 1 करोड़ 10 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए। देश में चारों तरफ खलबली मच गई।

इस वर्ष भी सूखे के कारण लोग चैन की सांस नहीं ले सके। चारों तरफ निराशा और भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। इस सदन में भी इस विषय को लेकर काफी हल्ला हुआ और सदस्य धरना देने बैठ गए। पानी और भूख से मरने वालों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई। 1980 में सरकार ने 156,95 लाख रुपए की सहायता दी, 80 करोड़ रुपए के अल्प-ऋण दिए और 2394 हजार मीट्रिक टन अनाज काम के बदले अनाज की स्कीम में लगाया।

लेकिन इसके बावजूद हमारी चेतना नहीं लौटी। इस भयंकरता के बाद भी हमको एह-सास नहीं हुआ। प्रधान मंत्री ने उसी समय कुछ राज्यों का दौरा किया। उनका दौरा इतना तूफानी था कि ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हमारे देश में बाढ़ और सूखे की विपत्ति नहीं आएगी ही नहीं, अब वह इस समस्या को पूर्ण रूप से हल कर देंगे। उसी समय 12-सूत्री कार्यक्रम तेजी के साथ अमल में लाया गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उस कार्यक्रम के 12 सूत्र प्रधान मंत्री के सूत्र के रूप में वहीं रह गए। जब भी देश में दिक्कतें आती हैं, तो प्रधान मंत्री का 5-सूत्री या 12 सूत्री या 20 सूत्री या 21-सूत्री कार्यक्रम चलता है। हमें इन कार्यक्रमों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उन पर कोई अमल नही हो पाता और वे मंत्रियों तक ही रह जाते हैं। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री ने इस समस्या की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया, जितना कि उन्हें देना चाहिए था।

उसके बाद सूखे के कारण 1981 में उत्तर प्रदेश; राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में भयंकर आफत आ गई। अरबों रुपये का नुकसान हुआ। यू० पी० में 800 करोड़ रुपए की खरीफ की फसल और 400 करोड़ रुपए की रबी की फसल बर्बाद हुई, हालांकि प्रधान मंत्री ने तीन चार महीने पहले ही वहां का दौरा किया था। प्रधान मंत्री सूखे की स्थिति को देखने वहां गई भी थीं। काश ! वह सूखे के साथ-साथ बाढ़ की स्थिति भी देख लेती, तो संभवतः यह बर्बादी न होती।

1982 में हरियाणा, यू० पी०, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल सूखे का शिकार हुए। यू० पी० में 700 करोड़ रुपए की फसल नष्ट हुई, 15 लाख टन खाद्यान्न कम उत्पन्न हुआ, 57 में से 46 जिले सूखे की चपेट में आ गए और 28,13,000 हैक्टेयर भूमि में सूखे के कारण भारी नुकसान हुआ। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में 50 करोड़ रुपए, पश्चिमी बंगाल में 10 अरब रुपए और केरल में 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। केवल सूखे के कारण 80 लाख टन अनाज का कम उत्पादन हुआ। हमारे देश में सूखे की यह भयावह स्थिति है।

1983 में केरल, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा। केरल

में 220 करोड़, महाराष्ट्र में 300 करोड़ रुपए और पश्चिमी बंगाल में 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश में 16,000 गांव सूखे की चपेट में आ गए और वहां कोई फसल नहीं हुई। राजस्थान में 22,000 गांव सूखे की लपेट में आए, जिनमें से आधे गांवों में फसल जल कर राख हो गई। 4,30,000 टन खाद्यान्न का कम उत्पादन हुआ, जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वयं सदन में बताया था।

1983-84 में भी सूखा पड़ा है, जिसके कारण आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, पांडिचेरी और मिजोरम इत्यादि प्रान्तों में बहुत बुरी तरह से तबाही आई।

यह बात माननीय मंत्री जी से छिपी हुई नहीं है कि तमिलनाडु में कितनी भयानक स्थिति थी। मंत्री जी ने इस बात पर अफसोस प्रकट किया था। उस प्रदेश में सूखे की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हो गयी थी कि एक आदमी को पानी तक मुहैया नहीं हो सकता था। एक पिता एक गिलास पानी पी रहा है, तो उसकी पत्नी पानी के लिए तरस रही है और बच्चा यह देख रहा है कि हम कैसे पानी पीयेंगे और मां-बाप मुझे पानी को देंगे या नहीं। 350 लाख 25 हजार एकड़ भूमि अभी हाल में सूखे से प्रभावित हुई है। जिसकी वजह से 6 लाख 30 हजार टन खाद्यान्न सामग्री कम पैदा हुई। जब कि अभी अन्य राज्यों की रिपोर्ट नहीं आई है। ये सब बातें जब मंत्री जी ने उत्तर दिया था, उसमें थीं।

हमेशा मानसून की वजह से सूखा पड़ता है। लेकिन हमारे देश में बाढ़ें भी आती हैं। यदि हम इसके कारणों में जायें, तो ऐसा प्रतीत होता है कि पानी की कमी की वजह से ही सूखा पड़ता है। बाढ़ की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश में पानी की भी कमी नहीं है। साल भर नदियों में पानी बहता है। हमारे देश में कुछ ऐसी नदियां हैं, लहरें हैं, जिनमें निरन्तर पानी बहता रहता है। फिर भी लाखों एकड़ जमीन सिंचाई के अभाव में बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। इन सब स्थितियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी योजनायें, हमारे कार्य और हमारी स्कीमें तत्कालीन स्थिति की ओर पहले ध्यान देती हैं। दूरगामी परिणामों की ओर ध्यान नहीं देती हैं। कहा जाता है कि सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए बांध बना रहे हैं। लेकिन आज तक जितने भी बांध बनाए गए हैं, चाहे वह उत्तर प्रदेश में हों या किसी भी अन्य प्रदेश में, वे सिंचाई के काम में ज्यादा नहीं आते हैं। उनका एक मात्र उद्देश्य होता है बिजली का उत्पादन करना। आज सूखे से निपटने के लिए नलकूपों का विस्तार उतनी मात्रा में नहीं है, जितनी मात्रा में होना चाहिए था। हमारी काम के बदले अनाज योजना भी गड़बड़ है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मुझे इस बात को कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि आज सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कोई भी प्रभावशाली कदम नहीं उठाया है। हमारा बीस सूत्री कार्यक्रम हो या 12 सूत्री कार्यक्रम, बाढ़ और सूखे से संबंधित, ये सब कार्यक्रम कागजों तक ही सीमित रहते हैं। इन कार्यक्रमों पर कोई सरकार की ओर कारगर कार्यवाही नहीं की जाती है। हम इसे गंभीरता से नहीं लेते। हमको ज्यादा से चेतना होती है तो हम खेल-कूद की ओर चले जाते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना रुपया आपने गत वर्ष एशियाड खेलों पर खर्च किया, यदि उतना रुपया आपने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए खर्च किया होता तो यह समस्या 80 प्रतिशत हल हो गई होती। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार 12 सूत्री कार्यक्रम चला रही है, क्या माननीय मंत्री जब उत्तर देंगे, तो बतायेंगे कि पूर्वकालिक राहत के नाम पर हमारे यहां क्या-क्या कार्यवाही हुई है? हम अभी बाढ़ से घिरे हुए हैं, फिर सूखा आने वाला है। उस समय पूर्वकालिक राहत के लिए अपने 12 सूत्री कार्यक्रम में क्या राहत देने के बारे में आप विचार कर रहे हैं?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : सूखा जरूर आएगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : सूखा देश में हर साल आता है । यही सोच कर कि सूखा नहीं आएगा, आप असफल हो जाते हैं । आपको यह पता नहीं है कि सूखा आने वाला है या नहीं है ? जब सूखा आजाएगा, तब यहां जिक्र होगा, हम और आप चिन्तन करने बैठ जायेंगे, कालिंग-एटैन्शन आजायगा । इस तरह से होता रहा है ?

12 सूत्री कार्यक्रम में एक प्वाइन्ट है कि अधिकारियों की नियुक्ति की जाय जो सूखे और बाढ़ के काम को देखें । मैं समझता हूं बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं जहां आज तक अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है । यह प्लान कागज पर ही लिखा रह गया । दो हजार की जनसंख्या पर एक उचित दर की दुकान खोलने का इस में प्रावधान है । मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में कह रहा हूं—जहां दस-दस हजार लोग रहते हैं, नदी के किनारे गांव हैं । बाढ़ में पूरा-का-पूरा गांव तबाह हो जाता है । वहां न लकड़ी मिलती है, न भूसा मिलता है । न चारा मिलता है, मनुष्य के खाने की बात तो कौन कहे । पिछले वर्ष हम ने यहां कुछ अखबारों और मित्रों को पेश किया था, जिन में लोग बाढ़ से वाराणसी, गाजीपुर जौनपुर में घिरे हुए थे यहां औरतों के लिये कोई स्थान नहीं था—वे टट्टी कहां जाये, पानी में बैठ कर टट्टी करती हैं । जिन लोगों को धर्म-शालाओं में भेजा गया, वहां चोरी और डकैती होती है । मैं यह बात गाजीपुर, बनारस, जौन-पुर, बलिया तथा कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में कह रहा हूं जहां इस प्रकार की घटनायें हुई हैं । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि हवाई सर्वेक्षण से काम चलने वाला नहीं है, नावों में चढ़ कर, जीपों के द्वारा वहां जा कर स्थिति को देखा जा सकता है ।

बिहार में पिछले साल बाढ़ आई थी और सूखा भी पड़ा था 12 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार सस्ती रोटी देने की बात चली थी । भ्रष्टाचार का यह भी अजीब तरीका था—सस्ती रोटी के लिये सस्ता गला चाहिए, सस्ता अनाज चाहिये और उस में भी ठेकेदारी प्रथा अधिकारियों की साजिश से शुरू हुई, भ्रष्टाचार हुआ । आप की यह योजना भी कारगर साबित नहीं हुई ।

कूओं की बोरिंग के सम्बन्ध में दो साल पहले मैं अपने क्षेत्र के ब्लाक अधिकारियों से मिला और कहा कि 12 सूत्री कार्यक्रम में यह भी है कि आम कूओं की बोरिंग करायेंगे । मैंने 20-22 कूओं की बोरिंग के लिये उन से कहा, लेकिन मेरे कहने के बावजूद तथा लाख प्रयासों के बावजूद एक भी कुंए का बोरिंग नहीं हुई । जब कि यहां पर कहा गया कि 20-25 हजार कूंओं की बोरिंग हो चुकी है । उत्तर प्रदेश से ऐसी रिपोर्ट आप के पास आई, लेकिन मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र सैदपुर में ऐसा कुछ नहीं हुआ ।

जैसा मैंने पहले भी आप से कहा है कि बाढ़, सूखा, तूफान जैसी चीजें हर स्थान पर कभी न कभी आती रहती हैं, जिन से भीषण तबाही होती हैं । कृषि और उद्योग की सब व्यवस्थायें छिन्न-भिन्न हो जाती हैं । 1977 में आंध्र प्रदेश में तूफान आया, भयानक बाढ़ आई, 10 हजार व्यक्ति उस में मारे गये । 1978-79 में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल से बाढ़ आई । 1 करोड़ 80 लाख हैक्टेअर में फसल

नष्ट हो गई। 40 लाख झोपड़ियां बरबाद हो गई, 2800 व्यक्ति मारे गये, 2 लाख पशुजान से चले गये। 1981 में बाढ़ आई एक हजार से अधिक व्यक्ति मारे गये, 241 लापता हो गये, 205 करोड़ रुपये की क्षति हुई, 10 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। 67 करोड़ 27 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के लोगों ने अपनी फसलों को अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा। 59 करोड़ रुपये की दूसरी फसलें नष्ट हुई। 2 लाख मकान गिर गये, जिनका मूल्य 15 करोड़ रुपये था। 65 हजार मवेशी नष्ट हो गये। 1982 में फिर बाढ़ आई-19 राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए जिन में दो केन्द्र शासित प्रदेश भी थे। 553 व्यक्ति मारे गये, 226 लापता हुए, 45 हजार मवशी नष्ट हुए, 1 करोड़ 47 लाख व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित हुए, 16 लाख 36 हजार हैक्टेयर में खेती नहीं हो सकी। 260 करोड़ रुपये की क्षति हुई, जिस में 137 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति थी। कितनी बड़ी भयानक बात है। ये केवल आंकड़े नहीं हैं, यह हमारे उन आंसुओं की स्थिति है, जो आंसू आज देश का हर व्यक्ति देखता है और उस को पी जाता है।

ऐसे ही राजस्थान की समस्या है और आसाम में है। मैं इस को शोर्ट कर रहा हूं। 1971 में हमारे मुल्क में 21 करोड़ रुपये की हानि हुई जबकि 5 वर्ष बाद 1976 में यह राशि बढ़ कर 630 करोड़ रुपये की हो गई। 1977 में यह लगभग दुगनी हो गई यानी 1130 करोड़ रुपये की हानि हुई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि लगातार धनराशि का नुकसान बढ़ता ही जा रहा है और सरकार या हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। 1983 की भी हम यही स्थिति देख रहे हैं। इस साल भी बाढ़ आई हुई है और गुजरात को हालत तो सब लोगों ने देखी ही है। अभी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों और विभिन्न स्थानों पर बाढ़ आई है और वे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बिहार में भी भयानक विभीषिका चल रही है। पश्चिम बंगाल की भी यही स्थिति है लेकिन इन सब संकटों के बावजूद लगातार ये संकट आते ही गये हैं, जिनका मैं आँकड़ा दे चुका हूं। इस प्रकार लगातार बरबादी के बाद भी हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके हैं कि आखिरकार इन सबका कैसे मुकाबला किया जाए। सरकार हमारी कहती है कि बाढ़ या सूखे पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। मैं मानता हूं कि यह विपत्ति अप्रत्याशित विपत्ति है और इस को हम देवी प्रकोप भी कह लेते हैं लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि आप यह कैसे कहते है कि हम इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं प्राप्त कर सकते। पूरा नहीं, तो आप ने आधा नियंत्रण भी इस पर नहीं किया है। आप बताइये कि आप ने कितना नियंत्रण इस पर किया है? मैं समझता हूं कि इस की विभीषिका बढ़ती ही जा रही है। आप कह रहे हैं कि सूखे का कारण पानी का अभाव है और बाढ़ का कारण पानी की अधिकता तो हम यह कहना चाहेंगे कि यदि हमारी योजना ठीक ढंग से बने तो 14,400 करोड़ एकड़ फीट पानी, जो सींचने के काम आ सकता है, उसका प्रति वर्ष नुकसान होता है। हमारे देश में 144 करोड़ एकड़ फीट पानी बहता है और उसमें 13 करोड़ एकड़ फीट पानी ही हमारी सरकार अब तक रोकने में सफल हुई है और इसका प्रयोग किया जाता है। 2000 ई० तक की जो आप की प्लानिंग है, उसमें 30 करोड़ एकड़ फीट पानी आप उपयोग में लाएंगे जिससे

हमारी समस्या बहुत ज्यादा हल हो जाएगी लेकिन मैं समझता हूं कि यह बहुत कम है । इससे हमारी कोई समस्या हल नहीं होगी । मौसम विज्ञान का आप सहारा लेते हैं लेकिन मैं देखता हूं कि मौसम विज्ञान की जितनी भविष्य-वाणियाँ होती हैं, वे अधिकांश ग़लत साबित होती हैं । मौसम विज्ञान कार्यालय जो भविष्य-वाणी करता है, उसे भी हम को देखने की जरू-रत है । यदि आन्ध्र में या गुजरात में सही ढंग से भविष्यवाणी की गई होती, तो आज ये परि-णाम न भुगतने पड़ते । हमें समय पर चेतावनी मिलती नहीं है । हम यह भी महसूस करते हैं कि जलाशय का जो पानी इकट्ठा करने का साधन है, यह भी वैज्ञानिक ढंग से गड़बड़ है । मेरा कहना यह है कि ऐसे इलाकों में अगर तालाब इत्यादि बना दिये जाएं, तो इन से सूखा और बाढ़ दोनों, समस्याओं को हल किया जा सकता है । मैंने पहले कहा है कि नहरों का निर्माण भी हमारे यहां उस ढंग से नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए । वैज्ञानिक ढंग से उनका निर्माण नहीं हुआ है और इसके कारण नहरों से अधिकांश पानी रिसता रहता है । कहीं पर पानी इतना ज्यादा है कि इस के कारण दूसरी खेती की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और कहीं-कहीं पर पानी का नामो-निशान नहीं है ।

अधिकारियों की बात मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगा । सूखा बाढ़ के राहत कार्य के लिए जो भी आप देते हैं और जितना भी आप देते हैं, उसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है । खुद प्रधान मंत्री जी ने सूखे की स्थिति को देखने के लिए अपने दौरे में स्वयं अनुभव किया था । यह परिस्थिति हम लोग देखते हैं ।

इस समय आप किसी भी बाढ़ क्षेत्र में चले जाएं । वहां बाढ़ से घिरे हुए लोगों की दुर-व्यवस्था को आप देख सकते हैं । वहां किसान को ठीक ढंग से दियासलाई नहीं मिल पाती, नमक नहीं मिल पाता । वहां पर अफसरशाही का बोलबाला है । जब कभी बाढ़ आती है तो केन्द्रीय सरकार की ओर से हवाई सर्वेक्षण किया जाता है । एक दल यहां से हेलीकोप्टर से सर्वेक्षण करने के लिए गया था लेकिन वहां हैलीकोप्टर के उतरने के लिए जगह नहीं थी इसलिए वह दल वापस चला आया । मैं नहीं समझता कि क्या सर्वेक्षण हैलीकोप्टर से ही हो सकता है, जीप में नहीं हो सकता है ? क्या वहां लोग सड़क द्वारा जीप से नहीं पहुंच सकते हैं और वहां की स्थिति का सर्वेक्षण कर सकते हैं ? हमारे अधिकारी लोग इन राहत कार्यों को ठीक तरह से नहीं करते । सिंचाई की असुविधा वहां है । खाद्य और दवाइयां जो लोगों को दी जाती हैं, उनकी स्थिति भी हमारे यहां बहुत खराब है । मैं चाहूंगा कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और इसमें किसी भी किस्म की कोई ढिलाई न बरती जाए ।

मान्यवर, नेपाल सरकार के सहयोग से जो हमारा बांध बन रहा था और पहाड़ों पर वह बांध बनना था । वह अभी तक कम्पलीट नहीं हुआ । अभी जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना चल रही है उसमें करोड़ों रुपया इस योजना के अन्तर्गत रखा है । इन रुपयों से कोई विशेष लाभ नहीं होगा इस छठी योजना में भू-संरक्षण, वनरोपण और समुद्री कटाव को रोकने के बारे में विशेष ध्यान देना चाहिए ।

छठी योजना में आपने बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं के लिये प्रावधान रखा है ।

आपने 8,448 करोड़ 36 लाख रुपये का प्रावधान बड़ी और मझौली सिंचाई योजनाओं के लिये किया और 1,810 करोड़ 30 लाख रुपये का प्रावधान छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये किया है। बाढ़ नियंत्रण के लिये आपने 1,045 करोड़ 10 लाख रुपये निर्धारित किये हैं। मैं समझता हू कि यह राशि पर्याप्त है ओर इससे पहले भी जितनी राशियां आपने खर्च की हैं वे भी काफी राशियां थीं। लेकिन जितनी भी राशियाँ खर्च की गई हैं उनका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं हुआ है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे।

मंत्री जी को इस बारे में बहुत तजुर्वा है। आप कभी कभी हाउस में ऐसी बात करते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि निश्चय ही आपको तजुर्वा है। लेकिन हम चार वर्षों में देख रहे हैं कि आपके तजुर्वे का कोई विशेष लाभ हमारे देश को नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि इस समस्या को मंत्री जी स्थायी तौर से हल करने की कोशिश करें। जब बाढ़ आती है या सूखा पड़ता है तभी ये तैयार होते हैं। इसके लिये हमारे जो आयोग बने हुए हैं और जो स्कीमें हैं, इन सब स्कीमों में आप जान डाल दीजिए और इनसे पूर्ण रूप से लाभ उठाने के लिए अपने को तैयार कीजिए।

MR. DEPUTY SPEAKER : Motion moved :

> "That this House do take note of the situation arising out of the annual floods and drought in various parts of the country resulting in heavy loss of life. property and crops seriously affecting the economy of the country and the imperative need for the implementation of the short-term and long-term measures to meet the situation."

PROF. MAHU DANDAVATE : Sir, I beg to move :

That in the motion,—

add at the *end*

> "and demands that adequate Central assistance be given to the concerned States to meet the grave situation created by floods and drought." (I)

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Sri, I beg to move :

That in the motion,—

add at the *end*—

> "and urges upon Government to take the following steps immediately, namely :—
>
> (a) appoint a task force, to study and evaluate the results of the floods and drougt control programmes so far under taken by the Government during the last three decades, and recommend ways and means for the better implementation of those programmes;
>
> (b) provide adequate funds to the State Governments to enable them to provide relief and succour to the flood and drought affected people in the respective States in the shape of grants and not as advance against Plan assistance;
>
> (c) speedily arrange for the physical availability of adeqdate quantity of food grains to the States to enable them to maintain the public distributtion system in their respective States;
>
> (d) advise the State Governmens to form all party committees at different administrative levels to monitor the distribution and management of the relief works;
>
> (e) expand the NREP programmes in the affected States. (2)

SHRI ABDUL RASHID KABULI (Srinagar) : Sir, I beg to move :

That in the motion,

add at the *end*

"and recommends formation of a Committee of Members of Parliament and experts to go into the whole problem of floods and drought and recommend necessary measures like insurance of crops to safeguard the interests of the farmers and other affected people." (3)

MR. Deputy-Speaker : Hon. Members, I would again make an appeal to be as brief as possible, so that this discussion may be lively and enthusiastic; everybody should participate, not only a few.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI (Bhubaneswar) : It is good that during this session the House has admitted this resolution for discussion because there are also recently floods in many places and naturally the House is concerned about it. We are happy that the resolution has come up for discussion.

To say that the Central Government has not done anything to reduce the severity of these natural calamities—floods and droughts in this country is to speak something untrue and completely untrue because if you look at the magnitude of this problem and the recurrence of this problem from year to year and the anxieties and the efforts the Central Government have made in this direction with show that the Central Government has given the highest priority to these natural calamities like control of floods, and drought which visit the country every year in one part or the other.

If you just have a little glance, the country suffered damages worth over Rs. 1410 crores during 1982-83 due to floods and cyclones in various parts of the country. The drought losss is not included in this. If that is included it has been calculated that on an average Rs. 600-700 crores is the damage due to drought every year. So both taken together, about rupees two to three thousand crores of loss we incur by these natural calamities every year. But I am happy to know that with reference to these problems, the Central Government has tried to set up different committees in different States and at the Central level to find out ways and means as to how to control these natural calamities which occur frequently in various parts of the country. They have calculated that from 1953 to 1981 on an average the annual loss is Rs. 365 crores.

Here if you look to the figures of help that the Central Government is giving, a sum of Rs. 495.47 crores have been spent so far from 1978-79 to 1981-82 on flood control measures have been adopted in various States. But here one thing which I would like to bring to the notice of the House is that though the Central Government is spending as lavishly as possible with all the constraints on their resources but the control measures are not directly implemented by the Central Government. It is all implemented by the respective State Governments. Sometimes I have said in this House that pumping of money by the Central Government has created a kind of an atmosphere in the States where if you go and speak to the people in the State, you will find that whatever money is going from the Centre to the States, that money is not being properly spent. Even the Comptroller & Auditor General in his report has said that whatever money the Central Government is giving to the States so that these natural calamities should be reduced is not properly spent and the Central Government has no control over these spendings and the schemes are not fully implemented. I do not wheather our Irrigation Minister or the Agriculture Minister can throw some light on this because they have also got this experience.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Arm him with all powers.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Therefore, I am confining to my State because you have told me about the limitation of time.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You have actually to come to your State.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : I can quote a few instances. Take the case of Orissa. I am not going back to still earlier period because for the last one century or so Orissa was ravaged by drought, cyclone and floods alternatively. In 1978-79, in Orissa there was a drought and cyclone ; there was tornado in 1979-80 ; in 1980-81 there floods and in 1981-82 there was drought—first there was cyclone and then there was flood ; in 1982-83 again there was drought and then flood. Thus, you will find that every year, Orissa was faced with either drought or cyclone or floods.

You will find that from 1963-76, in Orissa, damage was done due to floods. On an average, the loss to crops annually came to about Rs. 13.75 crores. From 1977 onwards, you will find that the loss went up to Rs. 19.21 crores but in 1978 it was Rs. 48.88 crores and in 1979 it came down. In 1980 there were lots of floods and drought and hence the loss was Rs. 117.15 crores. In 1980-81 it was Rs. 60.32 crores. In the last four or five years, the loss was more than Rs. 300 crores in Orissa. Sir, this is a poor state. Look at the poor state of economy of Orissa and the living conditions of the people there. But, I am happy to note that the Central assistance sanctioned to Orissa during all these difficult year was as follows :

1980-81 Rs. 42.89 crores due to floods.
1982-83 Rs. 170.51 crores due to drought.

In 1982-83 it was the worst drought. Money that has been spent so far on flood control in Orissa is concerned, the figures are as follows :

1976-77	Rs. 1 crore.
1977-78	,, 1.31 ,,
1978-79	,, 1.98 ,,
1979-80	,, 3 ,,
1980-81	,, 3 ,,

You can understand the situation. The Central Government is trying to come to the rescue of the variour State Governments. The Central Government has tried to help them as much as possible the State Governments to mitigate the difficulties and sufferings of the people. (*Interruptions*)

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore) : What about West Bengal ?

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : It is your duty to see whether the money has reached the people and it is my duty to see whether the money given to us has reached our people.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The point here is this. How the money travels we do not know.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Now, Sir, I shall give one or two examples. I would draw your attention to the reports. There was for example one report given by the Cyclone Distress Committee. That Committee was appointed with a view to giving accommodation to the people affected by cyclone in the coastal area of Orissa. I would like to know from the hon. Minister what steps have been taken so far to implement those recommendations of that Committee appointed in the year 1971. Again there was a Coommittee to examine the development of Chilka lake in Orissa. As you know Orissa is one of the flood hit states. In India floodprone states are in the Ganga basis, Brahmaputra valley and the coastal areas of Orissa. These are identified by the various expert committees appointed by the Government of India. As the three river basins cause immense menace to the people of the respective States, I would like to know from the Hon. Minister, when this Committee was appointed to see the Chilka Lake innovation takes place so that during the floods the water of all the rivers falling into the Chilka Lake, properly discharged into the lake. The present position is that the mouth of the lake is silted and the water is not discharged there. So, the areas in the coastal villages are completely submerged. So, I would like to know from the Hon. Minister what steps he has taken on the recommendations submitted by the Committee which was appointed to examine the programme for the development of the Chilka Lake in Orissa to control the floods ?

Another major difficulty for Orissa in regard to the floods is the Subarnarekha, which is also a great problem for the people of West Bengal. For that a Committee was appointed and it was decided that there must be a storage dam in Bihar. Only then the floods in Orissa and on the West Bengal side will be controlled. So far the storage

dam has not been completed. The Committee was appointed in August 1972. The Central Government also has allotted sufficient funds for that. Yet the progress has been very slow during these eight years.

There was another Committee appointed to see that the entire coastal belt should be planted so that whenever any tidal wave comes, it will act as a barrier and that the coastal areas will not be inundated because of the tidal waves that come.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : Kasurina plantation is needed there.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Yes, that the was the proposal. Though in many coastal areas it was suggested, yet it has not been done there. So, I will request the Hon. Minister to look into this and see that it is completed.

So far as the drought is concerned, Orissa has suffered the worst during 1982. The Central Government helped with about Rs. 200 crores to meet the difficulties caused. But I don't know whatever programmes they have undertaken, whether they have been properly monitored to see that the money that the Central Government gave, has been properly utilised to save the people of Orissa from the chronic drought and that these droughts do not occur again and again in the some area.

So far as the Drought-prone districts are concerned, the Central Government has selected 54 districts which are drought prone. But how is it that in spite of Central assistance to the drought prone areas, the position does not improve frome year to year in those very districts. And your reports from time to time show that these very same districts also suffered from droughts.

So far as the sanction of the money from the Central Government is concerned, you will find that in 1982-83 the total ceiling of expenditure sanctioned for the Drought Relief Work was Rs. 436.26 crores for all the States which suffered from drought. In 1983-84 Rs. 267.78 crores were sanctioned. The total comes to Rs. 704.04 crores. In 1981-82 it was Rs. 159.91 crores- You will find the ceiling of expenditure for drought relief work comes to about Rs. 900 crores in 1981-82, 1982-83, 1983-84 and the margin money also which the Fifth Finance Commission had set was only Rs. 1 crore or Rs. 2 crore for a State, but the margin money in the Seventh Finance Commission has been increased to more than Rs. 8 crores. I hope my figure is correct. It has been increased to Rs. 8 crores. We have said : why not increase it to 50 crores. We have given that suggestion, so that we can go ahead with our work of rehabilitation and relief when the drought comes.

The Comptroller and Auditor General has observed in his last year's report :

> "In U.P., Orissa and Madhya Pradesh, at least 86 irrigation projects taken up during the 5th Plan period were found in a state of virtual abandonment. In the case of as many as 19 irrigation projects scattered over six drought-prone States, constructions were later revealed to be faulty and sub-standard, according to official reports. In eight States, 15 projects were abandoned after spending Rs. 2 85 crores. In nine States, during the past 12 years, Rs. 13.05 crore found to be diverted to unapproved schemes and works."

I think that this kind of thing has to be looked into.

Once I said, and to-day I repeat this ; May be the Central Government, by releasing as much funds as possible to see that the States are put on a right footing, is unwrittengly adding a little to the generation of black money. From its own funds, black money is being created. I have suggested that when we are appointing Finance Commissions, we shall have to appoint a commission to oversee these huge expenditures from year to year.

Some Opposition friends asked why I had suggested it. I suggest there should be a Commisson on Expenditure, so that in respect of all the money that the Central Government is spending, we can see whether every pie is spent properly. I don't say that the Commission for expenditure should control but it can be monitored to see whether every pie given to the States, is spent for the purpose for which it is given.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Figures in respect of both grants and loans should be given.

SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Even before the Eighth Finance Commission, the States have said : "Give more of grants, and less of loans." But there should be a Commission of expenditure which will look into this.

So far as Orissa's problems are concerned, we have the problems of flood, cyclone and drought. The problems are very serious They should supply more food-shafts to Orissa as the price of rice is rising to more then 4 rupees a kilo. I appeal to the Central Government and the Ministers of Agriculture and Irrigation to give utmost priority to our problems. They should also help us to complete the Rengali dam. On Mahanadi, we need another dam below Hirakud. For this, a proposal has been sent to the Irrigation Ministry. I hope these requests from Orissa will be taken into consideration.

SHRI E. BALANANDAN (Mukundapuram) : The hon. Members who spoke before me have covered many areas. I am not going to repeat them. This kind of a discussion on flood and drought is taking place year after year.

On 1st August, the Minister of Agriculture said in Rajya Sabha in a reply to a question that due to floods, we have lost 717 lives ; 1.75 lakh houses were damaged and one lakh heads of cattle were lost.

2.80 lakh hectares of crops are affected by floods. This is the figures given by the hon. Minister in Rajya Sabha on First August. The most affected State this time due to floods and cyclones was the Gujarat State, four districts of the Gujarat State including Junagarh. Nearly 600 people died. Two million people were affected by floods ; and the loss of property and crop, etc. is not calculated. This time, the Brahmaputra, as usual, has crossed the danger level. Up and other States were affected very much. Year after year, we are facing such a situation. The Government of India has so many plans to control floods. If you go through the figures you will find that the loss occuring year after year is more than the money spent on agriculture and other connected purposes. For example, if you go through the figures regarding construction of houses, you will find that 15 lakh houses are lost annually by floods. In the 6th Five Year Plan, housing construction is estimated to be at 14 lakh houses, and the loss of houses due to floods is 15 lakh annually. Therefore, you can calculate the effect of it. During the last three years of the plan, according to official figures, the loss due to floods estimated to be Rs. 3,981 crores, which is more than the estimated expenditure on agriaulture and allied purposes.

We are discussing this subject to find out long-term and short-term measures for this kind of repetition of floods and drought. Therefore, I appeal through you to the Minister and the government to do something about it. I don't say that the government was not doing anything ; you were doing something about if, but we are not able to solve the problem of floods which is occurring every year. Every year, we are facing a serious situation. Therefore, the Government of India should meet this situation on a war footing. Can the government meet this situation by some allocation of funds alone ? Huge money is required for it. The people of the whole country should be taken into confidence. This is a national calamity and the whole nation should be made conscious about it. The people of this country should be told that this is the situation which can be met by some kind of scientific methods. I do not want to invite these quacks. Now the scientists are coming with so many remedies. I do not want to comment on this. We are having so many committees, flood control committees and commissions. I do not blame them. They were making so many suggestions. But what is lacking ? The seriousness has not gone into the mind of the Government. The Agriculture Minister is an efficient man. He is also a man who knows what he is dealing with. Also he can, at times if he feels, deliver the goods. At the same time, the problem is not very easy. It is very serious. But are we tackling this problem with that seriousness ? No, Sir. Therefore, we have to think over it seriously. The suggestion of flood control system has to be taken very seriously by the Government with the help of those people who are very much concerned with it.

17.00 Hrs.

If we go through the devastation in many States like Bihar, Rajasthan, UP, Cooch

Bihar, in West Bengal, Tripura and many other States, we find that so many human lives have been lost there besides loss of cattle, property, crop and other things. Long term measures, I have already told you. The short term measures have also to be taken. For example, West Bengal was approaching the Government of India for assistance. They have given something. My predecessor, Mr. Chintamani Panigrahi, was saying that the Central Government was benevolent and that they were giving whatever assistance was wanted. That is the position with regard to Orissa. But with regard to West Bengal, the Government of West Bengal requested for an assistance of Rs. 205.58 crores- You have given in two instalments merely Rs. 77 crores. To be frank and precise, due to current drought the situation, consequent to the failure of early monsoon, in unprecendented in the State. Nearly the entire rural population of more than 400 lakhs have been affected by the drought. You will say that you have sent teams and after assessing the situation you have given the assistance. You know that every State is burdened with overdraft. This is a common disease. The Finance Minister was keen to discipline all the States irrespective of Congress ruled or others. The finances of the State Governments are such that they may not be able to meet this kind of a situation. Therefore, the Central Government has to bear the brunt of the situation and they should come forward to help the States. Especially, you know, the West Bengal finances are very weak Because the situations developed beyond their control : they cannot do anything. Therefore, this point should be noted by the hon. Minister. As I said, when he want, to do he can do. So, he should do this time also to see that West Bengal is saved from the situation.

When we talk of measures, we say long-term as well as short-term measures. What are the short term measures ? Short-term measures include financial assistance. That is one point. Another big thing of food. Where is the Food Minister ? I do not know whether somebody is here to represent the Food Ministry...(*Interruptions.*)

AN HON. MEMBER : He is here.

SHRI E. BALANANDAN : If he is here, I am very glad. Then the food is there. Now, the point is that in West Bengal not only floods but droughts also come. Drought means the total crop is lost. They have to maintain certain public distribution system for which they must keep something to provide for the people to eat. Since the crop is lost, there is no grain at their disposal. So, the Central Government should come to the rescue and send more grain for the time being as a short-term measure. Now, what is the situation in West Bengal ? The situation in West Bengal is that for the maintenance of public distribution system they require 3,75,000 metric tonnes of foodgrains per month. The Government of India is supplying 2.25 lakh metric tonnes including the requirement of the roller flour mills. Perhaps at one time they could manage with this but now they cannot manage because of the drought. There is no crop, therefore, there is no production of foodgrains. The situation is not as it was earlier, So, the Government of India should make up their mind to see that at least this 3,75,000 metric tonnes foodgrains per month reach West Bengal through FCI godowns. All the bottlenecks should be removed and monthly supply should be maintained. These are the short-term measures with regard to West Bengal.

Then, I come to North. There is a State called Tripura. It is a small State. They are not capable of thinking about this kind of big money and they are not asking for it. Floods have come there, road communications have been disrupted. The Chief Minister has sent a telegram and I have a copy of that telegram with me. He has already spent Rs. 40 lakhs from whatever he had and he is now making a request to the Government of India to send a team to Tripura to assess the extent of loss. He has also requested that this amout of Rs. 40 lakhs which he has spent may be immediately given back and also 5,00 tonnes of rice should be sent to that State...(*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Because he has spent his own money according to you.

SHRI E. BALANANDAN : Because he has to exist there. Flood comes, washes away the whole thing, communication is lost, but nothing can be done. If he has to exist in the Government, he has to immediately spend something and ask for the aid. So,

the question of Tripura State is a question which he has to consider very seriously according to me.

Then I come to my own State Kerala... (*Interruptions.*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : You should have started from Kerala State.

SHRI E. BALANANDAN : No, Sir. I am coming to Kerala State last. The Kerala State is a State which has its own peculiar problems (*Interruptions*)

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : You say you want to end in Kerala.

SHRI E. BALANANDAN : The point here is, what is the agricultural pattern in Kerala ? We are having all perennial crops. Kalpakam, that is, coconut is the major agricultural produce in Kerala State. If one coconut tree is lost, then he has to plant it again and wait for five years to get another crop...(*Interruptions.*) Sushaila Ji is an expert because she holds certain lands and coconut trees. As she said five to seven years we have to wait. That is the story of coconut. Then I come to cardamom. Cardamom is a hilly crop. It earns you lot of foreign exchange. The whole cardamom crop is lost. Two things happened simultaneously. 35,000 workers who were employed in caradamom estates have no work and the total crop is lost. I do not want to give the figures of other things like pepper, etc. We have coconut, arecanut and similar crops. So, the situation in Kerala has to be viewed differently from that in other States because our agricultural pattern is different. In the history of Kerala, we have never experienced a drought of this kind.

[SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI *in the Chair*]

Another fact is that Kerala is a State which is industrially backward. For some time it was boasting of surplus electricity. But now the position is that there is no generation of electricity. The generation of electricity in our State is entirely based on hydel power. Since the rain God has failed us, if it is a God, or if somebody can be called a God...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA) : You do not believe in God.

AN HON. MEMBER : They believe in a ghost.

PROF. MADHU DANDAVATE : Their God is nationalised.

SHRI E. BALANANDAN : Well, I do not want to go into that.

Well, there was no rain, no water and the storage reservoirs became empty. The generation of electricity came to a standstill .. (*Interruptions*) The industry also came to a standstill. Therefore, the financial position of the State became precarious. That is why I say that the normal approach to an ordinary situation is not sufficient in the case of Kerala. It requires an extraordinary approach. Arguments and disputes between the opposition parties and the ruling party is the order of the day in Kerala. But, so far as the question of drought is concerned, the Kerala Assembly passed a unanimous resolution and sent it to the Government of India.

As you have yourself stated in reply to a question in this House, the Government of Kerala have requested for an assistance of Rs. 220.60 crores. There is some discrepancy in figures between your two answers, but I do not want to go into it. In response to that request of Kerala, you have given Rs. 36.77 crores as Plan assistance, which will be adjusted against the Plan schemes during the next five years. So, the point is about Rs. 36.77 crores to be adjusted in five years in the Plan. Sir, I am very sorry to say this. The Plan is a Plan for the development of the State and you are not respecting it and you are not helping us. This kind of help is rather painful. I do not want to ask anything. But it is painful that nothing is being given to us. Sir, you are asking about Orissa, you are getting something. but we, Kerala people, are not given anything. You are telling us 'All right, there is an allocation in the Plan, you take Rs. 5 or Rs. 10 from there'. That also is because of the actual contingency that arose on account of the drought. The Government has no say in it because the Plan allocation is made on

certain projects and on that basis only expenditure can be made – money has to be spent on that head alone. Because of drought so many other situations have arisen for which nothing can be done. (*Interruptions*). I am only saying that this attitude should change and the request of the Kerala Government is to be conceded. I know the Kerala Minister has come and met you yesterday, I hope you might have agreed to give something.

PROF. MADHU DANDAVATE : He gave him his good wishes !

SHRI E. BALANANDAN : Therefore, I am urging that the Kerala Government's request for Rs. 220 crores has to be acceded to and the amount has to be sanctioned by you. That is one part.

Another part is a serious one. What is that ? In the whole of the country, Kerala State is a State which has a statutory rationing system. That has to be encouraged by you, and I told you that because of the drought, what little crop of paddy which we produce is also not there. (*Interruptions*) Therefore, I want that the Minister should look into it, and I appeal to him, through you, that 1,35,000 tonnes of guaranteed supply of foodgrains should be made. I am not going to request for 2 lakh tonnes. I only request you that at least 1,35,000 tonnes of guaranteed supply should be made to Kerala State.

Finally, I am coming to the question of controlling the floods. About flood and drought situation, so many committees were constituted. I agree with you on the steps that are being taken in this regard, but I request the government of India to take the problem more seriously. Today I can quote the expenditure proposed in the Plan for this.

MR. CHAIRMAN : Please conclude.

SHRI E. BALANANDAN : I am concluding.

But you will find that the amount has not been spent properly. You will find that in Bihar some bund has been constructed to control the floods. The Chief Engineer has gone there three days before and has been satisfied that the bund has been constructed, and the third day the floods come and the bund is washed away. This sort of flood control has been done by the government. Therefore, this kind of action should be stopped. It should be taken as a serious problem, for which all the national energies should be mobilised.

I once again appeal to the Government that the specific request which I made should be seriously considered by the Government.

SHRI S.B. SIDNAL (Belgaum) : Mr. Chairman, everybody knows about flood conditions and drought conditions in this country since this country is wedded to the vagaries of monsoons. When the monsoon is present, it is a flood and, when the monsoon is absent, it is a drought. Both these things happen regularly.

The side-effects of flood are more acute than in the case of drought. With the presence of vigorous monsoon, there is a heavy loss of human lives crop and property. There is soil erosion and health hazard. There are so many side-effects due to flood. The question is as to whether we can control floods, cyclones and other natural calamities. In my opinion, these can be controlled. For example already in the case of Yamuna, it has been done by constructing channels. This has proved successful in protecting the flood affected areas. Once the flood affects certain areas for 5 to 6 years, the peasants cannot recover from the side-effects in spite of the grant or help or loan given by the Central Government. Unless a permanent master plan is drawn up, unless there is a permanent official machinery consisting of experts, engineers or scientists, all that will not help. The teams are appointed and the reports are given regularly. But the implementation is very difficult.

Specially in the case of floods, it is all accidental. The flood might come overnight. A ready-made thing cannot be applied. Military is summoned; some helicopters are summoned ; some boats are summoned. But in the process we cannot help much in rescuing human lives and loss of property. What is the permanent solution ? It has been said by the opposition parties that the Government is

not doing anything at all. I do not agree with them. The Government is doing everything in all its sincerity right from the beginning. But my appeal to the Government is to make a master plan for 5 or 10 or 15 or even 20 years allocating the funds regularly for doing constructive work, pucca work, right from A to Z.

Take for example the Yamuna river. The authorities have controlled the floods and they have been successful in that. It is on record. They have done it by constructing channels. Like that, there are many spots in the case of all the rivers which the people in the local areas know. We can have channels or some other projects or whatever measures we can take as long-term measures.

Also, in my opinion, along with the river belts, the afforestation can be done whereby we can check soil erosion and also the submerging of the villages. My hon. friend, Mr. Balanandan said that 15 lakhs or 20 lakhs houses are lost. It is not the loss of houses alone. Apart from that, many belongings of the peasants and other moveable property are totally lost which cannot be assessed or estimated. For that, my suggestion will be that there should be a special Department with this separate portfolio working for it regularly.

When the floods come in Karnataka or Assam or U.P, the Central assistance is sought on the basis of the reports of the State Government. During this period, the short-term help is not given. Take for example my district of Belgaum when it was affected by the flood on 30th June last. There was rain continuosuly for 72 hours affecting 25 villages in my district and 10 villages in my constituency. These were very heavily affected. So many islands were formed. The food supply and so many other things were not immediately done by the State Government. The State Government officials came as sight-seeing people. How could the D.C. help poor peasants. Other officials also came and saw the things but they could not help them. So, some short-term measures have also to be undertaken to help the drought-affected people.

So, in my opinion, in all such contingencies anticipating all such things, when the rain goes beyond 40 hours or 30 hours or 10 hours more than the proportion of the rain that a particular area received it should be noted by the Government and a permanent machinery should be set up for controlling floods or cyclones or other natural calamities. If you do not have that plan, I think there is no use spending crores of rupees. We are only flooding money to the floods and the money reaches the States very late and it is inadequate, Sometimes it is out of proportion. Sometimes, no proper assessment is made. For example, in my Constituency, according to the assessment of the State Government, 3,600 houses were affected by floods. But in fact more houses were affected. Even though 3,600 houses be collapsed due to floods during the floods, there were another 3,000 houses about to collapse after the floods as the water went 7-15' into the houses and half the wall is full of water and the other half is right. The homogeirity is not maintained with the result that cracks develop in the walls. Nobody would be prepared to dwell in a falling house. So, people lost their houses due to floods. The State Government would be unable to work properly and sincerely on the spot because of the inadequate help it gets from the Central Government. Floods cause huge loss of animals, fodder and implements. This cannot be understood by some of the officers who are puite ignorant of the needs of agriculture and industry. For instance, there are small-scale industries and leather tanning industry in my area which were affected by the flood. The State Government estimated the loss in the leather tanning industry at Rs. 2,000/-. So much of the chemical used for the tanning of the leather was lost. Therefore, I enquired into the matter. The loss sustained was really to the tune of Rs. 6-10, 000/-. The poor in these or professions are affected. They have no influence. The money that the Central Government gives to the State Government is not properly utilised by the State Government. Therefore, my request to the Hon, Minister through you it that a special machinery has to be established to meet the needs of the flood-affected areas. Otherwise, it will be a waste of time and money.

As regards drought, 64 districts are regularly affected by the drought and there are chronically drought-stricken areas, Therefore, we had to plan a special crop or afforestation of fruit-bearing trees or whatever it my be because of the absence of the regular agricultural crops. The special programme has to be drawn and special fund has to be allocated. Mere sanction of money without a concerted effort to implement a planned programme wlil not be of much help. It will be a waste. It will not be of permanent help to the victimes. Let us do bit by bit but not in a haphazard manner. I do not blame the Central Government that it is not helping. It is helping. But the State Governments which are said to be agencies to utilise the funds are not properly spending the money. There is lot of waste and delay. For drought, the Central Government deputes its machinery to assess the situation. The staff of the State Government will take 15 days to report. And then again the Central Government staff will come and survey whether this area is really affected or not. And then direct report will come. Then money will come. By this time, the rains will again come and the whole thing is over in many areas. Therefore, the spot study must at the most take only 8-15 days and not more than that. That is why I am insisting on the Government to have a special group of officials or a special Department which can attend to the work of making on-the-spot study without depending on any agency, and the money from the Central Government to the State Government either for floods or for drought should not be delayed. Of it is delayed, neither short-term measures nor long-term measures are of any help to the people. That is the need of the hour. If we do not actually give the money in time, it will be a waste. Therefore, my request to the Government of india is to help permanently and make a master plan by inviting some engineers, scientists or any of that sort that is required to help permanently and solve the natural calamities problem, thereby helping this country. Many of our plans in the past had been failures because of the delay in sanctioning money and this its transfer from one Department to the other. Because of this failure, all our achievements have been lost. Also agriculture is heavily affected. If floods occur continuously, no crop can be grown after some years. Keeping that in view, we have to start ; we are already late. I do not know, there may be some plan or something with the Government, but that is not helping really.

Lastly, I would say that my own district has been affected last June ; about 25 villages have been affected. The State Government has given about Rs. 500 or so, something which is not helping, Also some small industries, which were close to the river, were affected and have been closed down. They have not helped those people. I think they have come to the Central Government for help. I request the hon. Minister and the Central Government to help our State. Of course, Janata Party is ruling there. But we have to rise above Party because it is a national problem and it is an acute problem.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur) : Mr. Chairman, Sir, though the canvas of the subject-matter for discussion is quite wide covering floods as well as drought, I will deliberately impose a restriction on myself because of want of time and would like to concentrate only on the problem of floods. Though there are floods in different parts of the country, since I represent in this House the backward region, the coastal region, of Konkan of Maharashtra, I would like to draw the attention of this House to the unprecedented floods in the Konkan region of Maharashtra, and then we can generalise the problem : whatever is applicable in the case of the Konkan region will also be applicable to Assam, west Bengal, Gujarat and other parts of the country ; whatever suggestions I may put forward in this House will be applicable to others also.

As far as the damage done due to floods in different parts of the country is concerned, Government itself has admitted certain figures, and that will bring home the grave nature of the calamity that has befallen this country. For instance, due to floods and land-slides alone, the total damage that has been admitted by the Government is like this : deaths in floods and land-slides 730 ; damage to crops 2.08 lakh hectares ; houses that there damaged

1,84,849 ; and the cattle lost 94,887. These are the figures that have been given by the Minister himself and that will show the dimension of the problem that is to be handled.

As far as the west coast region of Konkan is concerned, you will find that all these losses have already been registered during the recent floods in the Konkan region. There has been loss of life, there has been loss of cattle, there has been damage to houses, The most important feature is that there is silting of rivers. Landslides, damage to agricultural crops, damage to fishermen's implements and also damage to shops and the market places—these are the various ways in which considerable damage has been done.

There is also one controversial point on which we will seek Central assistance. It is not merely financial assistance ; it is assistance in the form of advice and guidance by a team of geologists. It has already visited the Konkan region ; I believe it is still there. In the Konkan region there are certain parts like Sangameshwar and Chiplun, beautiful places ; one should visit those places. And you should also try to find out what has happened after the floods and what has happened after the landslides. There is a fear in the minds of the people residing there that it is not merely the damage done due to the floods alone ; they have a lurking suspicion that probably certain tremors created earthquake and they have also added to the damage done by the floods. As a result of that, there have been great landslides there. Some of the local experts from Maharashtra said, 'We find the fact that there were no tremors at all.', whereas the residents told the Ministers and other teams that have visited the area that there mild tremors and as a result of that, there were landslides. I may bring to the notice of this House that at Koyna Nagar there is already a seismograph that has been fixed up and the range of the seismograph is so wide that even upto Sangameswar and Chiplun in the Konkan region if there are tremors and earthquakes, those shocks could be registered on the seismograph. I would like the Government to find out from the Central team of geologists sent to the Konkan region to find out whether in the seismograph that has been located at Koyna Nagar, some mild tremors in the Konkan region were already recorded. I know, as a student of Physics, that seismograph cannot predict tremors but it can always register the tremors that have occurred and have taken place. Therefore, after the event has already taken place and since the seismograph at Koyna Nagar must have already recorded the seismic disturbances, probably the team of geologists that is going there can also proceed to Koyna Nagar and find out in depth whether there were any tremors and as a result of that, whether there were any landslides.

It is an accepted fact that once tremors occur in a particular region, once an earthquake takes place in a particular region, that region perpetually remains vulnerable for new tremors. Therefore, certain precautionary measures have to be taken and if the geologists' team which has gone from the Centre to this Konkan region establishes that tremors have occurred, in that case certain precautionary measures have to be taken. That is why I am bringing this particular aspect to the notice of the Government.

As far as the landslide is concerned, particularly, in the Konkan region, we find along with the damage done by the devastating floods there have been tremendous landslides that have occurred and as a result of that, the traffic has been completely dislocated for a long time. There are certain reasons due to which these landslides have taken place. Many experts have admitted the fact that in the Konkan region there is a wide tendency on the part of the residents and particularly, the contractors who want to sell fuel, to indiscriminately cut the trees. Jungle-cutting is going is going on a very large scale. As a result of that there is the greatest soil erosion and as a result of the soil erosion there has been a greater degree of landslides and added to the landslides these floods that have taken place have caused a tremendous damage.

Therefore, I would like the hon Minister to send central guidelines to all the States including the State of Maharashtra that under no circumstances they should allow the

cutting of trees. In fact, deterrent steps will have to be taken. Very stern measures will have to be taken against those indulging in cutting of the trees. As a result landslides, resulting out of erosion of soil can also be avoided.

There is a one more important feature in the floods of the Konkan region. We find that in the Konkan region during the recent floods, a lot of silting of the rivers has taken place. The peculiarity of the Konkan region is that there is a very heavy rainfall, normally, of more than 110" per year. But this time the entire rainfall concentrated in a short period of time and as a result of that, there was an overflow of rivers. One tragedy of the Konkan region in Maharashtra is that you find that there are heavy rains and the rain water run down the mountain tops with great speed and velocity and with the same speed and velocity it goes into the sea and as a result a lot of silting in the rivers takes place and the beds of the rivers have been lifted up and as a result the normal capacity of the river to contain the flow of water has also been exceeded and you find overflow of the water everywhere and you will find on the banks of the rivers in the Konkan region there has been a devastating destruction. Therefore, that has to be avoided. In that case, drudging of the river has to take place. When this question was raised on the floor of the Maharashtra Assembly, the Minister concerned said that drudging up of the river in the Konkan region was a very costly affair and it would be beyond the financial resources of the State to undertake this exercise of drudging up of rivers—the silted rivers. Therefore, I would humbly request, the hon. Minister concerned to kindly give the necessary Central assitance and to see that this particular operation of drudging up of the river which is already silted is undertaken effectively. That will be one of the methods by which it would be possible for us to see that this particular can be remedied.

Then, Sir, there is another aspect. Like Konkan region, there are so many other regions too. One advantage to some of the States' region is that they have got a network of small and big irrigation works and this is an accepted fact of hydraulics that in so far as the flow of water in the river is concerned, if there is a small network of irrigation—small or big—in that case, the river water taken to irrigation channels and, as a result of that, the pressure of water is dissipated to a very great extent. Therefore, the destructive potential of the river water is also destroyed or at least reduced to a considerable extent. That is the reason why when there are series of floods, to a large number of irrigation channels, water is diverted. Pressure is dissipated. As a result of that, destructive potential of water is reduced to a considerable extent. Devastation is also to a great extent reduced. If this work is to be undertaken, it is beyond the financial ability or capability of the Maharashtra State – Maharashtra State has the silting water problem—Central assistance should be given to them. There is one more aspect. I would briefly note down the points. That is regarding the alternative modes of transport. This question has been highlighted by the problems of floods. When floods occur in certain backward regions where modes of transport are very meagre and where only one mode of transport like motor transport is available, in that case, once that very route is destroyed and if railways are not available,and other routes are also completely blocked, there is dislocation of traffic that takes place. I would like to draw your attention a very important Committee was appointed during the Janata Government period. It was known as the National Transport Committee. Suggestions were made from both sides of the House and, as a result of a unanimous recommendation of this House, that Committee was appointed. That Committee has given a very important finding and an inference. Their inference was that from the point of view of defence as well as the safety requirements and in times of calamities like floods, it is very necessary that various modes of transport should not be treated as alternatives to each other but they should be treated as complement to each other. For instance, we must not say that since in the Konkon region we have adequate mode of transport we must not have rail transport or if we have rail transport, motor transport need not be introduced. The National Transport Committee has recommended that these two modes of transport should be treated as complement to each and they should not be treated as an alternative to each other. I would insist that looking to the defence needs and also to the safety require-

ments, it is better that the West Coast Konkan railway is linked as it will be beneficial not only to Maharashtra State but also to Kerala, Karnataka and Tamilnadu. It will provide a link route from Maharashtra upto the tip of Cape Comorin.

Sir I had the proud privilege to see that. The route from Trivandrum to Kanya Kumari has been connected. If a rail link is made from Bombay to Trivandrum, in that case there will be a rail link from Mangalore. From Bombay to Kanya Kumari the link will be connected. The problem of the Konkan region will be solved thereby.

(*Interruptions*)

I have one small point. I hope that if this proposal is accepted by Government coming from the Deputy Leader of the Congress Party I will support it. One more point I would like to make, In the states like Bengal, Kerala and Konkan, there are small rivulets across which there are foot bridges. In the recent floods almost all these wood bridges which are built up with the help of palm trees and the wooden planks, they have been completely washed out in the case of Konkan region and West Bengal and Kerala. Therefore, I make a very constructive proposal which, with my some association with the Indian Railways, I may bring to your light that about four to five thousand kilometres of Railways, when those routes became unfit for travel on the broad-gauge, were removed. Such rails are lying idle. They are ultimately completely melted down. I suggest that these railway lines, which have been removed because they are unfit for heavy traffic, they can be cut into pieces, and in such regions like Bengal, Kerala and Konkan region of Maharashtra which have small wood bridges, instead of the palm trees, if small pieces of rails are made available to them, the discarded rails and the planks of wood, I think it will provide the most suitable type of bridges and this should be done.

PROF. N.G. RANGA (Guntur) : You have forgotten Andhra Pradesh.

PROF. MADHU DANDAVATE : In fact, I must begin with Andhra Pradesh, because alphabetically Andhra Pradesh comes the first, Sir. Now, let me conclude with this request. On 1st August, 1983, the Minister of State for Agriculture answered to a Starred Question No. 104 Shrimati Pramila Dandavate in this very House. He said that only Karnataka, Gujarat, Himachal Pradesh and Meghalaya States have asked for the Central assistance due to floods.

MR. CHAIRMAN : You should have taken another question. Not that.

PROF. MADHU DANDAVATE : Why Sir. I think charity begins at home. Therefore, I would like to start with it. Therefore, Sir, I would like to point out to you that Maharashtra Government, in spite of such a loss, which is to the extent of Rs. 30 crores in the Konkan region, has not asked for Central Assistance, and has not sent any Report to the Central Government in this regard. When we brought it to the notice of the Prime Minister that these are the pictures of the flood, she said Maharashtra Chief Minister had not informed her. Then the report has still not come. In spite of that she wrote to me and said that from the Prime Minister's Fund, I have sent Rs. 5 lakhs. But that is not sufficient. Sir, Gujarat has been rightly given Rs. 20 crores and they desire more because Saurashtra floods have Played havoc, but nothing has been given here as far as such grants are concerned. Therefore that assistance should also be made available here. Therefore, in the light of this suggestion, I am moving the Amendment, which is the substance of my speech.

MR. CHAIRMAN : That you have already moved.

PROF. MADHU DANDAVATE : I have not. They don't know even what is the Amendment. I only know it is Amendment No. 1. They know the number. Therefore, I will read that Amendment and conclude :

> "At the end of the Motion *add* — 'and demands that adequate central assistance be given to the concerned States to meet the grave situation created by floods and drought'.

It includes Andhra. I hope Prof. Ranga will support my Amendment.

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति जी देश में सूखे और बाढ़ से 1982-83 में कुल मिला कर 31 करोड़ 27 लाख लोग प्रभावित

हुए । सूखे से 26 करोड़ 20 लाख लोग प्रभावित हुए और बाढ़ से 5 करोड़ 7 लाख लोग प्रभावित हुए । इनके लिए केन्द्रीय सरकार को काफी राशि खर्च करनी पड़ी । यह जो सूखा और बाढ़ देश में आई ऐसा सूखा औरबाढ़ देश में करीब करीब सौ वर्षों में नहीं आया । हमारे क्षेत्र में तो इस प्रकार का सूखा कभी भी नहीं पड़ा । हमारे राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में तो ऐसा सूखा शताब्दी के बाद पड़ा होगा । यह सब से बड़ा सूखा था । अखबारों में तो यह आया कि लोग भूख से मरे । लेकिन मैं कहता हूं कि लोग भूख से नहीं मरे । ऐसी स्थिति तो अवश्य हुई कि उन्हें खाना दिन में एक दफा खाने को मिला और जो खाना उन्हें मिला वह पौष्टिक भोजन नहीं था । इस प्रकार की उनकी स्थिति रही । इसका कारण । है राज्य सरकार के सीमित साधन और केन्द्र से पर्याप्त सहायता नहीं । जहां तक केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है राजस्थान सरकार ने अक्तूबर 1982 से ले कर मार्च 1983 तक के लिए पचास करोड़ की मांग की थी लेकिन उसको केवल 11 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपया ही दिया गया । इसके मुकाबले में मध्य प्रदेश की सरकार को जहां 87 लाख जनता प्रभावित हुई थी और हमारे यहां 1 करोड़ 70 लाख, 28 करोड़ की मदद दी गई । इसी प्रकार से अप्रैल से ले कर जून तक एम्प्लायमेंट जैनरेशन की मद में हमें 19.09 लाख की मदद दी गई जबकि राजस्थान को पहले सालो में 28 लाख रुपये की मदद दी जाती रही है । मजदूर को मिलता क्या है इसको भी आ देखें । केन्द्र सरकार एक मजदूर को सिर्फ पांच रुपये प्रति दिन और सामग्री के रूप में प्रतिदिन सवा रुपया नकद देती है और इस प्रकार सवा छः रुपया मिलता है जबकि एन. आर. ई. पी. मैं पंद्रह रुपये रोज दिये जाते हैं, नौ रुपये नकद और छः रुपये सामग्री के रूप में । आप एक बात और देखें । मार्च से ले कर जुलाई तक मजदूरों की संख्या ज्यादा होती है हमारे यहां क्योंकि यहां खरीफ की एक ही फसल होती है । मजदूरों को इस अवधि में हमें ज्यादा खपाना पड़ता है । यह चीज अध्ययन दल की समझ में नहीं आती है, उसके दिमाग में नहीं बैठती है और अक्तूबर से ले कर मार्च तक मजदूरों की संख्या जो निर्धारित की गई उसका हिसाब लगा कर उन्होंने अप्रैल में ढाई लाख और मई जून में साढ़े चार लाख निर्धारित करके हमारी मदद की जबकि इस अवधि में हमारे यहा सात आठ लाख मजदूर लगे । कहने का तात्पर्य यह है कि अपर्याप्त मदद दी जाती है । महीना तीस दिन का होता है लेकिन मजदूरी 26 दिन की दी जाती है । चार बीच में जो संडे आते हैं उसकी उनको मजदूरी नहीं मिलती है क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है । मिनिमम वैजिज जहां मजदूरों को मिलती है वहां उनको संडे की छुट्टी भी दी जाती है और 30 या 31 दिन की तनख्वाह भी दी जाती है लेकिन यहां 26 दिन की ही मजदूरी इनको मिलती है । चूंकि राजस्थान सरकार को केन्द्र ने पर्याप्त मदद नहीं दी इस कारण यह स्थिति पैदा हुई कि हमारे लोगों को हरियाणा, गुजरात, पंजाब आदि प्रदेशों में जा कर ठोकरें खानी पड़ी, सड़कों पर काम करना पड़ा और उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई । बांडिड लेबर की तरह उनको हरियाणा पंजाब में काम करना पड़ा और दुर्दिन देखने पड़े । जो नार्म आप फिक्स करें वे रीयलिस्टिक होने चाहियें और उनके अनुसार आपको मदद देनी चाहिये ।

अध्ययन दल क्या है ? इसने अपनी पहली रिपोर्ट जनवरी 1983 में दी है । 4, 5 साल से बराबर अकाल पड़ रहा है । सितम्बर में फसल होने के बाद मजदूर अक्तूबर में जाता है । उसे नवम्बर और दिसम्बर में कोई मजदूरी नहीं मिलती बल्कि दिसम्बर में दी जाती है । 3 महीने उसकी क्या दुर्गति होती है, उसको मजदूरी नहीं दी जाती । 15 दिसम्बर को जो कुछ मजदूरी दी गई वह बहुत कम व्यक्तियों को

दी गई। जनवरी के बाद कुछ फैमिलीज को मदद की और मार्च, अप्रैल, मई में ज्यादा मदद दी गई। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से लोगों को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है। इस तरह से भयंकर असंतोष पैदा होता है। इसीलिए केन्द्रीय सरकार कोई नार्म्स फिक्स करे।

अध्ययन दल ने 10 जनवरी 1983 को रिपोर्ट दी फिर उसके बाद मदद मिलती है। उसी प्रकार अप्रैल से जुलाई की मदद के लिये 15 जून को रिपोर्ट दी और 20 जून को आदेश जारी किया। इतना समय क्यों लेते हैं ? आप क्यों नहीं अध्ययन दल का टाइम फिक्स करते हैं ? गवर्नमेंट मशीनरी को भी ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए। और जल्द से जल्द इसका निर्णय करना चाहिये।

फैमिन को मदद एडवान्सड प्लान में से की जाती है। इससे प्लान का काम ठप्प हो जाता है और जिन क्षेत्रों में अकाल नहीं होता है, वहां के लोग इसका विरोध करते हैं कि तुम प्लान का पैसा इस तरह से क्यों खर्च करते हो ? मेरा कहना यह है कि एडवान्सड प्लान की परम्परा गलत है। फ्लड में जो मदद की जाती है उसमें 75 परसेंट आप सबसीडी देते हैं, 25 परसेंट राज्य व्यय करते हैं। परन्तु यहां आप सेंट-परसेंट लोन देते हैं। आप 7वें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट का भी कोई उपयोग नहीं करते। फैमिन में पशु मर जाते हैं, इकनामी नष्ट हो जाती है। बाद में बीमारी से मनुष्य मरते हैं। फ्लड के समय यह स्थिति तो होती है कि उसके बाद रबी की फसल अच्छी होती है, कुओं में पानी बढ़ जाता है परन्तु सूखे के समय बिल्कुल इकनामी नष्ट हो जाती है। फैमिन और फ्लड में कुछ तो पैरिटी होनी चाहिये। जिस प्रकार फ्लड के समय मदद दी जाती है उसी प्रकार फैमिन के समय भी दी जानी चाहिये।

मार्जिन मनी 10.19 करोड़ फिक्स की है छटे फाइनेन्स कमीशन ने। फिर आपने उसको रिड्यूस कर के 7.74 करोड़ कर दी। सातवें फाइनेन्स कमीशन ने देश में 50 करोड़ से उसे 100 करोड़ तक बढ़ाया परन्तु हमारे प्रान्त में 10.19 करोड़ के स्थान पर 7.74 करोड़ की मदद ही दी। इस प्रकार से हमें कम मदद दी जाती है।

हमारे राजस्थान कैनाल का कार्य चल रहा है। यह कार्य तीव्र गति से चले इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। हमारे मन्त्री महोदय ने इसके लिये पहले 40 करोड़ की मदद दी, मैं इसकी सराहना करता हूं। हमारे मन्त्री जी बड़ी दिलचस्पी से काम कर रहे हैं, युद्ध-स्तर पर काम कर रहे हैं। गदरा रोड का भी काम हो रहा है और कैनाल का भी काम चल रहा है जो कि 185 किलोमीटर है।

राजस्थान से पीने के पानी की योजना जोधपुर, बाड़मेर आदि सभी महत्वपूर्ण स्थानों के लिए बनानी चाहिए। अगर हम पीने के पानी के लिए ट्यूबवैल्ज पर निर्भर करगे, तो चालीस पचास साल तक तो यह संभव होगा, उसके बाद क्या व्यवस्था होगी ? पीने के पानी की समस्या की पर्मानेन्ट सालूशन राजस्थान कैनाल ही है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार पहाड़ी क्षेत्र के लिए 90 परसेंट ग्रान्ट और 10 परसेन्ट लोन दिया जा रहा है, उसी तरह डेजर्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम के लिए रकम को 50 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 500 करोड़ रुपए कर दिया जाए और 90 परसेंट ग्रान्ट और 10 परसेंट लोन दिया जाए, ताकि इस सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्र का विकास हो सके।

श्री रीतालाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, बाढ़ की विभीषिका प्रति-वर्ष आती है और जुलाई से सितम्बर के बीच

में बाढ़ की भयंकर आशंका और प्रलयंकर आफत जनता के सिर पर लटकती हुई मालूम होती है। बाढ़ केवल आज की ही बात नहीं है। इसका बहुत पुराना इतिहास है। ईसा से हजारों वर्ष पहले से बाढ़ आती रही है, लेकिन उसकी तीव्रता लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस वैज्ञानिक युग में लोग धरती से चन्द्र-लोक और अन्य ग्रहों की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बाढ़ के नियंत्रण के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद इस समस्या को हल नहीं कर पाए हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार 1954 से ले कर आज तक योजनाओं के अन्तर्गत 11,870 किलोमीटर बांध बनाए गए हैं, 21,370 किलोमीटर जल-मार्ग खोद दिए गए हैं, 297 नगरों की बाढ़ से रक्षा की व्यव-स्था की गई है 4700 गांवों का स्तर ऊपर उठाया गया है और 1,11,50,000 हैक्टर भूमि को संरक्षण दिया जा चुका है।

इतनी बड़ी उपलब्धि के बावजूद हम हर वर्ष देखते हैं कि बाढ़ का भयंकर खतरा उप-स्थित हो जाता है। इस बार सौराष्ट्र में 5,000 लोग लापता हो गए या मर गए और सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए। समाचारपत्रों में राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, केरल और पश्चिमी बंगाल से बाढ़ की भयंकर विभीषिका की रिपोर्ट्स आ रही हैं। प्रधान मंत्री विभिन्न राज्यों को विशेष ग्रान्ट्स दे रही हैं। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इतना खर्च करने के बाद भी बाढ़ बढ़ ही रही है। इससे लगता है कि योजनाएं ईमानदारी से नहीं चलाई जा रही हैं। उनमें बहुत अधिक घपला और भ्रष्टाचार होता है। राज्यों को जो रुपया स्वच्छंद रूप से आवंटित कर दिया जाता है, जब तक संसदीय दल के द्वारा उसके उपयोग की समीक्षा और कार्यों का स्थल-निरीक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक सच्चाई का पता नहीं चल सकता। हर साल बाढ़ आ जाती है और बाढ़ में वह रुपया भी बह जाता है। बिहार में कोसी नदी है, बूढ़ी गण्डक है, बागमती है, गंग है, कितनी ही नदियां हैं जिन पर साल व साल अरबों रुपया खर्च हो चुका है। वह रुपया भी उनकी बाढ़ में बह जाता है। मुख्य मन्त्री हर साल कह देते हैं कि बालू भर गई है, फिर से तटबन्ध बना रहे हैं। इसी तरह से हर जगह यही हालत है।

एक ब्रह्मपुत्र विकास बोर्ड बना हुआ है। वहां अरबों रुपया व्यय किया गया है लेकिन फिर भी वहां हर साल हजारों लाखों लोग डूब रहे हैं। आखिर कोई कारगर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? इसी प्रकार से दामोदर घाटी निगम बना है। उसने कुछ काम जरूर किया है जिससे कि दामोदर की विभीषिका कुछ रुक गई है बल्कि उस पानी से विद्युत उत्पादन भी प्रतिवर्ष होता है। लेकिन अन्य नदियां जो हैं, जैसे कोसी है, ब्रह्मपुत्र है, कृष्णा है, कावेरी है और सौराष्ट्र की नदियां हैं, उनके सम्बन्ध में भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पिछले साल सर्वेक्षण के लिए एक करोड़ रुपया रखा गया है।

सर्वेक्षण के लिए 90 लाख खर्च हुआ। इस साल झेलम के लिए पंजाब सरकार और सतलुज के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। 1978 से 1982 तक 16 हजार किलोमीटर का सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया। सन् 1955 से लेकर आजतक सर्वेक्षण कार्य हो रहा है आखिर इसका कब अन्त होगा? उच्चस्तरीय विचार कबतक किया जायेगा। मैं समझता हूं इस कार्य को केन्द्रीय सूची में लेकर भूमि संसोधन, भूमि संवर्धन इसका आयोजन करना पड़ेगा और सही ढंग से उसकी योजना बनानी पड़ेगी। इस काम के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी एक्सपर्ट सहायता लेकर बाढ़ नियंत्रण की व्यापक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी, आजतक ऐसा नहीं किया जायेगा तबतक आप हर राज्य को हर साल अनुदान देते रहेंगे और वह धन बाढ़ के साथ बह जायेगा। जो हमारी इरीगेशन मिनिस्ट्री

है, वह भी यह देख नहीं पाती कि किस ढंग से वह पैसा खर्च हो जाता है ।

इतिहास बताता है कि चीन की हांगहो, मिस्र की नील और दक्षिण पूर्व एशिया की सिकांग नदियों को किस प्रकार से नियंत्रित किया गया है । उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, कृष्णा, कावेरी और सौराष्ट्र की जितनी नदियां हैं उन पर अलग अलग ढंग से कार्पोरेशन वगैरह बनाकर नियन्त्रण की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए । यहां पर ससद में हम हर साल चर्चा करते हैं, दुःख प्रकट करते हैं कि बाढ़ आ गई लेकिन इसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय हो रहे हैं ?

जो बाढ़ें आती हैं उनके कई कारण हैं— तटबन्ध टूट जाते हैं, नदियां मार्ग बदल देती हैं, नदियों के मार्ग में अवरोध पैदा हो जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों का अन्धा-धुंध कटाव हो रहा है जिससे भूमि-स्खलन होता है, मोटे मोटे पत्थर नदियों के घाट में भर जाते हैं और नदियां मार्ग बदलती हैं— इन सारी बातों को रोकने के लिए सरकार ने क्या सोचा है ? कौन से सर्वेक्षण हो रहे हैं और कौन सी रिपोर्टें तैयार हो रही हैं ? इस सदन में हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

मैं इसको दो भागों में बांटता हूं, एक स्थायी क्षत्र और दूसरा अस्थायी क्षेत्र । स्थायी क्षेत्र में बड़ी-बड़ी नदियों के मार्ग विशेषकर मध्य एवं निचली भूमि तटीय भाग एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जिनमें असम घाटी के भाग, पश्चिमी बंगाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटक आदि क्षेत्र हैं । अस्थायी क्षेत्र में कम वर्षा वाले क्षेत्र, जिनमें अचानक वर्षा होने से नदियां मार्ग बदल लेती हैं, जैसे राजस्थान और दिल्ली आदि । योजनाओं पर महत्वपूर्ण तरीके से सरकार द्वारा ध्यान देने पर इन समस्याओं का निदान हो सकता है, जो कि सरकार को करना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया ।

श्री मोहन लाल पटेल (जूनागढ़) : सभापति जी, आज सदन में बाढ़ और सूखे की चर्चा हो रही है, लेकिन मैं पूरे देश की चर्चा करने वाला नहीं हूं, लेकिन गुजरात में एक महिने पहले सौराष्ट्र में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो बाढ आई है, उसकी गम्भीरता के बारे में मन्त्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं ।

18.12 Hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

वह एक छोटा एरिया दो सौ गांव का है, जहां पर कि बहुत नुकसान हुआ है । सिर्फ दो सौ गांव के एरिए का रेन-एव्रेज 510 मिली-मीटर है । मैं आपको बताना चाहता हूं कि 18 जून से 22 जून तक चार दिनों में 1300 मिलीमीटर वर्षा यानि डेढ़ साल की वर्षा इन चार दिनों में हो गई । इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वहां की स्थिति क्या होगी । तीस घण्टे तक दो सौ गांव पांच फीट से लेकर 15 फीट डूबे रहे । लोगों ने अपनी जान मकान के छप्पर पर चढ़कर बचाई । फिर भी 559 आदमियों की जानें गई और 70 हजार पशुओं की जाने गई । एक लाख मकान सिर्फ दो सौ गांवों में गिर गए, जिनमें से 80 हजार टूट गए और 60 हजार खण्डित हो गए, जो कि रहने के काबिल नहीं हैं । रेलवे लाइन टूटी रही और कोई काम्यूनिकेशन व्यवहार नहीं रहा । कौन से गांव की क्या स्थिति है, उसकी दस दिन तक मालूमात नहीं हो सकी । आठ-दस दिन तक फूड पैकेट हैलीकॉपटर द्वारा गिराए जाते रहे, जिससे कि लोगों का गुजारा हो सका । खेती की जमीन एक लाख हैक्टेयर वाश-आउट हो गई, वह खेती करने के लायक नहीं रही । मैं ज्यादा डिटेल में न कहते हुए, मैं यह कहना

चाहता हूं कि हमारे देश की प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री और राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा उस क्षेत्र का दौरा किया गया है, जिससे आपको वहां की गम्भीरता का अन्दाजा लग सकता है। दो शब्द अब मैं सहायता के बारे में कहना चाहता हूं। आज कल जो हमारा एस्सिटैंस का पैटर्न है उस को बदलने की जरूरत है क्योंकि हमारा यह पैटर्न बहुत पुराना है। पिछले कई सालों में हमारे यहां मंहगाई बढ़ी है। आज जो एस्सिटैंस का पैटर्न है उस में किसी हट की रिपेयर के लिये जो साइक्लोन या फ्लड से डैमेज होती है 100 रुपये प्रति हट दिये जाने की व्यवस्था है। इसी तरह से हट के रीकंस्ट्रक्शन के लिये 200 रुपये दिये जाते हैं। आज की मंहगाई में 100 रुपये या 200 रुपयों में एक खम्बा भी नहीं आता है। हमें अपने फाइनेन्स कमीशन को कहना चाहिये कि यह सिस्टम बदलना चाहिये। गुजरात सरकार इस में एक हजार रुपये देती है, लेकिन केन्द्र जो 200 रुपया देता है उस में भी 75 प्रतिशत यानी 150 रुपया देता है। हमारे यहां एक लाख से ज्यादा मकान गिरे हैं, अभी वहां सब लोग बारिश से भीगे पड़े हैं...

राव बीरेन्द्र सिंह : अभी तक कपड़े नहीं सूखे हैं ?

श्री मोहन लाल पटेल : कपड़े तो सूख गये, लेकिन बारिश अभी भी आ रही है, फिर भीग जाते हैं।

उन के पास अभी तक रहने के लिये कुछ नहीं है। कारुगेटेड शीट्स के कामन शेड बनाये गये हैं जिन में पानी आ जाता है। अभी तक कोई पक्की व्यवस्था नहीं है। वहां की गवर्नमेंट ने आप के पास एक टेलेक्स भेजा है जिस में कहा है—

> "Under the provision of Government of India, Ministry of Finance letter No. 43 (1)/F-79 dt. 25th April 1979; when the calamity is of rare severity, Central Government may extend assistance to the State concerned beyond 75 per cent of the total expenditure in excess of the margin money."

मैं आप से पूछना चाहता हूं—"रेअर सिविरिटी" किस को कहते हैं। अगर सब मर जायेंगे तो उस समय आप किस को मदद देंगे। मेरे यहां जो 200 गांव मोस्ट-एफेक्टेड हैं, उन की सब चीजें बरबाद हो गई हैं, उन का खाना, दाना, रवी का गेहूं, मक्का, सब बरबाद हो गया है—अगर आप इस को "रेअर सिविरिटी" नहीं गिनेंगे तो क्या गिनेगें ? तब फिर "रेअर सिविरिटी" किस को मानेंगे। वहां 100 प्रतिशत सहायता देनी चाहिये तथा आपका जो पैटर्न आफ़ एस्सिटैंस है उस में सुधार करना चाहिये, क्योंकि वह बहुत पुराना हो गया है।

जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक साल के अन्दर यह दूसरा तूफान है। इस के पहले साइक्लोन आया था और इस समय भी साइक्लोन आया है और साथ ही बाढ़ भी आई है। वहां पर बहुत सी संस्थायें रिलीफ का काम करना चाहती हैं। वे एक या दो या तीन गांवों को एडाप्ट करना चाहती हैं, पूरे मकान बना कर देना चाहती हैं। उन संस्थाओं की यह मांग है कि इन्कम टैक्स एक्ट में 35 (सीसी) के अन्तर्गत उन्हें छूट दी जानी चाहिये जिस से इस काम के लिये धन इक्टठा करने में बहुत सहायता मिलेगी।...

उपाध्यक्ष महोदय, हम तो पहले ही डूबे हुऐ हैं, थोड़ा और रोने दीजिये।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Be short and complete it. Your own colleagues want to speak. They will be deprived of the opportunity. Everybody must participate and report to their constituencies. You are not speak for yourself only.

श्री मोहन लाल पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहां से आता हूं जहां सब से ज्यादा नुकसान हुआ है।

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then it will go up to 12 O'clock. The Minister will

speak at 7 O'clock. I have already announced.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : You are raising points which should be raised in the State Assembly.

SHRI MOHAN LAL PATEL : Nobody has raised the points which I am raising. These are new points.

MR. DEPUTY SPEAKER : To give some advance or loan for huts and all that has to be done by the State Government. What has Rao Birendra Singh to do about that ? You speak on policies, how floods must be stopped ; how droughts are to be dealt with. Only policy matters are to be discussed in Parliament. The subjects which you are mentioning are to be discussed in the Assembly.

श्री मोहन लाल पटेल : हमारे यहां जो बाढ़ आई, उस में सब डिपार्टमेंट्स ने अच्छा काम किया है लेकिन जो टेलीफोन डिपार्टमेंट का काम हुआ, उस के बारे में मेरी बड़ी शिकायत है क्योंकि बिना कम्युनिकेशन्स के कोई भी रिलीफ का काम नहीं हो सकता । हमारा टोटल रिलीफ वर्क कम्युनिकेशन के ठीक न होने की वजह से कोलैप्स हो गया और 10 दिन तक कोई काम न हो सका । मैं आप को एक तार की कापी देना चाहता हूं, जिस को मैंने गाडगिल साहब, जो कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, को भेजा था । यह ट्रू सर्टीफाईड कापी है और यह 5-7-83 का तार है । इस में लिखा है :

> "In Saurashtra, unprecedented floods have taken a very heavy toll of men, cattle and property. Hundred died. A number of villages marooned and surrounded by waters. Prime Minister personally visited the area. Army, Navy and Air Force organised a lot of help. The only Department not helpful is Telephones. Urgent necessity to establish contacts with important places. Power lines and poles restorted. Only the Telephones administration totally negligent and non-cooperative. Please do something immediately."

यह जो तार मैंने भेजा था, इस का कोई जवाब आज तक मुझे नहीं मिला... (**व्यवधान**) जो वहां पर लगभग 20 हजार टेलीफोन हैं, उन में से 15 हजार टेलीफोन आज भी बन्द हैं और टेलीफोन ठीक होने से जो काम रिलीफ का जल्दी हो सकता था, वह नहीं हुआ । मेरी प्रार्थना है कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब इस तरफ ध्यान दें । मैंने जब डी०ई०टी० से पूछा कि इन को ठीक करने के लिए बाहर से कितने आदमी मदद के लिए आए हैं, तो मुझे बताया गया कि 2 आदमी अन्डरग्राउन्ड केबिलों की रिपेयरिंग के लिए और ओवरहेड लाइनों के लिए 10 आदमी आए हैं । मेरा कहना यह है कि जब इतने सारे टेलीफोन बेकार पड़े हैं, तो ज्यादा फोर्स उन को ठीक करने के लिए लगानी चाहिए ।

MR. DEPUTY SPEAKER : I will stop hon. Members after every hon. Member has spoken for 10 minutes. The Minister has also got to reply. Mr. Patel, you have already completed 10 minutes. I will allow only 10 minutes for each member. I am sorry I have to be very strict now. You must cooperate with me. If any member takes more time, you must join me in making him stop.

Mr. Kandaswamy.

SHRI MOHAN LAL PATEL : I am concluding. Only one minute.

MR. DEPUTY SPEAKER : It is only to help your own colleagues. All right ; one minute more.

श्री मोहन लाल पटेल : सौराष्ट्र में अभी भी बारिश का जोर बढ़ रहा है । सिंचाई मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं । हम ने उन से मांग की है कि जो डेम बने हुए हैं, उन की जांच की जाए । मेरा कहना यह है कि अगर 100 इंच भी बारिश हो जाए, तो भी वे डेमेज नहीं होने चाहिएं और वे इतने पक्के बनने चाहिए कि बहुत ज्यादा बारिश भी उन पर असर न कर सके । यहां से जो स्पेशल टीम गई थी, उस ने

5 डैमों को देखा और उनके बारे में अपनी रिपोर्ट दी है ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बारिश शुरू होती है, तो आकाशवाणी से यह सूचना दी जाती है कि फलां डैम ओवरफ्लों हो रहा है और जो नीचे वाले गांव हैं, वे जल्दी से उन को छोड़ कर चले जाएं । मेरी आप से प्रार्थना है...

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Kandaswamy.

श्री मोहन लाल पटेल : हमारे राज्य शासन ने फ्लड अफक्टेड एरिया के लिए 4 हजार मीट्रिक टन चीनी, 4 हजार मीट्रिक टन पोमेलीन, एक हजार टन सीमेंट, 5 हजार टन केरोसीन, 2 हजार टन चावल की मांग की है । मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी से जल्दी इसके बारे में कोई निर्णय कर के इनको शीघ्र भिजवाने की कृपा करें ।

*SHRI M. KANDASWAMY (Tiruchengode) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am very happy that this House has got an opportunity to discuss about the flood and drought situation in the country and also about the need to take short term and long term steps for finding a lasting solution to these twin evils. On behalf of my party the Dravida Munnetra Kazhagam, I wish to say a few words on this Resolution under discussion.

Sir, the south-west monsoon and north-east monsoon cause floods in our country. The northern States and the North-eastern States in our country are ravaged by floods on account of south-west monsoon and the north-east monsoon causes floods in southern States. While the floods are common in northern States, the southern States rarely witness such floods. According to governmental statistics, the annual loss due to floods and drought is of the order of Rs. 100 crores on an average. All over developmental efforts are offset by the recurring floods and drought in the country. Here I have to say that ten times more money is spent on flood control measures as compared to the expenditure on drought relief. For instance, the Government of Tamil Nadu is understood to have asked for Rs. 100 crores adhoc drought relief assistance but only less than Rs. 20 crores has been given by the Centre. On the other hand, the Centre has fully met the demands of flood-affected States. This kind of partiality in fighting the natural calamities/will/undermine the confidence of the drought-afflicted people in the Southern States, particularly the people of Tamil Nadu which is reeling under an unprecedented drought.

Sir, I have to say that such *ad hoc* assistance for undertaking drought relief measures should not be deducted from the Annual Plan allocations of the States. This is not a man-made calamity. The developmental plans of the States get deranged because of this adjustment. I demand that a separate DROUGHT RELIEF FUND should be constituted by the Central Government, out of which *ad hoc* financial assistance should be given to the drought-prone States. There should be regular flow of funds for drought afflicted States. Then only a lasting remedy can be implemented.

In Tamil Nadu, Thanjavur which is called the granary of Tamil Nadu and as rice-bowl of the State has today become an arid zone. The green fields have become parched earth. The Mettur Reservoir wears the look of a desert through this is the season for full flow of water in this reservoir. The canals are just dry streaks of earth in Thanjavur district. I have to blame the Centre for this sordid state of affairs in Tamil Nadu. If the Centre had taken the initiative to solve the Cauvery water dispute, this situation would not have arisen. A decade ago the announcement about constituting Cauvery Valley Authority was made by the Centre ; till today this Authority has not seen the light of the day.

The unprecedented drought in Tamil Nadu has taken the toll of lakhs of coconut trees and thousands of cattle, besides loss to the standing crops which withered away. The agricultural workers are migrating to other States as they do not have even drinking water in the villages. The drinking water crisis in the rural areas has reached alarming proportions. I have to blame the

*The original speech was delivered in Tamil.

State Government of Tamil Nadu for its failure to implement drinking water schemes in the rural areas. The Centre should have provided more funds for drinking water schemes in the villages.

There is no power for taking water through pumpsets from the bowels of the earth. The Hydel Power Stations do not generate power for want of water. For want of coal the Thermal Power Stations are not generating power. The power crisis has enveloped the State of Tamil Nadu. While inaugurating the Kalpakkam Atomic Power Plant in Tamil Nadu our hon. Prime Minister gave the rude shock to the people of Tamil Nadu by saying that the other Southern States have also a share in the power produced in Atomic Plant here. All these years the people of Tamil Nadu were cherishing the fond hope that the entire power produced in Kalpakkam Atomic plant would be exclusively given to Tamil Nadu. Now they feel that a grand deception has been practiced on them. I demand that all the power produced in Atomic Plant should be given to Tamil Nadu only the people will have some respite from the rigours of drought.

Sir, I would suggest that the loans given to the farmers through cooperative societies should not be recovered. All these loans should be waived by the Central Government in the interest of farmers in drought afflicted areas. Fresh loans should be sanctioned to them for digging wells and installing pumpsets. They should be supplied with hybrid varieties of seeds free of cost enabling them to continue with their avocation of agriculture. A national crop insurance scheme should be introduced forthwith for the benefit of farmers afflicted by such natural calamities. There is inordinate delay in the sanctioning of IRDP loans. The Government of India should ensure immediate sanction of IRDP loans to the farmers.

The drought in Tamil Nadu has lead to soaring prices of essential commodities. The cost of rice per Kg. is Rs. 6 to Rs. 6.50.

MR. DEPUTY SPEAKER : We are going to have discussion on price increase. Then you can deal with this subject.

SHRI M. KANDASWAMY : Sir, the poor people cannot buy rice from outside the fair price shops. But in fair price shops they are just getting 5 Kgs. per month, though they are entitled to get 20 Kgs. How do you expect them to survive ? It is just like the weeping child getting one plantain. This should be looked into by the Government and adequate supplies of rice should be made to Tamil Nadu. Before I conclude, I would suggest that the Central Team visiting the Drought-afflicted States should consult the local M.Ps and M.L.As about the extent of drought prevailing in their areas and after that only they should submit their report to the Government. I would demand that as short term relief work, road laying work should be taken up extensively. With these words I conclude my speech.

श्री उमाकान्त मिश्र : (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष जी, दुर्भाग्य की बात यह है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सारे देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति पैदा हो गई । हमारे गुजरात और असम में भंयकर बाढ़ है, और उसके साथ ही देश के बहुत से भागों में भयंकर सूखा है । हमारे श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री ने कहा है कि 3, 4 महीने बाद सूखा आने वाला है, मेरा कहना यह है कि अभी सूखे की स्थिति पैदा हो गई है । मैं अभी इन्टरमैशन में दिल्ली से पटना तक गया था । जुलाई के पहले हफ्ते में पानी बरसा और इसके बाद पानी बरसना बन्द हो गया । 17 जुलाई से 20 जुलाई तक फिर पानी बरसा और उसके बाद फिर बन्द हो गया ।

हमारे क्षेत्र मिर्जापुर, बनारस, इलाहाबाद, बुन्देलखंड और उत्तरी यू०पी० में बहुत सी जगह जहां सिंचाई के साधन नहीं है, वहां भदई की जो फसल होती है, अर्ली पैडी, क्वारी धान की फसल समाप्त हो गई है । 40 परसेंट सूखा ही पड़ा है । धान की जो रोपणी होती हैं वह पानी के बिना नहीं हो पा रही है । रोपणी सिर्फ वहीं हो रही है जहां एश्योर्ड इरिगेशन है जैसे गंगा नहर, राम गंगा नहर, शारद सहायक नहर, देवखली पम्प, नारायणपुर पम्प वगैरह जहां कि सिंचाई की गारन्टी हैं । बाकी

सारे इलाकों में धान की रोपणी नहीं हो रही है। सारे प्रदेश के आधे से अधिक हिस्से में पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर, भयंकर सूखे की स्थिति हो गई है। पिछले वर्ष के सूखे में और इस वर्ष के सूखे में अन्तर केवल यह है कि गत वर्ष पहले पानी बरसा तो नदियों में पानी आ गया, छोटे-मोटे बांध भर गये लेकिन इस वर्ष पहले पानी बरसा, दूसरा पानी बरसा लेकिन बांधों में पानी नहीं आया, बांध खाली पड़े हैं। केवल बड़ी नदियों से जो नहरें निकलती हैं, उनसे ही सिंचाई हो रही है। या ट्यूबवैल से या गंगा, यमुना नदी की नहरों से सिंचाई हो रही है। बाकी जो छोटे बन्ध हैं, मिर्जापुर वगैरह के वहां एक भी बून्द पानी नहीं है, एकदम सूखा है, तालाब नहीं भरे हैं, कुंए नहीं भरे हैं। यह स्थिति इस साल हो गई है। पिछले साल से ज्यादा सूखे की स्थिति हो गई है। पेय जल की संभावना कम हो जायेगी अगर पानी नहीं बरसा तो।

हम यह आशंका व्यर्थ कर रहे हैं जैसे अप्रैल मई में पानी बरसा फिर सूखा पड़ गया। कुछ ऐसा लगता है कि देश में, दुनिया में जो प्राकृतिक ऋतु चक्र है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। गर्मी में पानी, जाड़े में पानी, वर्षा में पानी की कमी, जाड़े में गर्मी, जैसे प्रधान मंत्री जी ने दल की बैठक में कहा कि सारी दुनिया में ऋतु चक्र में परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिये हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिस मौसम में धान की खेती करते हैं, उस मौसम में कौनसी खेती करें। इसलिए कृषि मंत्री से निवेदन करूंगा कि कृषि वैज्ञानिकों से सलाह कर के बतायें कि देश में किसान किस तरह से खेती करें। अभी गंभीर स्थिति पैदा होने की संभावना है।

मैंने सारे उत्तर प्रदेश का दौरा तो नहीं किया है, लेकिन गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद और झांसी आदि पांच छः मंडलों में सूखे की स्थिति है। इस लिए वहां पर सूखा-रहित कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। उत्तर प्रदेश 11, 12 करोड़ की आबादी का एक बहुत बड़ा प्रदेश है, जिसमें चार पांच प्रकृति की भूमि है और चार पांच तरह की आबादी है। इतने बड़े प्रदेश में किसी इलाके में सूखा रहता है और किसी इलाके में बाढ़ आती है। हमारे प्रदेश की कई सिंचाई योजनाएं रुकी हुई हैं, क्योंकि उनको पूरा करने के लिए पैसा नहीं मिला है, हालांकि वे योजनाएं योजना आयोग द्वारा एप्रूवड हैं। अगर हमारे जिले की ज्ञानपुर पम्प नहर, सोन पंप नहर और कनहर नदी बांध योजना को पूरा कर दिया जाए, तो सूखे का प्रहार हमारे जिले के केवल आधे हिस्से में रह जाए। सिंचाई मंत्री से मेरा निवेदन है कि उत्तर प्रदेश की जो सिंचाई योजनाएं अर्थाभाव के कारण रुकी हुई हैं, उन्हें पूरा करने के लिए वह धन की व्यवस्था करें।

मिर्जापुर के 20 में से 14 ब्लाक ऐसे हैं, जहां हर तीसरे साल सूखा पड़ता है। वहां पर सिंचाई के साधन नहीं हैं। वहां पर कुछ इलाकों में ड्राउट प्रोन एरिया प्रोग्राम को खत्म कर दिया गया है और कुछ में वह चल रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि मिर्जापुर जिले में डी पी ए पी को समाप्त न किया जाए, उसको चालू रखा जाए।

सूखे की समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं को पूरा करने में तो समय लगेगा, परन्तु कुछ तात्कालिक योजनाओं को कार्यान्वित करना चाहिए। उदाहरण के लिए गंगा नदी में कई करोड़ क्यूसेक पानी बह रहा है, लेकिन उसके किनारे के खेत सूखे पड़े हुए हैं। गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की तो एक बड़ी भारी योजना है, लेकिन गंगा, जमुना, सोनभद्रा, दक्षिण में कृष्णा और कावेरी और ब्रह्मपुत्र आदि जिन नदियों में स्थायी रूप से पानी रहता है, वहां पर पंप कैनाल बना दी जाएं और पानी को ऊपर उठा कर खेतों तक पहुंचाया जाए।

हमारे प्रदेश और हमारे जिले में भयंकर सूखे की स्थिति है। उसका मुकाबला करने के लिए तात्कालिक समाधान तो यह है कि राहत-कार्यों की व्यवस्था की जाए और दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की सिंचाई योज़नाओं के लिए अधिकतम धनराशि दी जाए, जिससे वहां पर सिंचाई की व्यवस्था की जा सके।

SHRI P.K. KODIYAN (Adoor) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I have very little time at my disposal.

MR. DEPUTY SPEAKER : Just a minute. The Minister is to reply at 7 O' Clock.

SHRI P.K. KODIYAN : We are at the tail-end. They are always at a disadvantage.

MR. DEPUTY SPEAKER : What to do ? Every hon. Member has got to co-operate with me. We are ringing the bell. Nobody stops from speaking. What can we do ?

If I give you five minutes, you come out with your points. I would give you five minutes. I would request all these hon. Members who have spoken here should remain present in the House till the end. When the Minister replies, if the members are not here, he will not reply to the points raised by the Members who have spoken but who are not present in the House. The Minister need not reply to the points raised by those hon. Members who are not present in the House. You reply only to those who are present.

SHRI P.K. KODIYAN : At the very beginning I would like to put some questions to the Hon. Minister. The Government have some long-term and short-term plans to deal with the recurring floods and droughts. We find that the drought and floods occur in a more serious manner even in areas which get the Government's special attention under the Flood Control Scheme and the Drought Prone Areas Schemes. Why is that in spite of so much of money being spent over the last many years, you are not able to solve this problem at least to some extent ? Instead of solving this problem, at least to some extent we find that every year the problem has been becoming more and more serious.

My second question is this. This year we had unprecedented droughts. Large parts of the country had suffered and some States have been suffering droughts continuously for years. For example, in Tamil Nadu, I think it is the fourth consecutive year and in Kerala it is the second consequtive year. Rajasthan has been suffering almost perennially from the droughts. Similarly areas in the Northern India,—some parts of UP, some parts of Bihar —and, of course, Assam, are suffering from floods in a more devastating manner. I want to ask the Hon. Minister whether this unprecedented occurrence of the natural calamity has anything to do with the disturbance in the ecological system in the country ? Whether deforestation that has been going and there has been felling of trees indiscriminately often by big contract with powerful political backing in the Himalays and in other areas whether it is South, North or East, has anything to do with it ? Why have you not been able to control it. In other words, I specifically ask why have the Government been allowing this systematic destruction of the econology of our country ?

RAO BIRENDRA SINGH : Have we not passed a special Act for this purpose ?

SHRI P.K. KODIYAN : That is why I am putting this question. Why despite all this Act has been going on ?

The third question I would like to ask is about the large-scale unemployment and distress as a result of serious drought situation in several parts of the country. Mr. Jain, the Hon. Member from Rajasthan when he was speaking was very furious about the situation there. He was talking how the people in Rajasthan were suffering, due to continuous drought, and how they were forced to migrate to other areas in Haryana and Punjab. He was speaking with emotion.

This is the situation not only in Rajasthan, but also in other areas, in parts of West Bengal, parts of Bihar, parts of U.P., parts of Tamil Nadu and Assam.

This year, particularly from Bihar, the

number of migrant agricultural workers to Punjab and other areas has gone up unprecedently very high. Why ? Similarly, take Tamil Nadu. Thanjavur, as the hon. Minister knows, is the rice bowl of the South. Lakhs and lakhs of agricultural workers and peasants are there. They are very hard working people. But from there, lakhs and lakhs of agricultural workers are compelled to leave, not to other districts in Tamil Nadu, because the majority of districts in that State are affected seriously by drought, but to Karnataka, Andhra Pradesh and other States. Why is it so ?

You are claiming that you are spending a lot of money under the National Rural Employment Programme ..

SHRI CHITTA BASU : They are not spending.

MR. DEPUTY SPEAKER : Mr. Chitta Basu, if you interrupt very often, I will not call your name.

SHRI P.K. KODIYAN : A large number of poor people are compelled to lead their lives under conditions of starvation. Perhaps the hon. Minister may deny if I say that a number of starvation deaths have taken place in. Bihar, parts of U.P. and Rajasthan. You may deny, but as one who is working among the poor people in the villages, I can give evidence also. Perhaps even then you may deny it, because you would say you have the National Rural Employment Programme and so many other schemes to help the people, and that they are not allowed to starve—according to you and not allowed to die of starvation.

These are some of the questions I am putting.

18.53 Hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI *in the Chair*]

Hon. Members who have spoken earlier have given a number of suggestions. I would say that you have to tackle this problem with people's cooperation. Even the NREP has to be implemented with people's cooperation. So also your mass tree plantation programme, the so-called afforestation programme. How is it implemented ? You implement it through the bureaucrats. There is no people's cooperation. Mr. Panigrahi was specifically pointing out...

RAO BIRENDRA SINGH : In West Bengal, it is always people's cooperation according to the State Government, but there are complaints about that also.

(*Interruptions*)

SHRI P.K. KODIYAN : Please understand the spirit of the criticism and try to improve the situation. I am not blaming any particular party. So, people's cooperation is necessary. I have seen how the tree plantation scheme works. It is being done as a ritual. You may tell us here that so many lakhs and millions of trees have been planted, How many of them will survive ? Against man and the beast, how many of them will survive ? Even then, have not cared to seek people's cooperation.

Lastly, I want to speak about my State. Whatever Mr. Balanandan has said here, I full support. The Kerala Government has submitted a scheme for drought assistance amounting to more than Rs. 284 crores. There is another supplementary schemes amounting to nearly Rs. 300 crores for crop rejuvenation. You have sanctioned so far only Rs. 36 crores ; and that too a part of this assistance has been given as plan assistance. The hon. Minister should explain how much has been given as loan, how much has been given as grant and how much has been given as part of plan assistance out of this.

Shri Chintamani Panigrahi has mentioned that Orissa was given Rs. 200 crores as drought relief. I have no grudge against the liberal assistance being given to Orissa by the Centre. Orissa has suffered so much under various natural calamities, cyclones, drought and floods. But, what is the justification of giving only Rs. 36 crores to Kerala State out of the total assistance sought for, that is Rs. 284 crores ? How is it that you were able to give only Rs. 36 crores and that too a major part of it as plan assistance ?

As has been pointed out, we are having paddy crop in a limited area. We are devoting most of our irrigated area for cash crop, which is earning valuable foreign exchange for the country. Now all plantation crops including coconut, coffee, cardamom, tea and

rubber, have been serously affected by drought ; and for all these plantation crops, it takes years for rejuvenation. If we are losing paddy crop this year, we hope next year we can raise a better crop if there is rain. But, so far as plantation crops are concerned, it takes years for rejuvenation. That is why Kerala State requires a special assistance apart from drought relief for rejuvenating its economy is mainly depending on plantation crops, which help us earn valuable foreign exchange.

Therefore, I request the hon. Minister to consider our case for assistance for drought relief as well as for rejuvenation of the affected plantation crops with sympathy and provide assistance as liberally as possible.

SHRI TARUN GOGOI (Jorhat) : Madam, Chairman, ours is a country which is ravaged by various types of calamities. We are having the problem of surplus of water as well as scarcity of water. As a result of which there is a colossal loss to the economy of the whole country.

I would like to come to my own State. This time our State has been affected by the floods. There have been unprecedented floods not only once but thrice and even fifth time already. Not only that. The flood season is not yet over. It may come again. There the flood continues upto the end of September. In my State, floods have become an annual feature. As a result of which the economy of whole Assam has been badly affected. Since 1950 when there was an earthquake; the topography of the State had been changed. As a result of that there has been flood every year in Assam.

Assam is rich in natural and mineral resources. Despite this, its economy is in poor shape. Assam's economy is mainly agricultural economy. There more than 70 per cent of the people depend on agriculture. So, it is the poor agriculturists who suffer most.

Besides floods, there is erosion also. Thousands of acres of cultivable land has already been eroded and thousands of people have to be shifted to other areas.

River Brahmaputra has become a river of sorrow. On the other hand, if it is harnessed properly, it wil, help bring prosperity not only to our State but to the entire country. It has got the capacity to generate a few thousand megawatts of electricity. Besides the Brahmaputra other rivers also bring lot of sufferings to the people. This year 17 persons have already lost their lives. Thousands of people have been rendered homeless. Thousands of people have to be rescued. They have taken shelter in different camps. Besides that, the standing crop—paddy, jute and other crops – in 1.5 lakh hectares has already been damaged. Vast areas of Sibsagar, Jorhat, Majlisi, Lakhimpur, Tejpur, etc. have been submerged. The Bugdoh river is very much higher than the ground level of the Sibsagar town itself. So, many areas of that town were under water. Besides this, the water level of the Brahmaputra and its tributaries had all along been above the danger level. As a result of whicn there is a constant pressure on the embankments. There have been breaches in different areas of the embankments, So, immediate repair work of those branches has to be undertaken. The Government of Assam has asked for Rs. 7 crores for the repair of breaches and Rs. 3 crores for immediate relief. But uptil now, no money has been sanctioned. I am happy that the Minister of State, Mr. Mirdha, is going to Assam day after tomorrow. He will visit different parts of my State. Besides that, I also request the Minister to send immediately a central team to assess the situation there. This team is long overdue. It should have been sent to Assam long back.

Every year because of floods there is disruption of read communication and sometimes rail communication also. As a result of that, prices of essential commodities go up. All along we have to pay exhorbitant prices. To tide over the crisis, the Government of Assam has asked for 5000 MT of rice and 5000 MT of wheat from the Centre. The Central Government should take immediate steps to despatch these quantities of rice and wheat, so that they can meet the situation there.

The Brahmaputra Control Board has been constituted after a long time. But the progress has not been very satisfactory. There was a proposal to construct two dams—one at Subensiri and another at Dihang. But

so far, no satisfactory progress has been made. I hope, speedier steps will be taken so that this dam could be constructed as early as possible. We have been hearing for a long time about linking of Brahmaputra with Ganga Necessary steps should be taken so that these schemes can be materialised as early as possible. Besides Brahmaputra, its other tributaries are also creating problems because the river-beds of all these rivers have raised because of silting. So, steps should be taken for raising the embankments of those different rivers also, particularly the Bhugdoi river. Bhugdoi river is a river of my town. Because of the silting, the river-bed has become much higher. So, unless raising is done in different tributaries also, it will not be possible to check the floods. I hope, the Government will take all the necessary steps to mitigate all these hardships and problems. So far we have been taking only ad hoc measures. Not that the Government of Assam or the Government of India have not spent money, they have spent lot of money. In spite of that we have not been able, not only to control but even to minimise the problems. So, we must take comprehensive steps. It is not possible for a State like Assam, with its limited resources to take up a gigantic plan. This undoubtedly requires a massive plan and massive resources also and I hope the Government will give due consideration to these. With these words I conclude.

PROF. NARAIN CHAND PARASHAR (Hamirpur) : Madam, the country is once again faced with a serious situation. Some parts of the country are really under flood and some others are suffering because of drought. In my own State, though floods are not there but heavy rains have damaged some crops, especially in Hamirpur district. Therefore, we have to pay some attention to this.

Madam, Himachal Pradesh is a land through which the rivers flow but it is again in a matter of pity that in some parts of the State drought is there, We have been subjected to the problems caused by the construction of big dams, irrigation dams. People are aware of Nangal Dam, people are aware now of Pong Dam and Sutlej-Beas link Project and all that. But all these dams and irrigation projects have drained the water out of Himachal Pradesh. When the people there want to cultivate and irrigate their fields, then the authorities demand the payment at the rate of Rs. 21 per cusec. So. this matter was brought by me to the notice of the hon. Minister that we should not be asked to pay for our own water. This is a very strange situation and he has agreed to consider the matter, So, the Himachal Government, with its limited resources, could only encourage tubewells and all that small projects. We are looking forward to the Minister of Irrigation for having irrigation projects which are brought to his notice. One of these projects is known as the Swan Channelisation Project in Una district which would cost over Rs, 70 crores. This should be executed with the help of the World Bank. This project was forward by our Government to the Ministry of Irrigation and is currently under the examination of the Central Water Commission: If approved and executed, this will bring green revolution in the lower parts of Himachal known as the Shivalik ranges, with which our Minister for Agriculture is very familiar beeause we were at one time part of Punjab,

Madam, the damage caused by rains is so terrible that about 50 to 60 per cent of the crops, maize crop at the moment, have been destroyed and the people are left with no recourse. Now when we are faced with such a situation, we debate upon this. We debate this problem year after year. One thing comes to my mind, and that is something which I have been pleading earlier, that we should have some permanent machinery so that they can swing into action. Now what happens is that we have to depend upon the State Government, which in turn depends upon the district administration and down below to the patwari and even to the lowest official in the hierarchy. He submits his report and through the various channels it ultimately comes up to the Central Team. It is only when these two reports match that something comes out.

There is another very strange thing about the programme of relief. Lately, recourse has been taken to providing permanent assets, to build assets under the drought programme, or relief programme, NREP and things of that type. But there are certain cases which are hard-hit under

this arrangement in offering employment. In certain families there is nobody to take advantage of this programme. For example, there may be some widow who may be getting her fields cultivated through workers on daily wages ; or there may be some old people who are getting their fields cultivated. How can they help in the construction of roads, school buildings and all that if their crops are destroyed ? They get no individual compensation. So, I would suggest that there should be a matching of the two ; individual compensation or individual relief should be given in such hard cases and permanent assets should also be created.

In addition to this, there is the permanent feature of our perennial irrigation, which can be encouraged. I have written to the hon. Minister of Irrigation that the Beas, the Sutlej and the Rabi, these three rivers flow through the interior of Himachal Pradesh, on the other side the Yamuna flows and, to some extent, the Chenab also flows through Himachal Pradesh. Just as the hon. Member from UP was saying, while Ganga is full of water, the fields on the banks of the Ganga are dry and, therefore, they are drought-hit. Similar is the situation in Himachal Pradesh. The rivers are flowing down into the big barrages and big dams, which have been constructed by the Government at the Centre and the Punjab and other States. But the fields on the banks of these rivers are dry. So, if in Hamirpur, Una and Bilaspur through which the Beas, Sutlej and some other rivers flow, if some medium and minor irrigation projects can be started, that would be of great use to our State.

Recently you must have read in the newspapers about a strange disease with which we have been afflicted, and that is the scab disease in apple, This has destroyed the cash crop of Himachal Pradesh in an unprecedented scale, and the people, who used to earn their liveli-hood and who were thinking of leading a normal way of life by the money they were earning from apple are put to such a great loss that the State Government had to resort to some drastic action. The Chief Minister announced that he will purchase all the diseased apple and destory them. If it is not done, what would happen is that the disease would spread and it would engulf the rest of the area, which is now not affircted by this disease. So, I would strongly urge on the hon. Minister, who incidentally also holds the portfolio of Horticulture, to send some expert team, which can carry out some research and find some cure for this deadly disease.

This disease has come from Kashmir through Kulu and now it has spread in Simla, Solon and Kinnor districts. The result is that the entire economy of Himachal Pradesh has been very adversely affected by this disease. So, I would suggest that some sort of immediate solution should be found to this by the Centre. Our State does not have the reasources to have the research carried out.

We have noticed one thing. There is a variety of apple which is more subject or prone to scab disease. The juicy apple, whose sweet content is higher, they are very easy quick and prone to such disease whereas the other varieties of apple, which are not so juicy, whose sweet content is not so high, they are not so prone to this disease. Therefore, immediate resarch and relief are needed on this score.

With these words, I would request the hon. Minister to take a view of the hill States, of the country in a larger perspective. Everybody accuses the hill States that there is deforestation, the contractors are doing this and doing that. The State Government of Himachal Pradesh and the other hill States are not fond of cutting down trees. They want to preserve wild life, the flora, the fauna, everything. But what happens is that the merchants from the plains the big sharks, they go and rob the hill States of the forest wealth. Similarly, people from other areas go there, rob us of the waters and all the natural resources which we have got.

So, the Hill States should be treated on a different footing. They should be given funds for preserving their flora, fauna and forest wealth so that they are not robbed by people who are influential, who use the money as a tool to buy things from the hills. They take away our labour and our resources also. That is why I say the hill States should be treated on a different

footing. Irrigation may cost more, but they need irrigation projects. So, irrigation and other facilities should be provided to them. With these words, I would request the hon. Minister to pay special attention to this serious problem of scab and the heavy rains causing damage to the crops.

SHRI A. NEELALOHITHA DASAN NADAR (Trivandrum) : Madam Chairman, flood and drought have become a usual phenomenon in our national life for the last so many years. It is a shame on our parts that even after 35 years of Independence, even after our advance in science and technology we have not been able to control floods and droughts.

Members of this House from both sides, including the mover of the Resolution, Mr. Shastri, have mentioned various points of this question and I am supporting and endorsing all those views.

As my own State, Kerala, is facing unprecedented drought, I want to add some points regarding the unprecedented drought and its adverse effect on our economy, about which Mr. Balanandan and Mr. Kodiyan have already said something.

Madam, the seriousness of the drought situation in Kerala has been brought before the Central Government by the State Government of Kerala through three memoranda, namely, (i) the Memorandum on scarcity situation and assistance for relief expenditure in Kerala State in 1982-83, (ii) Supplementary Memorandum on scarcity situation and assistance for relief expenditure in Kerala State, 1983-84 and (iii) Supplementary Memorandum on crop loss due to drought and assistance for relief and rehabilitation expenditure in Kerala State, 1983-84.

Apart from this, there is the Report of the Central Team also pending with the Government of India. I request the Minister, through you, Madam, to say what was the report of the Central Team and what action has been taken on the recommendations of the central Team by the Government. I am sorry to point out that recently the Kerala State Assembly has passed unanimous Resolution demanding a minimum of Rs. 284 crores for the relief and rehabilitation measures to meet the drought situation in Kerala, but the Government of India has so far provided only Rs. 1 crore which is a meagre amount to meet the drought situation in Kerala. This shows the stepmotherly attitude of the Government of India towards Kerala. The Government of India has been showing this attitude to Kerala in all other matters for the last 35 years.

Madam, the seriousness of the situation can be understood by the fact that even upto this middle of August, there is not enough rainfall in Kerala and the factories in Kerala are closed down because of a power cut and workers are thrown out of employment and in all other spheres of power consumption the power cut has been applied strictly.

Madam, the damage caused by drought in Kerala, particularly to the agricultural front is not like the damage caused to other States. Particularly, it will take years at least from 5 to 10 years, for the perennial crops like coconut, pepper arecanut, tea, cardamom, coffee, cashew, cocoa, rubber, and spices like clove, nutmeg, cinnamon etc. to overcome the crisis even with the full assistance from the Centre to the State Governments.

The seasonal crops like paddy, tapioca, banana, sugarcane, cotton and sesam are also seriously affected by drought. The decline in production of pepper and cardamom, has affected our foreign exchange earnings also because through the export of these items we have been earning foreign exchange substantially. Not only drought has affected our agricultural production but it has also adversely affected quite a range of our economic activities including consumption, savings and investment.

Coconut is an important agricultural produce of ours. Actually, 1/7th of our total State economy comes from coconut. But because of this drought, the coconut production is affected, our agricultural production is affected, our agricultural economy is affected and our State's economy is affected. Because of the decline in Production in our plantation sector, it is going to affect our economy as a whole for so many years to come.

This unprecedented drought has foiled all our calculations regarding the Sixth Five Year Plan as far as the State of Kerala is concerned. That has already been pointed out by my hon. friend, Mr. Balanandan. I do not want to elaborate further on that.

Through you, Sir, I seek adequate financial assistance for Kerala as requested by the State Government and by the State Assembly, for providing complete assistance, for rehabilitation of crops completely destroyed, for providing compensation for the partially damaged crops and for providing interim relief along with compensation for workers thrown out of employment due to closure of factories because of power cuts on account of drought. In the plantation sector also, a large number of workers are thrown out of employment.

I also seek declaration of a tax holiday for all agricultural taxes and a moratorium for all agricultural loans till the crisis is over. During the period for which the moratorium is declared for agricultural loans, no interest should be charged for that period.

What is significant in this combination of drought and flood is that in India which has mighty rivers thousands of billions litres of water are flowing through these rivers, into the sea every day. The melting snow and the rains that precipitate the water resources every year are estimated to be the highest in the world in any country of similar size. If all these waters could be scientifically managed, both flood and drought could possibly be controlled to a considerable extent. So, I request the Government to declare water as a national asset.

I also request the Government to declare a national water policy' As a part of that policy, I also request for the implementation of an integrated and comprehensive land and water management programme. As a part of it, we can take up projects like the Ganga-Cuveri link project. We have been hearing of it even before independence. But even after 35 years of independence, we have not been able to implement that project. I request that the Ganga-Kaveri-Brahmaputra Link Project should be implemented which will help us in a long way to control floods and drought and which will also help us to provide employment to many young people of our country.

With these words, I express my pity and sympathy for all those people affected by floods and drought in various parts of the country whether it is Tamilnadu or Andhra Pradesh or West Bengal or Assam or Konkan area of Maharashtra or Saurashtra area of Gujarat or Rajasthan or parts of UP or Bihar and other places.

I also support all the demands for assistance from all those sections and regions of people.

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं सिर्फ दो-तीन प्वाइन्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूं। यह जो फ्लड और ड्राउट का मसला है, यह हमारी स्टेट में कुछ अलग ही है। करीब दो साल पहले मेरी कांस्टीटुएंसी में हेवी स्नोफाल की वजह से 80 हजार से ज्यादा भेड़ बकरियां और हजार से ज्यादा याक, घोड़े और बाकी कैटिल मर गए। उसके लिए वहां से हमारी सरकार ने सेन्ट्रल गवर्नमेंट को रिलीफ देने के लिए लिखा। मैं मशकूर हूं क्योंकि राव साहब ने 1 करोड़ 30 लाख की रकम रिलीफ के लिए (सारी स्टेट के लिए) सैंक्शन की जिसमें हमारा लाख का भी कुछ हिस्सा था। लेकिन बदकिस्मती से वह पैसा आजतक वहां नहीं पहुंचा है। (**व्यवधान**) आपका कहना है कि हमने जो 1 करोड़ 30 लाख वहां के लिए रिलीज किया था उसका स्टेट सरकार पहले हिसाब दे दो, तब लद्दाख के लिए रिलीफ दे देंगे। इसमें हम तो सफर कर रहे हैं। खाने वाले बीच में खा गए हैं। काबुली साहब नाराज हो जायेंगे अगर मैं कुछ कहूं तो। इसलिए मेरी गुजारिश यह है कि आप मेहरबानी करके रिलीफ दें क्योंकि वह, रिलीफ तो गरीब लोगों के लिए है, जोकि एन्टायरली भेड़-बकरियों को पाल कर गुजारा करते हैं। वह ट्राइबल्स हैं, इन्डोटिबेटन बार्डर पर रहने वाले हैं, भेड़-बकरियों की ऊन और पशमीने पर ही गुजारा करते हैं। उनका सारा

लाइव-स्टाक खत्म हो गया है। अगर उनको कुछ थोड़ी-बहुत रिलीफ दो साल पहले मिल गई होती तो 5-10 नयी भेड़-बकरियां खरीदकर वह उनको बढ़ावा दे सकते थे। मेरी आपसे गुजारिश है कि वहां के जो डी सी हैं उनको थ्रू आप डायरेक्टली रिलीफ का पैसा रिलीज कर दीजिए। ताकि जो पैसा देना है, वह जल्दी गरीबों तक पहुंच सके। इस बारे में राव साहब को भी पता है। दो साल पहले कुछ क्लाउड वर्स्ट की वजह से और कुछ सूखा पड़ गया था। इसकी वजह से लोग तकलीफ में हैं। यही दो बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाकर अपनी बात समाप्त करता हूं।

کی اون اور پشمینے پر ہی گذارہ کرتے ہیں۔ ان کا سارا لاؤ اسٹاک ختم ہو گیا ہے۔ اگر ان کو کچھ تھوڑی بہت ریلیف دو سال پہلے مل گئی ہوتی تو پانچ دس نئی بھیڑ بکریاں خرید کر وہ ان کو بڑھاوا دے سکتے تھے۔ میری آپ سے گذارش ہے کہ وہاں کے جو ڈی سی ہیں ان کے تھرو آپ ڈائریکٹلی ریلیف کا پیسہ ریلیز کر دیجئے تاکہ جو پیسہ دینا ہے وہ جلدی غریبوں تک پہنچ سکے۔ اس بارے میں راؤ صاحب کو بھی پتہ ہے۔ دو سال پہلے کچھ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے اور کچھ سوکھا پڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ سے لوگ تکلیف میں ہیں۔ یہی دو باتیں منتری مہودے کے دھیان میں لاکر اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔

SHRI CHITTA BASU (Barasat) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have moved an amendment consisting of five points. Since you have allotted me only five minutes, I will mention those five points.

The first point I want to draw the attention of the Minister to is that there should be a Task Force appointed for the purpose of undertaking a study and evaluating the result of the flood-control programmes and drought control programmes undertaken by the Government during the last three decades. The reason is this. As far as my memory goes—I say this without seeing my papers before me—for flood control measures till the end of the Fifth Five-Year Plan a total sum of Rs. 650 crores was invested ; the Sixth Plan allocation for flood control is Rs. 1,500 crores. In spite of these investments, floods have become an annual phenomenon. So far as drought is concerned, it is more or less a problem concering irrigation. So far as investment in the irrigation projects is concerned, it comes to about Rs. 7,500 crores uptill now. These programmes for the control of drought and the programmes for the control of floods have been undertaken by the Government, but no fruitful results have so far been achieved. So, it is time for us to undertake and evaluation so that concrete measures can be undertaken for the improvement of these programmes.

So far as the question of drought relief and assistance is concerned, I am not interested in going into the figures as to what have been the amounts the State Govern-

شری پی۔ نام گیال (لداخ) : سبھاپتی مہودے۔ میں صرف دو تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو فلڈ اور ڈراؤٹ کا مسئلہ ہے یہ ہماری اسٹیٹ میں کچھ الگ ہی ہے۔ قریب دو سال پہلے میری کانسٹی چوینسی میں ہیوی اسنو فال کی وجہ سے ستّر اسّی ہزار سے زیادہ بھیڑ بکریاں اور ہزار سے زیادہ یاک گھوڑے اور باقی کیٹل مر گئے۔ اس کے لئے وہاں سے ہماری سرکار نے سینٹرل گورنمنٹ کو ریلیف دینے کے لئے لکھا۔ میں مشکور ہوں کیونکہ راؤ صاحب نے ایک کروڑ تیس لاکھ کی رقم ریلیف کے لئے (ساری اسٹیٹ کے لئے) سینکشن کی جس میں ہمارے لاس کا بھی کچھ حصّہ تھا۔ لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ آج تک وہاں نہیں پہنچا ہے۔

- - - (انٹرپشن) - - -

آپ کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ایک کروڑ تیس لاکھ وہاں کے لئے ریلیز کیا تھا اس کا اسیٹ سرکار پہلے حساب دے تب لداخ کے لئے ریلیف دے دیں گے۔ اس میں ہم تو سفر (suffer) کر رہے ہیں۔ کھانے والے بیچ میں کھا گئے ہیں۔ کابلی صاحب ناراض ہو جائینگے اگر میں کچھ کہوں تو۔ اس لئے میری گذارش یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے ریلیف دیں کیوں کہ وہ ریلیف تو غریب لوگوں کے لئے ہے جو کہ اینٹائرلی بھیڑ بکریوں

ments have asked for and what have been the amounts sanctioned by the Central Government to the State Governments concerned. But it is the unanimous opinion of the people of the affected States that the assistance given is meagre and thoroughly inadequate. The bandhs in three States, Orissa, Bihar and Kerala, demonstrate the popular feelings about the attitude of the Government of India in the matter of giving proper aid to the States concerned.

Another very important feature s involved in this. Whatever little amount has been given by the Centre to the States has been in the form of an advance against Plan assistance which means no assistance at all, which means a cut-back of the Plan, and if you cut back the Plan, what remains of development ? This is no relief at all, no assistance...

MR. DEPUTY-SPEAKER : It is because of advance Plan amount, the Central Government is careful not to give more.

SHRI CHITTA BASU : It is no help. So far as last year and this year are concerned, according to the Minister's statement, about Rs. 739 crores have been given as drought assistance against Plan assistance for that State. That means that there has already been a cut of Rs. 750 crores to the State plans. This is the net result. My amendment is that in the form of advance against plan assistance these assistances are given. But they should be given in the shape of grants.

I now come to the question of availability of foodgrains. Members from Kerala have demanded a certain amount just to maintain the existing public distribution system. West Bengal Government has given a figure which is necessary only for maintenance of the existing public distribution system. Other States have also given. The question is not of expansion. The question is to maintain the existing public distribution system and whatever is allotted, does not physically reach the place. I have got the figures. Therefore, in my amendment I have suggested that adequate foodgrains for the maintenance of the public distribution system should be made physically available and not simply allocation...

PROF. MADHU DANDAVATE : Not merely morally.

SHRI CHITTA BASU : My charge is that it may be on paper but it is not physically made available. So my demand is ; allot adequately and adequately make available physically.

My fourth point is that my hon friend from Kashmir has raised a very important question that for distribution of relief there should be all-Party committees at State level. There should be a monitoring agency to look over the relief operations. The Minister of Agriculture (RAO BIRENDRA SINGH): Has it been done in West Bengal ?

SHRI CHITTA BASU : There are.

PROF. SATYASADHAN CHAKRABORTY (Calcutta South) : In spite of the fact that you do not believe your party people, there are Congressmen there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If any State wants an all Party committee, has the Centre objected to it ?

SHRI CHITTA BASU : But the States are not doing it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Has the Centre objected to it ?

SHRI CHITTA BASU : It is for them.

MR. DEPUTY-SPEAKER : They have not objected.

SHRI RAM PYARE PANIKA (Robertsganj) : They themselves will not agree because they wish to exploit the situation.

SHRI CHITTA BASU : The last point and that point is regarding the NREP programme. Time you will not allow me, otherwise I will have proved that there has been a systematic cut of the NREP programme in almost all the drought-affected States. If you permit me, I have enough facts to prove...

PROF. MADHU DANDAVATE : Lay it on the Table.

SHRI CHITTA BASU : It is already with the Government. I say nothing new. I say it from the government publication.

The last point. I will request the Irrigation Minister because he is present. Will you kindly look into your files and papers ? There have been 48 to 50 projects whose cost escalation has amounted to as much as 50% because of the inordinate delay in executing them. Does he also know—I think he knows– that even the target of the Sixth Five Year Plan for providing 5.6 million acres of additional irrigation potential during the last 2.3 years could not be achieved. Since this is the penultimate year of the Sixth Five Year Plan, the prospect is bleak, that the Sixth Five Year Plan target in terms of irrigation potential cannot be reached.

Having regard to this, would the hon. Minister take this position to accept these amendments, and particularly, look into the Irrigation Department's activities so as to see that the Sixth Five Year Plan target is achieved ?

Sir, the whole House will support him if he demands financial resources from the Planning Commission as well as from the Ministry of Finance. I would give my support to that.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Hon. Members, I have already informed that the Minister will reply at about 7 P.M. Now it is 7-45 P.M. There are six hon. Members — four from the ruling party and two from the Opposition. I shall give the chance to all. I would make an appeal to you that each one of you will not take more than five minutes. Then the Minister will be able to reply at 8 O'Clock. I do not want any speech but I want your cooperation. Shri Dabhi. You will not take more than five minutes.

SHRI AJIT SINH DABHI (Kaira) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, in Gujarat for the last few years, Saurashtra region and its people have been repeatedly victims of the vagaries of the weather. The 1979 tragedy of overflooded Machhua Dam which swept away to death more than 1500 men, women and children and to which horrible scene to which even the American Satellite system was a witness, still haunts the memory of Indian people. The whole industrial city of Morvi was practically destroyed. Property—private and public—worth Rs. 250 crores was destroyed.

Hardly had Gujarat come out of that terrible shock of Machhua Dam calamity, last November, i.e., in 1982, last year, we witnessed an unprecedented devastating cyclone moving at a speed of more than 100 k.m. per hour, hit Saurashtra. Whirling round the low pressure belt over Saurashtra, this cyclone caused the death of more than 500 men, women and children. Thousands of cattle, the sources of livelihood of small and marginal farmers and herdsmen were destroyed. Thousands of houses were destroyed rendering thousands of people homeless. Crores of rupees worth of property was lost.

Barely nine months have passed after the cyclonic calamity, Saurashtra has again become a prey to Nature's fury. More than total rain of the whole season, it poured down in only 2 days. Sir, it rained not cats and dogs. Neither it rained cows and bullocks but as one local journalist described it, it rained camels and elephants. Hard and stony land of Saurashtra could not absorb and contain the waters of the torrential rain, causing unprecedented flash floods. About 30 river dams were overflooded causing horrible deluge. The flood waters swept away to death hundreds of men, women and children.

Sir, the official survey of the damage caused by the heavy rain and flash floods is not finalised by the Gujarat Government, But, the *ad hoc* official figures say that 561 men, women and children have lost their lives. 70,445 catle, buffaloes, bullocks and other milch cattle are destroyed. This is a big blow to the small and marginal farmers as these cattle were their source of livelihood.

26,597 huts have been either washed away or destroyed completely and 75,325 huts are partially or wholly damaged. 13,586 buildings are destroyed completely and 30,549 buildings are damaged. Thousands of people have become shelterless. Damage to the crop is estimated to be more than Rs. 12 crores. This is over and above 1,00,000 hectares of arable land which is lost because layers of sand brought by the floods have got deposited on the land. It is estimated that 10 lakhs of people are affected by these flash floods in Saurashtra.

Sir, damage to public properties like roads, sea ports, irrigation system, river

dams, electric supply systems and electric poles, tele-communication system, water supply systems, buildings of municipalities, Nagarpanchayats and village panchayats which have fallen down has not still been finally surveyed. But, Sir, the Hon. Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi, had visited the flood-stricken areas of Saurashtra on foot and in jeep and had taken an aerial survey of the deluge wrought by the floods. She was very much moved by the colossal damage wrought by this calamity and she told the pressmen and I quote :

> "The loss of human life and property is colossal. It requires national effort of rehabilitation of flood-stricken people of Saurashtra."

As the Prime Minister herself has said that the loss of life and property was colossal, hence the task of rehabilitation of thousands of people who have lost their property, who have been rendered homeless and who have been deprived of their means of livelihood is equally colossal.

Therefore, the Government of Gujarat alone cannot fulfil the gigantic task of rehabilitation of the thousands of flood stricken people of Saurashtra, because it is money that makes the mare go. This task requires huge economic assistance from the Central Government. Sir, under the instructions of the Prime Minister, the Central Government has already sanctioned Rs. 10 crores, but Sir, through you I appeal to all sections of this House to join me in exalting the Central Government agree to...

MR. DEPUTY-SPEAKER : The entire House is with you in this regard.

SHRI AJIT SINH DABHI : .. the Gujarat Chief Minister demand for immediate release of an advance loan by way of non-planned assistance of Rs. 25 crores for the gigantic task of rehabilitation of the flood-stricken people of Saurashtra.

Sir, as the motion presented to the House mentions long-term measures to meet such natural calamities, I have to make some suggestions to the Central Government.

As advance or timely information of floods can save lives of people and their cattle wealth, micro-wave links and wireless communication system must be improved and strengthened in Saurashtra. Microwave system joining Saurashtra with Gandhinagar, the Capital of Gujarat, should be immediately established. The Central Government must immediately provide 200 wireless sets to be installed on dams of rivers which are prone to flash floods. Sir, we welcome the Central Government's decision to instal radar at Bhuj in Gujarat so that coming cyclone can be identified in advance and warning can be given to the people in advance. But, Sir, I would request the Government to implement this particular decision urgently because by this time Saurashtra has been identified as the area where the low pressure belt is frequently formed causing cyclone and thereby causing colossal damage to Saurashtra.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : भारत सरकार की तरफ से फ्लड और फैमीन में जो मदद की जाती है वह वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन हम को एक शिकायत है। भारत सरकार वैस्ट बंगाल को ज्यादा पैसा देती है, जो हमारे विरोधी हैं उनको ज्यादा पैसा देती है और हम जो उनकी पार्टी के आदमी हैं, उनको कम। रात-दिन ये आपके साथ झगड़ा करते रहते हैं। ये कहते रहते हैं कि भारत सरकार ने हमारी पूरी मदद नही की। उलटा काम हो रहा है। सब से ज्यादा पैसा इनको ही मिला है। इनकी शिकायत बनी रही है कि इनको ज्यादा पैसा नहीं मिला, कम मिला। सब से ज्यादा अकाल राजस्थान में पड़ा है। राजस्थान के लोगों के पास खाने को नहीं, पीने को पानी नहीं, जानवरों के लिए घास नहीं, काम की व्यवस्था नहीं। फिर भी सब से ज्यादा पैसा वैस्ट बंगाल को और सब से कम राजस्थान को। इस पर भी ये आपके गुण नहीं गाते। हमें देंगे तो हम रात दिन आपके गुण गाएंगे। आप बचिये इन लोगों से। जो आपकी व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले लोग हैं उनकी आप ज्यादा मदद कीजिये और जो रात दिन निन्दा

करने वाले हैं उनकी मदद करने से कोई विशेष लाभ नहीं ।

आपका काम बहुत अच्छा है । फैमिन में आपने खूब पैसा दिया है । मुझे कोई शिकायत नहीं है । अगर कोई शिकायत करता है तो गलत करता है कि भारत सरकार ने पैसा कम दिया । शिकायत है तो यह कि जो पैसा दिया वह ठीक से खर्च हुआ या नहीं, इस को आप नहीं देखते हैं । आप अपनी व्यवस्था को मजबूत बनाइये । मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । पिछले साल हमारे यहां मजदूरों को एक डेढ़ रुपया मिला । इस साल आपने राज्य सरकार के कान अमेठे होंगे, साढ़े चार रुपये मिल गए । आपने तय कर रखा है कि सात रुपये मिलने चाहिये । अगर सात नहीं तो पांच तो मिलने ही चाहिये । लेकिन पांच भी नहीं मिलते हैं मजदूरी को । इसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है । जिन्होंने पांच रुपये के हिसाब से पेमेंट नहीं दिया है उनके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये । पांच रुपये पूरे दिलवाने चाहियें ।

राव वीरेन्द्र सिंह : पांच के हिसाब से राजस्थान को पैसे दिए है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यही शिकायत है कि पांच रुपये मजदूरी नहीं दी गई । इसके बारे में आप को कुछ करना चाहिये ।

फ्लड्ज में भी आपने बहुत पैसा दिया है, कोई शिकायत नहीं है । इसके लिए हमें भारत सरकार की तारीफ करनी चाहिये । लेकिन फ्लड का पैसा कहां कहां लगा इसको आपको देखना चाहिये । 1981 में आपने 25 करोड़ रुपया दिया ताकि पुलियां बनें, सड़कें बनें । लेकिन एक ही बारिश में जैसे मिट्टी ढह जाती है पानी आते ही उस प्रकार से सारी पुलियां बह गई । कम से कम आप मानिटर तो करिये । जितना पैसा देते हैं वह पैसा वाजिब खर्च होता है इसको तो आप देखें, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है इस को तो आप देखें । गलत काम जहां भी हो रहा है उसको रोकने की नितान्त आवश्यकता है । मानिटरिंग की आपके यहां व्यवस्था नहीं है । आपका विभाग केवल टीम तो भेज देता है जहां जहां फ्लड आते हैं और आप उसकी सिफारिशों के आधार पर पैसा भी दे देते हैं लेकिन उस पैसे का खर्च ठीक हो रहा है या नहीं, इसकी आपके यहां व्यवस्था नहीं है । 900 करोड़ रुपया इस साल आपने दिया । यह सब ठीक तरीके से खर्च हुआ या नहीं, मजदूरों को ठीक मजदूरी मिली या नहीं, यह आपको देखना चाहिये । ये पैसे का दुरुपयोग भी करते रहेंगे और आपकी निन्दा भी करते रहेंगे । इस ओर आप विशेष ध्यान दें ।

अब मैं दो शब्द राजस्थान कैनाल और फ्लड्ज के बारे में कहना चाहता हूं । हमारे यहां दो फ्लड्ज बहुत जबर्दस्त आते हैं । एक घग्घर का जिस को आप अभी तक रोक नहीं पाए हैं और दूसरा भरतपुर कामा का । दोनों बहुत ज्यादा एरिया को बरबाद करते है । खुशी की बात है कि आपने राजस्थान कैनाल को योजना बनाई । राजस्थान कैनाल पर जहां 65 करोड़ का बजट था और उस में उसको पूरा होना था वहां उस पर पांच सौ करोड़ लग चुका है और अभी तक भी वह पूरी नहीं हुई है । जो लोग गड़बड़ कर गए हैं उनके खिलाफ राम सिंह कमिशन बिठाया गया । उसने जांच की कि दो सौ करोड़ इंजीनियर्ज खा गए हैं । आपको इंजीनियर्ज के खिलाफ कार्यवाई करनी चाहिये थी जिन्होंने दो सौ करोड़ की गड़बड़ की । बड़े बड़े इंजीनियर्ज को आपने छोड़ दिया और बेचारे छोटों को पकड़ लिया । आपने चीफ इंजीनियर्स, सुपरिन्टैंडिंग इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही की । ये सब ऐसे ही हैं ।

हमारे यहां पीने का पानी नहीं है । मेरी आपसे शिकायत है कि 100 में से 75 हैंडपम्प आज बिना पानी के पड़े हैं । लोगों ने पूरे हैंडपम्प खोदे नहीं, पैसा खा लिया और करोड़ों

रुपये की इस तरह से गड़बड़ हो गई। 20 सूत्री कार्यक्रम में पीने के पानी की व्यवस्था कराने की बात है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसकी व्यवस्था कराई जाये। यह अभी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, इसकी आप जांच करायें।

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह बहुत ही सामयिक और गंभीर है। जो प्रस्ताव हमारे शास्त्री जी लाये हैं, मुझे खुशी है कि इधर से और उधर से दोनों पक्षों की ओर से इस पर बहुत ही रचनात्मक सुझाव आये हैं। मैं उन रचनात्मक सुझावों के साथ अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

गम्भीरता उस समय आ जाती है जब कि 5 करोड़ हैक्टेयर भूमि सूखे से प्रभावित हो जाती है। बाढ़ और तूफान से एक नहीं करोड़ों भारतवर्ष के किसान प्रभावित हुए हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित उत्तरप्रदेश की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

उत्तरप्रदेश में पिछले वर्ष ओले से 49 जिले, सूखे से 46 जिले, बाढ़ से 44 जिले और शीतलहरी से प्रदेश के समस्त जिले प्रभावित हुए। हमारे मिर्जापुर जिले में वर्ष 1978-79 में जनपद के उत्तरांचल में भीषण बाढ़ आई। वर्ष 79-80 में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। अभी दो वर्ष भी नहीं बीते कि 1981-82 में जनपद के 1742 गांवों में भीषण सूखा पड़ा। इसी फरवरी में 3059 गांवों में भयंकर ओला वृष्टि हुई। 1356 गांव ऐसे थे जिनमें खरीफ में सूखे और रबी में ओले की दोहरी मार पड़ी। 237 गांव को छोड़कर शेष समस्त गांवों में ओला पड़ा और उससे क्षति 50 से 100 प्रतिशत तक रही परिणामस्वरूप जनपद में व्यापक असर पड़ा।

जो हमारी सैंट्रल सहायता मिली, हो सकता है हमारी प्रदेश सरकार ने कोई टैक्नीकल गलती की हो, लेकिन उसने गलती भी नहीं की, 31-7-82 को उस ने आपसे 164.97 करोड़ रुपया मांगा, लेकिन आपने उसे अस्वीकार कर दिया। जब कि इस साल देश में जो सूखा और ओला पड़ा था, आपने 700, 900 करोड़ रुपया दिया। हम आपके आभारी हैं, लेकिन उत्तरप्रदेश के साथ पक्षपातपूर्ण कार्यवाही हो गई। बाढ़ में जहां हमारी क्षति हुई 342.67 करोड़ की वहां आपने 66.82 करोड़ 3, 4 महीने के बाद दिया। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप ऐसी कोई प्रणाली बनावें कि देश में सूखा हो तो सैंट्रल गवर्नमेंट का एक सैल हो जो बगैर इस बात की चिन्ता किये कि किस स्टेट को समय से सहायता दिया, आप हिन्दुस्तान के सभी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित लोगों को समान रूप से सहायता दें।

जो दीर्घकालिक सुझाव आये हैं, 1980 में इंडियन फारेस्ट एक्ट में इन्होंने अमैंडमैंड कर दिया, इंडियन फारेस्ट एक्ट में इस संशोधन के कारण देश में सब सिंचाई परियोजनाएं, चाहे वह डी पी ए पी हो, सूखे इलाके में बिजली लगाने की योजना हो, या सड़क-निर्माण, पुल-पुलिया और बंदियां बनाने की योजना हो, रुक गई हैं। सूखे का विषय भी मन्त्री महोदय के पास है और जंगल विभाग भी उनके पास है। इस लिए यह आवश्यक है कि उस संशोधन को जल्दी वापस लिया जाए। अगर इसमें देर की जाएगी, तो उन योजनाओं की लागत बढ़ जाएगी और जनता को लाभ नहीं होगा।

सिंचाई मंत्री से मैं कहना चाहता हूं कि नदियों के पानी के जितने डिसूपट्स हैं, वह उनको जल्दी से जल्दी समाप्त कराएं।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में डी पी ए पी के ब्लाक्स घटाने शुरू कर दिए गए हैं। मिर्जापुर में दो ब्लाक घटा दिए गए हैं। इसके कारण वहां पर पहाड़ी ब्लाक में सिंचाई की गंगा लिफ्ट योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। मन्त्री महोदय इस पर एक बार पुनः विचार करें और

सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में उन योजनाओं को लागू करें।

माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने इस प्रस्ताव में एक 5-सूत्री संशोधन दिया है। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रधान मंत्री के 12-सूत्री कार्यक्रम में वह शामिल है। प्रधान मंत्री ने सूखे से बचने के लिए एक कार्यक्रम राज्यों को दिया है, लेकिन दुख की बात है कि बार-बार चिट्ठी लिखने पर भी राज्य सरकारें उसको कार्यान्वित नहीं कर रही हैं। जो राज्य सूखे या बाढ़ से प्रभावित हैं, उनके सहायतार्थ पुनः प्रधान मन्त्री के 12-सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जाए।

मिर्जापुर से शेरपुर तक गंगा नदी के किनारे पर जितने गांव हैं, उनको कटने से बचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि बाढ़ का असर उन पर न पड़े।

फेमिन कोड न जाने कब का बना हुआ है। तब से आज तक कितने परिवर्तन हो गए हैं और जमाना कितना आगे बढ़ गया है। मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह फेमिन कोड में आवश्यक संशोधन करें, क्योंकि यह समय की आवश्यकता है।

जहां तक एन आर ई पी का सम्बन्ध है, नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल ने कहा है कि 50 प्रतिशत स्टेट्स कांट्रीब्यूट करें। नतीजा यह है कि सेन्टर जो पैसा भेजा जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट्स उसका उपयोग नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। जो स्टेट्स डेफिसिट में हैं, जिन्होंने ओवरड्राफ्ट लिए हुए हैं, उनसे एन आर ई पी में 50 प्रतिशत देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मेरी मांग है कि इस में परिवर्तन किया जाए और सूखे तथा बाढ़ के समय इसमें ढिलाई की जाए और केन्द्र से शत-प्रति-शत सहायता दी जाए। इस बात पर ध्यान न दिया जाए कि किस राज्य सरकार ने हिसाब नहीं दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार हिसाब देखती रहे और पब्लिक भूखी मरती रहे।

जब हमने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रयास किया है और कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी फिक्स कर दी है, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि बाढ़ और सूखा से सम्बन्धित कार्यों में भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दी जाए। अभी इस बारे में राजस्थान के मित्र ने शिकायत की है। क्वान्टिटी के नाम पर मजदूरों को कम मजदूरी दी जाती है।

बाढ़ से प्रभावित हरिजन-आदिवासियों को घर बनाने के लिए 200 रुपए की सहायता दी जाती है। क्या 200 रुपए में घन बनता है? बाढ़ से पीड़ित लोगों की भरपूर सहायता की जाए, जिससे हरिजन और गरीबी की रेखा से नीचे के सभी जातियां और बिरादरियों के लोग कम से कम घर तो बना सकें।

जब सूखे या बाढ़ जैसी विपत्ति आती है, तो असामाजिक तत्वों चाहे वे सरकार के भ्रष्ट लोग हों और चाहे सेवा के नाम पर गांवों में घूमने वाले दलाल हों, की बन आती है। अभी माननीय सदस्य ने एक अच्छा सुझाव दिया है, कि सरकार जो 900 करोड़ रुपए की सहायता देती है, उसमें से दस बीस करोड़ रुपए यह देखने के लिए खर्च किए जाएं कि उस रुपए का प्रयोग उचित हो रहा है या नहीं। आप सेन्टर में ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक सेल तैयार करें जो इस बात को देखें कि जो रुपया आप दे रहे हैं उसका सही ढंग से उपयोग हो रहा है या नहीं। एन आर ई पी में आप पैसा नहीं दे रहे हैं लेकिन इसमें आप अपनी तरफ से पूरा पैसा देकर काम शुरू करें क्योंकि इसमें लोगों की जान व माल के आरक्षण का प्रश्न है।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश पर विशेष ध्यान रखेंगे जोकि इस देश में सबसे अधिक सूखे और बाढ़ से प्रभावित रहा है तथा इस बात पर ध्यान नहीं

देंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई टैक्निकल बात की है क्योंकि वहां पर हमारे एक्सपर्ट्स गए थे और उन्होंने सारी चीजें देख ली हैं, वे इस बात को महसूस करते हैं कि देना चाहिए इसलिए कोई कारण नहीं है कि आप न दें।

*SHRI S. T. K. JAKKAYAN (Periakulam): Mr. Deputy Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me an opportunity to say a few words on behalf of my party the All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam on the Resolution about Floods and Drought in the country.

Sir, Tamil Nadu is reeling under an unprecedented drought and all the districts in the State are facing the distress of drought. It is feared that the drought conditions may lead to famine in the State. The loss to crops is estimated to be of the order of several crores of rupees. Here I would like to suggest that the ad hoc money for undertaking drought relief measures should not be adjusted towards annual plan allocations for the State. This adjustment upsets the plan schemes of the State. This is also contrary to financial ethics. There should be a separate fund for drought relief assistance. The only the States can find out a lasting solution for this recuvrring natural calamity.

In the South there is drought and in the North there is flood. The annual loss on account of drought and floods according to governmental statistics is of the order of Rs. 1800 crores. During the past 35 years the cumulative loss due to floods and drought is estimated to be Rs. 28,000 crores.

The Centre sends a special team of officials to drought afflicted States. They visit some places here and there and submit their report to the Government here on the basis of which drought relief assistance is given to the concerned State, I am sorry to say that the report of the Central team is not based on correct assessment. The Central Government should be guided in this by the report of the popularly elected State Goverments. Why should not the Centre extend its financial assistance on the basis of reports from thet State Government? If it is found necessary, then the local M. Ps and M.L. As may be associated in the preparation of such reports. Then only the people undergoing untold miseries will get substantial relief.

My hon. friend Thiru M. Kandaswamy in his speech stated that the Government of Tamil Nadu headed by Puratchi Thalaivar Thiru MGR has failed to take adequate steps to tackle the drought in the State. This is not a realistic appreciation of the facts. My puratchi Thalaivar's Government has initiated intensive efforts on a war footing to give immediate relief and assistance to the people of Tamil Nadu afflicted by drought. I am sure that the Central Government will vouchsafe my claims in this regard.

There is only one permanent solution to avert the recurring floods in the North and the recurring drought in South and that is linking of Ganges with Cauvery. In a letter to a former Member of Parliament in Tamil Nadu our Prime Minister had stated that this Ganges-Cauvery linkup scheme is under the consideration of the Central Government. I would like to know what is the stage of this consideration and when it will be taken up for implementation.

Now, Puratchi Thalaivar's Government in Tamil Nadu is implementing the Telugu Ganga scheme for the purpose of providing drinking water to the people of Madras. Both the States of Tamil Nadu and Andhra Pradesh are facing financial constrains. I demand that the Centre should secure World Bank loan for this project. The Centre should also come forth to extend necessary funds for this project for the good of the people of Madras.

Krishna river can be linked with Godavari, then Godavari with Narmada and Narmada with Ganges—in this way the Ganga-Cauvery scheme can be implemented in stages. I am sure that our prime Minister will take personal interest in this scheme of national importance.

Sir, the Irrigation Commission in 1972 had recommended the use of the waters of

*The original speech was delivered in Tamil.

west-flowing rivers in Tamil Nadu so that the perennially drought afflicted districts of Ramanathapuram and Madurai, particularly Andipatti, Sedapatti, Bodi, will get water for irrigation. The Central Planning Commission has also appointed a technical team to study the feasibility of this project. The Report of this Committee is with the planning Commission. Besides the report of an Expert Committee constituted by the Irrigation Ministry to assess the possibilities of this scheme is also available to the Government. I would like to know what action has been taken on the recommendations contained in the Reports of these two Technical Committees. If this scheme is implemented by diverting the waters of west-flowing rivers, then as I said just now, Andipatti, Sedapatti, and Bodi in Madurai District and Ramanathapuram district which are regular drought afflicted areas will get water for agriculture.

Sir, the hon, Minister of Irrigation, Shri Mirdha, visited the Periyar reservoir in Thekkadi. I am sure that during this visit he would have made a personal assessment about the extent of water to be retained in this reservoir so that the people of My Periakulam constituency can get uninterrupted supply of water for irrigation. Before I conclude, I would appeal to him that he should ensure that Periakulam reservor retains the prescribed level of water for the purpose I have stated above. During drought, greater emphasis must be paid for road-laying works. A national crop insurance scheme should also be introduced because the floods and drought are natural calamities. There should also be a comprehensive. insurance scheme for the cattle. The *bundhs* of rivers should be raised to control the flood havoc. Some Six years ago there was some announcement about the constitution of Cauvery Valley authority. Till today it has not been constituted. Immediate steps should be taken in this regard by the Centre, The Centre should also help in the resolution of Cauvery water dispute in the interest of the people of Tamil Nadu. Sir, the power generated in Kalpakkam Atomic plant should be exclusively supplied to Tamil Nadu so that all the pumpsets in the State get power for drawing water from the wells. The State of Tamil Nadu can legitimately stake its claim for all the power generated in the Atomic Plant because the Government of the State has not only given 1000 acres of land but also all other concomitant needs for the setting up this prestigious project.

Sir, I would conclude my speech by emphasising the need for taking all the necessary steps to minimise the loss on account of floods and drought and to maximise the use of available waters in the country for agriculture.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1982-83 का अकाल जिस भीषणता को लिए हुए है, वह इतिहास में अपने आप एक चीज है। जो अकथनीय है, अवर्णित है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि भारत के इतिहास में अब तक कभी भी 26 करोड़ एक लाख व्यक्ति अकाल से और 15 राज्यों में कभी भी अकाल से ग्रसित नहीं हुए, जितने कि 1982-83 में हुए।

मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ऐसे संकट काल का मुकाबला करने के लिए केवल तभी शासन व्यवस्था सक्षम हो सकती है और उन परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं, जबकि शासन के पास या नेता के पास पोलिटिकल बिल हो। पोलिटिकल बिल के आधार पर ही केवल इस तरह के संकट को जो कि दूरगामी संकट है, उनको किसी तरह से पार किया जा सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से हमारे देश की प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार राजस्थान के अन्दर सुदूरवर्ती पश्चिम क्षेत्रों में, जहां पर कि दिन में आदमी जाते हुए हिम्मत नहीं कर सकता था सूखे में, जहां पर इस तरह की गर्मी और धूप थी, वहां पर हमारी प्रधान मंत्री जी ने जाकर लोगों का हौसला बढ़ाया है। वह स्थान जहां पर कि औरत, आदमी और बच्चे पानी के लिए तरसते थे। उन लोगों को कम्बल दिया, सहारा दिया। संकट के समय में केवल आर्थिक सहायता या खाद्यान्न की सहायता ही नहीं, अपने आप में हौसला और हिम्मत भी

ऐसी चीजें हैं जिन के द्वारा उस संकट को राष्ट्र पार कर सकता है। आज तक जितने अकाल इस देश में पड़े हैं और हम ने देखे हैं उन में चारे का अभाव था, अनाज का अभाव था लेकिन राजस्थान में जो अकाल पड़ा पूरे गांव को लगातार कई दिनों तक पीने का पानी नहीं मिला। वहां पीने के पानी के जितने स्रोत थे, जितने कुंए थे, गांव के आसपास पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं रही। जहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, उस से आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय सहायता और दूसरी सहायता दे कर किस तरह से उस संकट का मुकाबला किया। मैं केन्द्रीय सरकार, राजस्थान सरकार और साथ-ही-साथ राजस्थान के उन बहादुर लोगों को जो अकाल से ग्रसित रहे हैं, धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हिम्मत और हौसले से इस भीषण अकाल का मुकाबला किया।

आप को, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानकर ताज्जुब होगा कि राजस्थान की कुल पौने तीन करोड़ की आबादी में से पौने दो करोड़ लोग अकाल से ग्रसित थे, वहां पर 2 करोड़ 60 लाख पशुधन उस अकाल से झूझता रहा, लगातार एक-एक हफ्ते तक मवेशियों को पानी नहीं मिला। वहां के किसान अपने मवेशियों को लेकर मध्य प्रदेश और हरियाणा गये, दूसरी जगहों पर गये और अपने से अधिक उन मवेशियों को जीवित रखने का प्रयत्न किया। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां पिछले पांच सालों से लगातार अकाल पड़ रहा है, इन पांच सालों में किस तरह से वहां के लोगों ने अकाल का मुकाबला किया, इस की आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि आप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और दूसरे इलाकों में जहां लगातार अकाल पड़ता रहा है, वहां जाकर हालात को देखें, उन की दयनीय अवस्था और दरिद्रता को देखें, तो महसूस नहीं करेंगे कि वास्तव में ये लोग भी आजाद हिन्दुस्तान के नागरिक हैं। मैं मंत्री महोदय आप की प्रशंसा किये बगैर नहीं रह सकता, जिस तरह से खुले दिल से आप ने राज्य की सहायता की है। 1982-83 में आप ने 436.36 करोड़ रुपये की सहायता दी। 1983 के चालू वर्ष में भी करीब 229.8 करोड़ की सहायता आप ने दी है। इस के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में जो स्पिल-ओवर वर्क थे उन के लिये भी 38.90 करोड़ की सहायता दी, जिन की सैंक्शन 1982 में ही आप ने दे दी थी इसलिये दोनों वित्तीय वर्षों में आप ने पूरी सहायता दी है।

लेकिन फिर भी कुछ इस तरह की शिकायतें हैं जिन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खास तौर से राजस्थान में आप को मालूम होगा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय किया है जो राजस्थान में मिनिमम वैजेज के बारे में है। मदन गंज—हरपुरा रोड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एशोशियेशन, अजमेर ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पैटीशन दायर की थी और उस में यह प्रार्थना की थी कि संविधान का आर्टीकल 14 जो कानून में समानता चाहता है उस के अधीन यह मांग की गई थी कि राजस्थान फैमीन रिलीफ वर्कस एक्जेम्पशन फ्रोम लेबर लाज एक्ट, 1954 असंवैधानिक है, संविधान की भावना के प्रतिकूल है, इस के साथ ही अवैध है। उपाध्यक्ष महोदय, आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में इस एक्ट में जो प्रावधान किये गये थे वे इस तरह के प्रावधान थे जो मजदूरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते थे। इस लिये सुप्रीम कोर्ट के दो जजों न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति पाठक ने निर्णय दिया कि यह जो कानून है यह असंवैधानिक है, अवैध है। ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ गया है कि वह मिनीमम वेजेज एक्ट के तहत उन को मजदूरी दे या जो फैमिन कोड है, जिस का इरादा यह था कि वह रोजगार देना चाहती है और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है और उस में यह जरूरी नहीं

है कि मिनीमम वेजेट एक्ट के अनुसार 9 या 10 रुपये प्रति दिन प्रति मजदूर को दिया जाए, उस के अनुसार उन को मजदूरी दे। उस में एक टेस्ट यह था, एक क्राइटीरियन यह था कि टास्क फोर्स का इतना काम जरूर होना चाहिए। अब राजस्थान सरकार के सामने यह पैसे का संकट है क्योंकि उन को उसी रेट से मदद दी जाती है जो कि रिलीफ वर्कस के लिए होती है। अब ये जो रिलीफ वर्कस खोले गये हैं, उन के लिए पैसा कहा से आए। अभी तक अप्रैल, मई और जून में फैमिन रिलीफ वर्कस के लिए राज्य सरकार को 31 करोड़ रुपये सैंक्शन्ड किये गये हैं जब कि वहां पर राज्य सरकार 54 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है और अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू किया जाता है, तो यह धनराशी और भी अधिक होगी। इसलिए मेरा आप से निवेदन यह है कि जो धनराशि राज्य सरकार 30 जून तक खर्च कर चुकी है, वह धनराशि उसे दी जाए, और उसकी मांग पूरी की जाए।

एक आखरी बात में पानी के बारे में खास तौर से कहना चाहता हूं। इस समय राजस्थान में 1982-83 में पीने के पानी का जो संकट आया है, उस का किसी तरह से मुकाबला नहीं किया जा सकता जब तक कि एक पर्मानेन्ट तरीके से इस तरह के रिसोर्सेज डेवलप न किये जाएं। मुझे खुशी है कि माननीय मन्त्री जी ने एक एक्शन प्लान तैयार किया है और इस के साथ साथ स्पोट पर जा कर, उस को चैक करने के लिए और उस को मोनीटर करने के लिए आप के महकमें ने जो योजना बनाई है, वह अपने आप में प्रशंसनीय है। यदि उस योजना को आप वास्तव में कार्यान्वित कर सकेंगे, तो जो पैसा आप पानी के लिए दे रहे हैं और दूसरे कामों के लिए दे रहे हैं, उस से आप एक पर्मानेन्ट स्रोत भी बना सकेंगे।

मैं इतना कह कर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने मिनीमम वेजेज एक्ट के बारे में किया है, उस को देखते हुए, जो पैसा राजस्थान सरकार ने मांगा है, उस की पूर्ति करने के लिए आप कष्ट करें।

SHRI UTTAM RATHOD (Hingoli): Mr. Deputy-Speaker, Sir, my hon. friend, Mr. Rajnath Sonkar Shastri, who brought forward this motion, as we are all aware, is famous for flooding issues during the zero hour and it is for the first time that he has canalised not only his energy but the energy of the whole House in the right direction. I thank him for that.

Most of the points have been made by my learned friends earlier. So, without going into all the details, I would speak something about Maharashtra floods which we had recently and also the drought that we had to face last year.

You are aware that this year in three districts of Konkan, we face heavy floods and nearly 20 people lost their lives, 2000 cattle heads were lost and the total loss that accrue was to the tune of Rs 20 crores. On this occasion, I would request the hon. Minister that he should sanction the amount that has been requestod by the Government of Maharashtra through their memorandum submitted to him last week. Generally, Mr. Rao Birendra Singh is in the habit of giving only 50 per cent of the amount that has been asked for. I would request him not to apply that criterion and give as much as possible to Maharashtra.

Both drought and flood are inter-linked. Had we tried to control floods earlier, I think, we would not have had so many droughts in our country. But, unfortunately, when actually the planning started we thought of taking up major projects in the most fertile areas. That is how Brahamaputra was completely neglected.

My friend Mr. Tarun Gogoi has earlier said much about Assam and Brahmaputra. You are aware that Brahmaputra is known as Lohit. Lohit in Assam means red which in dicates blood. Since 1974-75, when the Central Government has started giving for Brahmaputra floods 100% grant, the amount came to only Rs. 85 crores, not even one third of the amount that we spent on Asiad.

I would request the Hon. Minister that in the interest of that particular poor State, they should spend more amount and do something so that the floods of Brahmaputra can be controlled.

You will be surprised to know that in the 33rd year of our independence, we have formed a new Board called Brahmaputra Flood Control Board which has now recently started functioning. I hope that this Board will come out with a master plan soon and it will be executed soon.

While examining the Planning Department, we found that there were several projects which we have undertaken and which could not be completed for more than 20 years. As Mr. Chitta Basu has rightly pointed out, the cost escalation has gone beyond Rs. 800 lakhs. When we asked the Hon. Chairman of the CWPC or the Secretary, they said sometimes they had no steel. If they have steel, there was no cement. Such a thing should not happen in future.

If we are interested in irrigating the whole land and in controlling the floods, the only way is to develop the whole, basin, the whole valley and not to plug only the major rivers. For that, you will have to plug first the streamlet and then the tributary and then you can control the major river area. That is how you can irrigate the whole area. Not only that, you can also control the floods.

Silting is the biggest problem we are facing. We thought that Bhakra-Nangal will be silted completely after 150 years. But after 25 years, we find that Bhakra-Nangal has been silted to the tune of 27%. This is because we have tried to plug the main river and we have left all the streamlets and tributaries like that. Ultimately what happens ? Due to erosion, the whole thing comes and settles down near the barrage. If we are really interested in irrigation and flood control, we must change our policy and take to the policy of having dams on streamlets and then tributaries and then on main rivers.

I have only certain suggestions about longterm plan. One is what I have told just now. Secondly, DPAP programme. In Maharashtra, certain districts have been shown under DPAP programme. The Government of Maharashtra had appointed Sukthankar Committee and they suggested some more taluks. The Committee has kindly accepted. But to my surprise when I asked the list of the new DPAP taluks that were declared as drought-prone areas, I fonnd Osmanabad district missing from that. Prof. Madhu Dandavate will certify that Osmanabad is one of the areas in Maharashtra which does not have proper rainfall. So I would suggest that this particular district should be examined and it should be added and DPAP programme should be taken up seriously and it may be worked out efficiently.

Afforestation is the most important matter. Whatever forests we had, we are losing, as Mr. Prof, Narain Chand Parashar has said. But afforestation is more important now and I hope that with Rao Birendra Singh, this programme will be taken up with more enthusiasm.

I think that Mr. Rao Birendra Singh's name includes Indra who is responsible for rains and floods. I hope he would not do it in future.

Let Mr. Ram Niwas Mirdha's name be Jala Niwas Mirdha so that he may store water through percolation tanks, small tanks and medium tanks. If you construct these, the chances of floods will be reduced. If you go to Telangana, they do not have many floods. It does not have at least one tank. That is why, you will find that in Telengana we have very few floods. Whether you try to store water, the chances of floods are reduced. So, on this occasion I would pray to both of them to do their work properly and save us from disasters.

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY (Puri) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, my story is different. It is not drought alone that the State of Orissa suffers from ; it suffers from cyclone, flood, drought and tornado and you can imagine the difficulties and the distressing situation prevailing there. 67 per cent of the people in the State of Orissa are living below poverty line. Professor Madhu Dandavate was talking and my

friend from Kerala was talking ; they are coming from States where the per capita income is above the national average. But in the case of Orissa it is quite different ; 67 per cent of the people live below poverty line. It is not so today ; it is an area which has been suffering traditionally from natural calamities. During the freedom struggle, Gandhiji was personally looking after the relief works in Orissa and Thakkar Baba was being deputed to go round to supervise the relief works organized on behalf of the Congress Party itself and other relief organizations. My submission would be that Orissa needs special attention. The wages of the agricultural labourers prevailing in some areas are just Rs. 5 to Rs. 6. The price of rice is Rs. 4 and above, and the controlled rice supplied by the Government is completely inadequate. So, this is the background. You can imagine the difficulties and sufferings of the people. In those difficult days, number of people were thrown out of their hearth and home and they were taking shelter on national highways, culverts and bridges. The house construction assistance that was given was to the extent of Rs. 500 and that was only in cases where the damage were such that there was no trace of house at all. You can imagine the difficulties of the people. The assistance was Rs. 500 where there was no trace of house at all. If even three walls had been damaged, the assistance was to the extent of only Rs. 200. This was the house construction assistance that was being given. My submission to the Agriculture Minister is that Orissa requires a new strategy of relief. The famine code requires to be amended. A new vision of relief measures must be taken...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please try to conclude.

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY : There is one thing which is very important. This year the rabi crop in other States has grown well, but in Orissa a large part of the rabi crop was damaged on account of attack by pests, and the pesticide that was supplied did not work. I have raised this issue, and previously also this was being raised. My submission would be that the Agriculture Minister must personally intervene in the matter. Pesticides and insecticides that are sIpplied and used are not working. That has been the experience not only this year but for the last two or three years.

Another aspect is that wrong seeds were being supplied by the State Government. Large acres of land became non-productive on that account ; they said that wrong seeds were supplied. Imagine the predicament of the farmers. I have got the question-answer here. About 5,000 quintals of paddy seeds were wrongly supplied and they were non-yielding. So, you can imagine the devastation and the damage and the sufferings of the farmers.

One point more. This is about some technical matter. The Govermment never consider the ayacut areas of irrigation projects as a drought affected area. There are vast areas of this nature which forms parts of my constituency and which has been severely affected by drought. It has not been declared as a drought-affected area although the Revenue Department has reported that it has been affected to the extent of 80%. I would request the Agriculture Minister to take up the matter with the State Government to accept the realities of the situation.

Another aspect is about the flood control measures of Mahanadi basin. All the traditional ideas of flood control of Mahanadi now did not work. So my submission would be so far as Irrigation Minister is concerned that he should look into it and there should be a fresh investigation as to how they can control the flood in Mahanadi river and how to protect Puri, Balasore and Cuttack districts which are traditionally suffering from floods.

MR. DEPUTY-SPEAKER : When is the Minister to reply if you go on like this ?

SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY : With regard to devolution of federal finance, my submission would be that so far as natural calamities are concerned, it should be exclusively and entirely the responsibility of the Union Government. It should take over the entire financial responsibility particularly in States which are so backward. My submission would be that it should be totally taken up by the Union Government.

Than you very much.

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : आनरेबल चेयरमैन, आज जो यहां इतनी तफसील के साथ अपोजिशन और रूलिंग पार्टी की तरफ से बहस हुई, मेरे ख्याल में उससे मेरे उस अमैंडमैंट की हिमायत हुई है जिसका मकसद यह है कि जो करोड़ों रुपये का नुकसान सैलाव और सूखे की वजह से मुल्क को हो रहा है, उसके लिए उपाय ऐसे हो सकता है कि हम पीजेन्टरी को बचाने के लिये, जो किसानों की तबाही हर साल ड्राउट और फ्लड से होती है, उसका सामना इस तरह से हो सकता है कि क्राप्स की वाकायदगी के साथ इन्श्योरेंस की जाए ताकि जो हमारी 80 परसैंट पोपुलेशन विलेजेज में रहती है और तबाही का शिकार होती है, उसका कोई इलाज हो। यह इलाज इसी सूरत में हो सकता है कि इस मुल्क के हजारों लाखों किसानों की क्राप्स को नेशनलाइज किया जाये और इन्श्योरेंस किया जाये। यह बड़ी देरीना मांग है कि किसी भी नुकसान के सूरतेहाल में उसका मुआवजा उनको दिया जाये, यह सरकार की पालिसी होनी चाहिये।

जहां तक रियासत जम्मू-काश्मीर का ताल्लुक है, हमारी स्टेट पहाड़ी है और हिमालयन रेंज में पड़ती है और हमारी प्राब्लम मुख्तलिफ हैं। जो हमारे प्लेन्स हैं, मैदानी इलाका है वह साउथ इंडिया के इलाके से मुख्तलिफ है और उसी विनाह पर मैं कह सकता हूं कि काश्मीर और हिमाचल प्रदेश और शुमाली यू०पी० और बिहार का शुभोली हिस्सा और असम व नेफा के जो इलाके हैं, उनमें एक जैसी सूरतेहाल है, पर मैं यह कह सकता हूं कि इन जगहों में पानी के जो हमारे जरिये हैं वह वहीं से नदियां निकलती हैं। काश्मीर को यह इम्त्याज हासिल है कि सिन्धू, रावी, चिनाव, जेहलम और बाकी दरिया वहीं से निकलते हैं जो कि हमारे जूनवी इलाके, खासतौर से पंजाब व हरियाणा को बहुत फायदा देते हैं।

इस विनाह पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि मेरे ख्याल में इस मसले का हल इस तरीके से हो सकता है, यह सिर्फ इरिगेशन और रिलीफ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि इन्टर-कनैक्टेड है। हमें रिलीफ और इरिगेशन, इलैक्ट्रिसिटी और डिफरैंट डिपार्टमेंट इन्क्लूडिंग टूरिज्म को उसमें जोड़ना होगा, मिलाना होगा, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक ऐसा बड़ा मनसूबा बनाना होगा प्लान करनी होगी ताकि हम मुस्तकिल तौर पर सैलाव का मुकाबला कर सकें और सैलाव की तबाहियों को रोकने में कामयाब हो जायें।

अब जम्मू-काश्मीर स्टेट की बात लीजिए। जहां तक वैली, काश्मीर की घाटी, का ताल्लुक है, उसके बारे में कल्हण ने बहुत पहले संस्कृत में काश्मीर की जो तारीख लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि वह सतीसर है, पहले यह एक बहुत बड़ी झील थी और फिर इसमें से पानी रफूता रफूता बारामूला के पास बाहर निकला। अभी तक वही सूरतेहाल है। पानी एक ही तरफ से निकल रहा है और जब भी काश्मीर घाटी में सैलाव आता है, तो ऐसा आता है कि सारी फसल तबाह हो जाती है और लाखों लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है।

काश्मीर की बदकिस्मती यह है कि वहां काफी सर्दी पड़ती है और उसकी वजह से वहां पर सिर्फ एक ही फसल—रबी की फसल—होती है, खरीफ नहीं होती है, जबकि पंजाब और हरियाणा में दो दो फसलें होती हैं। जब काश्मीर में वह फसल तबाह हो जाती है, तो पूरे साल के लिए अकाल पड़ता है और हमें बहुत सालों तक मुसीबत बर्दाश्त करनी पड़ती है।

काश्मीर घाटी में इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशल बहुत है। वहां पर बजाते-खुद सैलाब एक मुसीबत ही नहीं, बल्कि स्टेट और पूरे हिन्दुस्तान के लिए एक बरकत साबित हो सकता है, अगर हम उस सारे पोटेंशन, उस सारी शक्ति, को इस्तेमाल करें, जो बिजली की सूरत में पैदा हो सकती है। वहां पर बड़े रेजरवायर को डेवेलप कर के बिजली पैदा की जा सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हम इस तरफ कोशिश करें, तो काश्मीर दस हजार मैगावाट बिजली तैयार कर सकता है, जो हम पूरे हिन्दुस्तान को दे सकते हैं और हिन्दुस्तान में पावर के सैन्टर में जो कमी है, हम उसको दूर करने में सहायता दे सकते हैं।

काश्मीर घाटी में यह सैलाब हर तीसरे चौथे साल आता है और उससे वहां पर जो बर्बादी लोगों को उठानी पड़ती है, उसकी कोई मिशाल नहीं मिलती। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी आटोबाइग्राफी में इसका जिक्र किया है कि काश्मीर को हजारों सालों से तबाही का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि काश्मीर एक कप की तरह है, जिसमें से पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, सिवाए एक रास्ते कि के जो कि जेहलम वैली रोड या बारामूला है। गवर्नमेंट को काश्मीर की घाटी में ऐसी प्राजेक्ट्स शुरू करनी चाहिए, जिससे वहां पर बिजली पैदा की जाए और रेजरवायर कायम किए जाएं।

दरख्त काटने और इरोजन के बारे में जो कहा गया है, मैं उससे पूरा इत्तिफाक करता हूं। करोड़ों रुपयों की जंगल की लकड़ी जम्मू-काश्मीर से बाहर जा रही है। जम्मू-कश्मीर एक बैकवर्ड स्टेट है। हमारे पास आमदनी के बहुत कम जरिये हैं। एक जरिया यह है कि जंगल काटे जाएं और लकड़ी को पंजाब और बाकी देश की मार्केट्स में बेचा जाए। अगर मरकजी सरकार वाकई चाहती है कि जंगल का कटाव खत्म हो और इरोजन न हो, तो उसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-काश्मीर जैसी बैकवर्ड स्टेट्स को मदद देनी चाहिए, ताकि वह उस लास को काम्पेन्सेट करे, जो जंगल की कटाई को कम करने से होगा, क्योंकि इन स्टेट्स को बहालते-मजबूरी जंगल काटने पड़ते हैं।

लद्दाख के सैक्टर में जब सिंध में बाढ़ आ जाती है, तो तबाही होती है। 1982 में वहां पर जो तबाही और बर्बादी हुई, अभी तक मरकजी सरकार ने सही मानों में उसके लिए मदद नहीं की है। यही हाल जम्मू का भी रहा है। इस बिना पर मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी स्टेट की बैकवर्डनेस को मद्दे-नजर रख कर वहां पर वाटर रेजरवायर कायम किए जाएं और पावर पोटेंशल का इस्तेमाल किया जाए। जैसे श्रीनगर में डल झील पर एक प्राजेक्ट बनाया जा सकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You mentioned the name of Ladakh. Has Mr. Namgyal permitted you ?

SHRI ABDUL RASHID KABULI : He only represents 50% in Ladakh and the other fifty per cent is represented by somebody else. For example, there are two M.L.A. one from Kargil and the other from Leh.

SHRI P. NAMGYAL : I represent the entire area.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : I also represent the area.

यहां पर डेजर्ट डेवेलपमेंट प्रोग्राम का जिक्र किया गया है। मुझे खुशी है और सरकार को खुशी है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने लेह को उसमें लिया है और जंस्कार को उसमें लिया है लेकिन अफसोस की बात यह है कि जहां लेह और जंस्कार को लिया गया, कारगिल जोकि लद्दाख का ही हिस्सा है उसको नहीं लिया गया। उसको किस बेसिस पर नहीं लिया गया ? क्या यह पोलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन था जिसकी वजह से डेवलपमेंट स्कीम के अन्दर उसको नहीं लिया गया ? मैं समझता हूं जब मर्कजी सरकार स्टेट्स को मदद करे तो किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही होम मिनिस्टर ने यहां पर कहा कि लद्दाख का जो ट्राइबल एरिया है उसको शामिल करने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि उसको शामिल करना चाहते हैं लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर सेन्टर को नहीं लिख रहे हैं

(**व्यवधान**)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमारा जो लद्दाख का सेक्टर है, उसके लिए मैं कह रहा हूं कि उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, रूलिंग पार्टी का एम.एल.ए. कहां से आया और अपोजिशन का एम.एल.ए. कहां से आया, यह नहीं देखना चाहिए। मर्कजी सरकार में मेरी गुजारिश है कि जम्मू-कश्मीर स्टेट को पार्टी पालिटिक्स की बेसिस पर मदद नहीं करनी चाहिए। लद्दाख के बारे में हमें शिकायत है, हमने बार बार प्रोटेस्ट की है कि आधे लद्दाख रीजन में डेजर्ट स्कीम को लिया गया लेकिन आधे में नहीं लिया गया। इसलिए मेरी जो अमेन्डमेन्ट है उस पर मैं जोर दे रहा हूं, जिसमें मैंने कहा है कि पार्लमेन्ट के आनरेबल मेम्बर्स और एक्सपर्ट्स पर मुश्तकिल एक कमेटी बनाई जाए जो इसमें प्रोब करे। इस वक्त जो ड्राउट और फ्लडस की प्राब्लम है, जिससे पूरा देश हर साल तबाही का शिकार हो रहा है, उसको देखते हुए मेरा सुझाव है कि मेम्बर्स आफ पार्लमेंट और एक्सपर्ट्स पर मबनी कमेटी बनाई जाए। वह कमेटी इस प्राब्लम को हल करने के लिए मेम्बर्स रेकमेंड करेगी जिसमें एक हल यह भी हो सकता है कि क्राप इन्श्योरेंस की स्कीम लागू की जाए। (इति)

شری عبدالرشید کابلی (سری نگر)

آنریبل چیئرمین - آج جو یہاں اتنی تفصیل کے ساتھ اپوزیشن اور رولنگ پارٹی کی طرف سے بحث ہوئی میرے

خیال میں اس سے میرے اس امینڈمینٹ کی حمایت ہوئی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کروڑوں روپے کا نقصان سیلاب اور سوکھے کی وجہ سے ملک کو ہو رہا ہے اس کے لئے اُپائے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم بھی جینٹری کو بچانے کے لئے جو کسانوں کی تباہی ہر سال ڈراؤٹ اور فلڈ سے ہوتی ہے، اس کا سامنا اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کراپس کی باقاعدگی کے ساتھ انشورینس کی جائے تاکہ جو ہماری ۸۰ پرسینٹ پاپولیشن دیہز [illegible] ہے اور تباہی کا شکار ہوتی ہے اس کا کوئی علاج ہو۔ یہ علاج اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس ملک کے ہزاروں لاکھوں کسانوں کی کراپس کو نیشنلائز کیا جائے اور انشورینس کیا جائے۔ یہ بڑی دیرینہ مانگ ہے کہ کسی بھی نقصان کی صورتِ حال میں اس کا معاوضہ ان کو دیا جائے یہ سرکار کی پالیسی ہونی چاہیے۔

دو دو فصلیں ہوتی ہیں۔ جب کشمیر میں وہ فصل تباہ ہو جاتی ہے تو پورے سال کے لئے اکال پڑتا ہے اور ہمیں بہت سالوں تک مصیبت برداشت کرنی پڑتی ہے۔

کشمیر گھاٹی میں الیکٹری سٹی کا پوٹینشیل بہت ہے۔ وہاں پر بذاتِ خود سیلاب ایک مصیبت ہی نہیں بلکہ اسٹیٹ اور پورے ہندوستان کے لئے ایک برکت ثابت ہو سکتا اگر ہم اس سارے پوٹینشیل اس ساری شکتی کو استعمال کریں جو بجلی کی صورت میں پیدا ہو سکتی ہے۔ وہاں پر بڑے ریزروائر کو ڈیولپ کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہم اس طرف کوشش کریں تو کشمیر دس ہزار میگاواٹ بجلی تیار کر سکتا ہے جو ہم پورے ہندوستان کو دے سکتے ہیں۔ اور ہندوستان میں پاور کے سیکٹر میں جو کمی ہے ہم اس کو دور کرنے میں سہایتا دے سکتے ہیں۔

کشمیر گھاٹی میں یہ سیلاب ہر تیسرے چوتھے سال آجاتا ہے اور اس سے وہاں پر جو بربادی لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے بھی اپنی آٹو بائیوگرافی میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کشمیر کو ہزاروں سالوں سے تباہی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیوں کہ کشمیر ایک کپ کی طرح ہے جس میں سے پانی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستے کے جو کہ جہلم ویلی روڈ یا بارہ مولہ ہے۔ گورنمنٹ کو کشمیر کی گھاٹی میں ایسی پروجیکٹس شروع کرنی چاہیئے جس سے وہاں پر بجلی پیدا کی جائے اور ریزروائر قائم کئے جائیں۔

درخت کاٹنے اور اروزن کے بارے میں جو کہا گیا ہے میں اس سے پورا اتفاق کرتا ہوں۔ کروڑوں روپوں کی جنگل کی لکڑی جموں کشمیر سے باہر جا رہی ہے۔ جموں کشمیر لیک بیک ورڈ اسٹیٹ ہے۔ ہمارے پاس آمدنی کے بہت کم ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ یہ ہے کہ جنگل کاٹے جائیں اور لکڑی کو پنجاب اور باقی دیش کی مارکیٹ میں بیچا جائے۔ اگر مرکزی سرکار واقعی چاہتی ہے کہ جنگل کا کٹاؤ ختم ہو اور اروزن نہ ہو تو اسے ہماچل پردیش اور جموں کشمیر جیسی بیک ورڈ اسٹیٹس کو مدد دینی چاہیئے تاکہ وہ اس لاس کو کمپنسیٹ کرے۔ جو جنگل

جہاں تک ریاست جموں کشمیر کا تعلق ہے ہماری اسٹیٹ پہاڑی ہے اور ہمالین رینج میں پڑتی ہے اور ہماری پرابلم مختلف ہیں جو ہمارے پلینس ہیں میدانی علاقہ ہے وہ ساؤتھ انڈیا کے علاقے سے مختلف ہے اور اسی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ کشمیر اور ہماچل پردیش اور شمالی یو۔پی اور بہار کا شمالی حصہ اور آسام اور نیفا کے جو علاقے ہیں ان میں ایک جیسی صورتِ حال ہے۔ پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان جگہوں میں پانی کے جو ہمارے ذریعہ ہے وہ وہیں سے ندیا نکلتی ہیں۔ کشمیر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ سندھو، راوی، چناب، جہلم اور باقی دریا وہیں سے نکلتے ہیں جو کہ ہمارے جنوبی علاقے خاص طور سے پنجاب اور ہریانہ کو بہت فائدہ دیتے ہیں۔

اس بنا پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سوال میں اس مسئلے کا حل اس طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ صرف اریگیشن اور ریلیف ڈیپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے بلکہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ ہمیں ریلیف اور اریگیشن الیکٹری سٹی اور ڈیفیرینٹ ڈیپارٹمنٹ انکلیوڈنگ ٹورزم کو اس میں جوڑنا ہوگا ملانا ہوگا اسٹرے ٹجی بنانی ہوگی ایک ایسا بڑا منصوبہ بنانا ہوگا پلان کرنی ہوگی تاکہ ہم مستقل طور پر سیلاب کا مقابلہ کر سکیں اور سیلاب کی تباہیوں کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں۔

اب جموں کشمیر اسٹیٹ کی بات لیجئے۔ جہاں تک ویلی کشمیر کی گھاٹی کا تعلق ہے اس کے بارے میں کلہن نے بہت پہلے سنسکرت میں کشمیر کی جو تاریخ لکھی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہے پہلے یہ ایک بہت بڑی جھیل تھی پھر اس میں سے پانی رفتہ رفتہ بارامولہ کے پاس باہر نکلا۔ ابھی تک وہی صورتِ حال ہے۔ پانی ایک ہی طرف سے نکل رہا ہے اور جب بھی کشمیر گھاٹی میں سیلاب آتا ہے تو ایسا آتا ہے کہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔

کشمیر کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں کافی سردی پڑتی ہے اور اس کی وجہ سے وہاں پر صرف ایک ہی فصل "ربیع کی فصل" ہوتی ہے خریف نہیں ہوتی ہے جب کہ پنجاب اور ہریانہ میں

کی کٹائی کو کم کرنے سے ہوگا کیونکہ ان اسٹیٹس کو بحالتِ مجبوری جنگل کاٹنے پڑتے ہیں۔

لدّاخ کے سیکٹر میں جب سنگھ میں باڑھ آجاتی ہے تو تباہی ہوتی ہے۔ سنہ ۱۹۸۲ء میں وہاں پر جو تباہی اور بربادی ہوئی ابھی تک مرکزی سرکار نے صحیح معنوں میں اس کے لئے مدد نہیں کی ہے۔ یہی حال جموں کا بھی رہا ہے۔ اس بنا پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹیٹ کی بیک ورڈنیس کو مدِنظر رکھ کر وہاں پر واٹر ریزروائر قائم کئے جائیں اور پاور پوٹینشل کا استعمال کیا جائے۔ جیسے سری نگر میں ڈل جھیل فرخ پروجیکٹ بنایا جا سکتا ہے۔

MR. DEPUTY-SPEAKER : You mentioned the name of Ladakh. Has Mr. Namgyal permitted you ?

SHRI ABDUL RASHID KABULI : He only represents 50% in Ladakh and the other fifty per cent is represented by somebody else. For example, there are two M.L.As.— One from Kargil and the other from Leh.

SHRI P. NAMGYAL : I represent the entire area.

SHRI ABDUL RASHID KABULI : I also represent the entire area.

یہاں پر ڈیزرٹ ڈیولپ مینٹ پروگرام کا ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے خوشی ہے اور سرکار کو خوشی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے لیہہ کو اس میں لیا ہے اور جنسکار کو اس میں لیا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں لیہہ اور جنسکار کو لیا گیا۔ کارگل جو کہ لدّاخ کا ہی حصّہ ہے اس کو نہیں لیا گیا۔

اس کو کس بیس پر نہیں لیا گیا۔ کیا یہ پولیٹکل ڈسکریمینیشن تھا جس کی وجہ سے ڈیولپمینٹ اسکیم کے اندر اس کو نہیں لیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں جب مرکزی سرکار اسٹیٹس کو مدد کرے تو کسی طرح کا کوئی ڈیسکریمینیشن نہیں ہونا چاہیئے۔

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, आज ही होम मिनिस्टर ने यहां पर कहा कि लद्दाख का जो ट्राइबल एरिया है उसको शामिल करने के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि उसको शामिल करना चाहते हैं लेकिन वहां से चीफ मिनिस्टर सेन्टर को नहीं लिख रहे हैं। (**व्यवधान**)

شری عبدالرشید کابلی

ہمارا جو لدّاخ کا سیکٹر ہے اس کے لئے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ڈسکریمینشن نہیں ہونا۔ رولنگ پارٹی کا ایم ایل اے کہاں سے آیا اور اپوزیشن کا ایم ایل اے کہاں سے آیا، یہ نہیں دیکھنا۔ مرکزی سرکار سے میری گذارش ہے کہ جموں کشمیر اسٹیٹ کو پارٹی پولیٹکس کی بیس پر نظر نہیں کرنی چاہیئے۔ لدّاخ کے بارے میں ہمیں شکایت ہے۔ ہم نے بار بار پروٹسٹ کی ہے کہ آدھے لدّاخ ریجن میں ڈیزرٹ اسکیم کو لیا گیا لیکن آدھے میں نہیں لیا گیا۔

اس لئے میرے جو امینڈمینٹ ہیں اس پر میں زور دے رہا ہوں جس میں میں نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آنرایبل ممبرس اور ایکسپرٹس پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو اس میں پروب کرے۔ اس وقت جو ڈرواٹ اور فلڈس کی پرابلمس ہیں جس میں پورا دیش ہر سال تباہی کا شکار ہو رہا ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے میرا سجھاؤ ہے کہ ممبرس آف پارلیمنٹ اور ایکسپرٹس پر مبنی کمیٹی بنائی جائے۔ یہ کمیٹی اس پرابلمس کو حل کرنے کے لئے میجرس ریکمنڈ کرے گی جس میں ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کراپ انشورینس کی اسکیم لاگو کی جائے۔

प्रो० सत्यदेव सिंह (छपरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मन्त्री जी

तथा माननीय सिंचाई मन्त्री जी यहां पर उपस्थित हैं। बिहार खनिज पदार्थों में सबसे धनी और सम्पन्न प्रदेश है फिर भी वह अत्यन्त निर्धन है। इसका कारण यह है कि प्रति वर्ष उत्तर बिहार भयंकर बाढ़ की चपेट में रहता है और दक्षिण बिहार सूखाग्रस्त रहता है जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई है।

जहां तक मेरे क्षेत्र छपरा संसदीय क्षेत्र का सम्बन्ध है, सारन जिले के दक्षिण में गंगा नदी है और गंगा के दक्षिणी तट पर भोजपुर जिले को बचाने के लिए बक्सर से कोइलवर तक तटबन्ध दिया गया है लेकिन गंगा के उत्तरी तट पर जो सारन जिला है, छपरा है, वहां पर तटबन्ध न देने से जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो वह सीधे उत्तर को मुड़ जाती है – नतीजा यह होता है कि सिवान से लेकर सोनपुर तक सारे का सारा क्षेत्र जो है वहां महासमुद्र सा दृश्य बन जाता है। गत वर्ष 23 सितम्बर को तत्कालीन सिंचाई मन्त्री, स्वर्गीय केदार पांडे जी सोनपुर से लेकर छपरा तक एक विशेष ट्रेन द्वारा गए थे और उन्होंने रेलवे लाइन के दोनों तरफ जो दृश्य देखा था उसको देखने के बाद छपरा की सार्वजनिक सभा में उन्होंने घोषणा की थी कि अगले वर्ष बाढ़ का यह दृश्य नहीं आयेगा और गंगा के ऊपरी तट पर सारन जिले को बचाने के लिए प्रबन्ध किया जायेगा। लेकिन हमारे केन्द्रीय मन्त्री अब नहीं रहे। भगवान ने उनको हमारे बीच से उठा लिया। आज वह उनका सपना, वह उनकी कल्पना और उनका आश्वासन उनके साथ चला गया। माननीय राम निवास मिर्धा जी आज यहां उनके पद पर हैं। उनके उस पद की गरिमा और वचन को कायम रखने के लिए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे छपरा चलें, वहां की स्थिति का जायजा लें। लेकिन अगली बार, क्योंकि इस बार तो भीषण बाढ़ आएगी और उससे कोई बचा नहीं सकता है। बाढ़ का इतना भयंकर प्रकोप होता है कि महीनों तक लोग छतों पर बैठे रहते हैं। पानी आ तो जाता है, लेकिन पानी को निकालने का कोई रास्ता नहीं है। महीनों तक हमारे खेतों में दस फीट तक पानी रहता है। गांव एक टापू के समान बन जाता है। पेयजल की समस्या पैदा हो जाती है और बीमारी फैलती है। बाढ़ का पानी पीते हैं और मवेशियों के लिए चारा तक नहीं मिलता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि इस वर्ष तो हम बाढ़ झेलेंगे, हमको कोई बचा नहीं सकता है, लेकिन इसके बाद बाढ़ का प्रकोप हमें प्रताड़ित न करे। इसके बाद आप हमें बाढ़ से बचायें, केवल हमारा वह तटबन्ध दे दें गंगा के उत्तरी किनारे पर, तो हम बच जायेंगे। नैनी चंवर के कार्य की कोई योजना बनी है, लेकिन जल निकासी की योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं हुई। पहले यह योजना पांच लाख की थी, लेकिन अब वह एक करोड़ से भी अधिक की योजना हो गई है। छपरा संसदीय क्षेत्र में दरियापुर प्रखण्ड, गरखा, दीघवारा, सोनपुर आदि प्रखण्डों को बाढ़ से बचाने के लिए माही, सुखमान, गोगरी नदियों पर तट बन्ध देना आवश्यक है। यह ठीक है कि इन छोटी-छोटी योजनाओं को पूरा करना राज्य सरकार का काम है, लेकिन ये काम पूरे नहीं हो रहे हैं। हमारे नए सिंचाई मन्त्री हैं और ईश्वर की दया से बिहार प्रदेश में भी नए सिंचाई मन्त्री बनेंगे, इस प्रकार दोनों नए सिंचाई मन्त्री नए काम को पूरा करें और नया बिहार बनायें। ...(**व्यवधान**)...उपाध्यक्ष महोदय, हमारी एक गंडक योजना है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डा० राजेन्द्र प्रसाद, की योजना थी। वह योजना सबसे सस्ती, सबसे कम खर्च में सबसे अधिक उपादेय योजना थी, आज वह गंडक योजना हमारे लिए अभिशाप बन गई है। पानी वर्षा का आता है, लेकिन उसके निकासी की योजना नहीं है। पानी वहां जम जाता है, नतीजा यह होता है कि हम खेतों में काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारा जिला हमारा प्रदेश गरीब है और बाढ़ और सूखे के चलते

वह आगे की ओर नहीं अग्रसर हो रहा है। हम श्रमिक भाई हरियाणा और पंजाब में जाते हैं। रोजी-रोटी के लिए बंगाल और असम में जाते हैं तथा देश के कोने-कोने में जाते हैं। हम परिश्रमी है। हम श्रम करना जानते हैं, लेकिन साधन-हीन हैं। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप हमें साधन दें जो आपके पास साधन हैं। माननीय मन्त्री जी आप रिलीफ के इन्चार्ज हैं... (व्यवधान)...मैं आपके माध्यम से माननीय राव बीरेन्द्र सिंह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो रिलीफ के लिए, सहायता के लिए, राशी दी जाती है, उस का सही उपयोग नहीं होता है। मैंने आपसे निवेदन किया था और शिकायत भी की थी कि सारे बिहार प्रदेश में सबसे अधिक तबाह और परेशान जिला छपरा जिला है। जो राशि आपने वहां के लिए आवंटित की थी, वह वहां के लोगों को नहीं मिल सकी। बिहार प्रदेश की सरकार, बिहार प्रदेश के मन्त्री और बिहार प्रदेश की सरकार के अधिकारियों ने ऐसा गोलमाल किया कि सारा धन समानता के आधार पर बांट दिया। चाहें कहीं बर्बादी हो या न हो, जिससे हमको क्षति होती है और परेशानी होती है। गरीब लोग अन्न न मिलने की वजह से, दवा-दारू न मिलने की वजह से, भोजन न मिलने की वजह से मर जाते हैं। मवेशियों की जानें चली जाती हैं। भगवान न करें कि इस साल बाढ़ आए, यदि कहीं आ जाए, तो ऐसी हालत में हमारा जिला जो कि हर साल प्रभावित होता है, अगर इसके लायक समझें, आपकी सहायता और दया का पात्र हो, तो उसको वाजिब हक दिलाने की कृपा करें। आप यहां से दल भेजते हैं और वहां से प्रतिवेदन आता है, लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं होता है। इसलिए मेरा आपके निवेदन है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारी वहां जायें, जो निष्पक्ष होते हैं, जो ईमानदार और निष्ठावान होते हैं, वे वहां जाकर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रखें। जहां जिस को जितना मिलना चाहिये, वह मिले, गरीबों को मिले। लेकिन बीच में लोग पैसा उड़ा लेते हैं, जिस की वजह से जो गरीबों को मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं जो बहुत बहादुरी से काम कर रही है।

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH) : Although the government is very much aware of the problem being discussed, Shri Rajnath Sonkar Shastri moved a motion and a very large number of friends have taken part in the debate. A very large area of the country suffers annually from floods and drought, drought and floods successively, alternatively and simultaneously also. We have been paying a very great attention to this problem from two sides. (1) The main relief comes from preventive measures that have been adopted and large sums of money have been provided in the past plans for prevention of floods or at least for reducing their fury where it has been possible ; and also assistance has been provided against drought whenever it has been occuring in a very serious proportion.

Before I come to the actual steps taken during this year and the last year to mitigate the misery of the people, I would like to inform the members about the system that we follow. The procedure has been laid down by the Seventh Finance Commission for providing relief in cases of natural calamities and such disasters. There is an amount of margin money that is placed at the disposal of each State every year. Normal disasters of calamities are supposed to be looked after by the States with the help of this margin money. It is when this money is not found sufficient that the States appeal to the Centre and send memoranda on the basis of which the Central Government has a mechanism for assessing the real problems and the requirements for providing relief to the affected people. The central team visits various States ; they go into the facts given by the States, make their own estimates and assessment and then a high level committee

looks into the recommendations of these teams which are composed of representatives of a few Ministries like the Agriculture Ministry, the Ministry of Finance and the Planning Commission. Officers from other Ministries are drawn to be included in these teams in the case of specific problems in the States. For instance, if there is a flood, an officer of the Irrigation Ministry would be requested to go. If it requires a particular specialist and an engineer, then an expert would be requested to go there. On the basis of the recommendations of the high level Committee the Finance Ministry takes the decision and money is released. For flood, cyclone and such disasters the quantum of assistance that the Central Government provides is 75 per cent of the money needed or proposed to be spent by the State. This is after the margin money has been spent or adjusted. In the case of drought the procedure is not very different. Some members have tried to make out that for drought the Central Government does not take as sympathetic a view as in the calamity from flood. It is not correct. In the case of drought, upto 5 per cent of the development plan of a State is generally sanctioned by the Central Government as additional plan assistance. If the expenditure is more than 5 per cent of the annual development plan, the Central Government shares 50 per cent of the expenditure. Whatever is given as advance plan assistance is adjusted against the State plan over a period of five years. Where there is a very severe drought, very big calamity, free assistance, grant or whatever you may call it, is given from the Central Government. It is not that everything is loan in the case of drought.

SHRI RAM PYARE PANIKA : What about UP ?

RAO BIRENDRA SINGH : We have discussed it several times. UP did not ask for any assistance earlier. But on the demand of the Members, they asked for assistance later.

I would like to give the figures of liberal assistance that the Central Government has provided to the States in the past few years. In the case of drought, in 1979-80, which was a very bad drought year and Mr. Dandavate's Government was in power, the amount of assistance given to all the States was of the order of Rs. 193 crores.

PROF. MADHU DANDAVATE : It was not my Government but Mr. Morarji Desai's Government.

RAO BIRENDRA SINGH : When Mrs. Gandhi's Government came in, immediately we took note of the fact that the assistance provided to the States was not adequate. It was the same drought that was continuing. It was not a new drought in 1980. The same year in addition to what they had given, Mrs. Gandhi's Government sanctioned Rs. 264 crores. This was for the same drought which you thought needed only Rs. 193 crores. Additional Rs. 264.22 crores was given as assistance.

SHRI R.L. BHATIA (Amritsar) : Mr. Madhu Dandavate was busy with the Railways.

PROF. MADHU DANDAVATE : Was the assistance increased because of the increase in inflation ?

RAO BIRENDRA SINGH : I give you full credit for behaving like a professor. You tried to find something.

In the year 1981-82, though whether conditions were not ideal but they were good and our production also was a record production in the year 1981-82 but in spite of that, an assistance of Rs. 192.60 crores was given against drought. In the year 1982-83, which is the last year, for drought relief the amount sanctioned by the Central Government is Rs. 436.26 crores, on drought alone, and it is last year because it was a drought year. We agree that it was a very bad drought year but this additional money also sanctioned was an all-time record and compare it with the 1979-80 drought year when the other Government... (*Interruptions*). We did not stop at that, we have continued assistance even in the current year. The drought was last year, fortunately it is a good whether now. The monsoon is helping us but in spite of that we are continuing assistance on account of drought and an amount of Rs. 268.78 crores on drought has also been sanctioned after March this year, in 1983.

SHRI M.M. LAWRENCE (Idukki) : As grant or as flood advance ?

RAO BIRENDRA SINGH : I do not know, I have given you the whole system and told you how it works. This brings us to a total sum of Rs. 781 crores given for drought year 1982-83 which is continuing into 1983-84. In spite of that if some hon. Members feel that Government of India has not provided sufficient funds, I only sympathise with their thinking. There is a tendency on the part of some States to use this avenue for providing relief against natural calamities to augment their States' resources and it is there that we have to exercise some check. I can give you examples where the normal programmes are not being taken up by the State Governments because they have to provide some share and because with this money, most of which comes free to them, they take up their normal development plan works under our assistance.

SHRI M.M. LAWRENCE : Which are the States ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why don't you wait ?

SHRI M.M. LAWRENCE : We want to know, this is a serious allegation....(*Interruptions*)

SHRI A.K. BALAN (Ottapalam) : Minister should not hide things...(*Interruptions.*)

RAO BIRENDRA SINGH : I will talk about Tamil Nadu also, don't worry, and about West Bengal too.

Since my hon. friend, the Minister of Irrigation, has decided not to intervene to save the time of the House, it becomes my duty to inform the hon. Members about what this Ministry has been doing because, after all, it is irrigation which can prevent floods. It is a known fact that targets for extension of irrigation set in this country since this Government took over in the Sixth Plan probably have never been set by any other country anywhere in the world and they have never been achieved at this rate. 14 million hectares of additional land to be brought under irrigation in one Five Year Plan could not even be imagined. But our Government have done that and the targets are more or less achieved. About 2.5 million to 3 million hectares of land have been added every year during the past three years of this Plan period.

Another very important programme which can prevent this calamity from flood are the flood control measures. Everybody knows, it has been discussed so many times in the House, that there are certain geographical and natural limitations for controlling floods. There are not many suitable storage sites in the country. We have about 1,440 million acre-feet of water flowing into the rivers, and most of it flows during the three monsoon months through our northern rivers. We have not been able to harness more than 140 million acre-feet of this huge water mass of 1,440 million acre-feet so far. But efforts are being made, negotiation are going on with the neighbouring country of Nepal. We want to store more water for irrigation so that drought will no longer occur in this country. Flood control measures are being adopted.

During the 30-year period, up to the end of the Fifth Five Year Plan, say up to March 1980, when this Government had just taken over, the total outlay on flood control was Rs. 976 crores. But, for the Sixth Plan, this Government has provided an outlay of Rs. 1,045 crores. Now some hon. Members.. (*Interruptions*)

I was trying to inform the hon. Members that this is a very big problem. As pointed out, there are 40 million hectares of land, which is flood-prone. Out of that, according to experts, not more than 32 million hectares can be protected ; 8 million hectares can still not be protected. Out of that 32 million hectares, this Ministry has been able to look after about 11.17 million hectares so far. During the Sixth Plan period, the target of the Ministry is to protect 2.55 million hectares more. About 8 million hectares of land on an average suffers from floods annually, from year to year. Orissa, West Bengal, Assam, some other northern States. Eastern U.P. and Bihar suffer very big damage every time because of floods. Orissa was badly affected in the past, first by cyclone and then by floods. But, Sir, I cannot understand any hon. Member complaining that enough money was not pro-

vided for Orissa for flood relief and for taking anti-flood measures and flood protection measures.

PROF. MADHU DANDAVATE : About measures Mr. Patnaik was complaining the other day, Sir.

RAO BIRENDRA SINGH ; You will be surprised to know that the total plan outlay for flood control for the year 1983-84, both the Central sector and the State sector plans put together, is of the order of only Rs. 160 crores. The total outlay for both Central and State sectors for this year is that much only, Rs. 160 crores. The total Plan is Rs. 1,045 crores. But last year, Orissa alone got Rs. 170 crores for flood and cyclone relief, Rs. 10 crores more than the amount given for the whole national plan on flood control. And yet, I am surprised if somebody blames the Central Government for not being liberal enough to provide relief and succour.

Now, a very important point crops up. All the States and all the hon. Members want more and more money and when money is given, when liberal assistance is given, they complain that money is not properly utilised. But this is going to happen and when we try to control the matter, to exercise a check, then an outcry goes that the Centre is stingy and not liberal or generous enough. Sir, it is not imaginable that a State Government would be able to spend Rs. 170 crores for anti-flood measures because they are not having that infrastructure and that machinery, and engineers cannot be created overnight.

AN HON. MEMBER : What happened to that money ?

RAO BIRENDRA SINGH : Material cannot be purchased overnight. That is why there are complaints that all this money was not utilised. Similarly, in the case of West Bengal they wanted huge sums for drought relief and when we sanctioned it, now they are coming forward with a request, 'Please extend the period, we could not spend it up to June'. The money is not utilised in time.

AN HON. MEMBER : What is wrong ?

RAO BIRENDRA SINGH : Because it was intended to be spent within period over which the State Government have projected their estimates. (*Interruptions*). It cannot be used.

(*Interruptions*)

SHRI SUNIL MAITRA (Calcutta North-East) : How many instalments you paid ? Was it paid in one instalment ?

(*Interruptions*).

RAO BIRENDRA SINGH : I don't want to tease my hon. Members because everybody knows...

(*Interruptions*).

I have brought it home to them several times that not to always shout about West Bengal and that it will come back on them.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly) : What is the truth ?

RAO BIRENDRA SINGH : Are you wanting to know the truth or you just want to interrupt ? You listen now. I will give you the truth. The truth is that West Bengal is the only State in the country where the Central Government was so generous that within one financial year, the Central teams were sent twice and again third time. West Bengal is the only State where against all our norms and practices that we have adopted for the Congress-ruled States and which we are implementing. West Bengal Government came forward for gratuitous relief, assistance, after the monsoon season had started...

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : For what ?

RAO BIRENDRA SINGH : For feeding the people in the camps while they should be working in the fields, while they should be sowing their crops and planting paddy. Even though we sanctioned the amount of Rs. 3.56 crores.

SHRI SUNIL MAITRA : You must be knowing that still that is not sufficient.

(*Interruptions*)

MR. DEPUTY SPEAKER : Why are you objecting ? He is only saying what the Central Government has done.

RAO BIRENDRA SINGH : They could not utilise the money and we agree to their

request to extend the time. You see our generosity.

SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : Why are you favouring West Bengal ?

RAO BIRENDRA SINGH : We are not favouring West Bengal. We are trying to look after the people of West Bengal.

PROF. RUP CHAND PAL : That should be the mission. That is all right. You are not favouring the State Government.

MR. DEPUTY-SPEAKER : People in any State are the people of India. The Central Government has a responsibility to take care of the people of India ; they may be in West Bengal or Assam or any State. They are doing their duty only.

RAO BIRENDRA SINGH : If the hon. Members are interested, I would like to give some figures about the amount of assistance sanctioned in respect of some of the States about which mention has been made specifically by several hon. Members. For the year 1982-83, Kerala has been sanctioned Rs 40.87 crores—Rs 4.10 crores during the year 1982-83 and Rs, 36.77 crores for drought relief in the current year.

SHRI CHITTA BASU : What was their projected demand ?

RAO BIRENDRA SINGH : Forget about their demand.

SHRI A. NEELALOHITHADASAN NADAR : What was the demand ?

RAO BIRENDRA SINGH : Mr. Nadar, if we try to take into account the inflated demands that the States make and we take notice of all that probably you will suffer the most. So, don't talk about that.

RAO BIRENDRA SINGH : Don't talk about what demands you project. For Madhya Pradesh that is the same as Kerala. During 1982-83 and 1983-84 a sanction of Rs. 60.96 crores was made.

Rajasthan was sanctioned Rs. 106.75 crores.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : तभी हमने आपकी तारीफ की है लेकिन वहां पर उसकी व्यवस्था ठीक नहीं है । आपकी तरफ से कोई कमी नहीं हैं और उसके लिए हम आपके थैंकफुल हैं ।

RAN BIRENDRA SINGH : We have given lot of money for sanction of tubewells, for hand-pumps; for cattle camps and what not.

MR. DEPUTY-SPEAKER : What have you given to Rajasthan canal ?

RAO BIRENDRA SINGH : It is looked after. First stage is complete. Second stage is progressing well. People are being assisted in Food Programme also in that area.

Tamilnadu has been sanctioned a total of Rs. 68.36 crores ; Rs. 49.97 crores for current year and Rs. 18.39 crores last year. 20,000 borewells for drinking water sanctioned. Now they have requ sted us increase the number to 24,000. We are considering their demand.

PROF. MADHU DANDAVATE : There is no water in boring wells.

MR. DEPUTY SPEAKER : We are also giving water by train.

RAO BIRENDRA SINGH : West Bengal was given Rs. 74.27 crores for drought relief last year and Rs. 30.59 crores in the current year making a total of Rs. 105 crores approximately.

SHRI CHITTA BASU ; But the projected demand was Rs. 200 crores.

RAO BIRENDRA SINGH : You have not been able to utilise this amount. You have been asking for extension of time.

Mr. Dandavate's suggestion is very good. Probably.

PROF. RUP CHAND PAL : In what respect ?

RAO BIRENDRA SINGH : He himself would not like that the people

should suffer on account of the inefficiency of some State Government. I was talking about drought, Not the floods.

PROF. MADHU DANDAVATE : How much was sanctioned for the recent floods in the Konkan region ?

RAO BIRENDRA SINGH : I would like to mention everything if time permits. But you know that you are also tired.

Gujarat was sanctioned Rs. 72.91 crores for flood relief last year.

Orissa Rs. 170.51 crores.

Uttar Pradesh Rs. 66.82 crores. I think that should satisfy you. We have received memoranda. We have received memoranda from some State Governments. A team has visited Himachal in June, and we are looking into the report. A team has been ordered to visit Karnataka and Maharashtra...

PROF. MADHU DANDAVATE : That was before the floods :

RAO BIRENDRA SINGH : About the Konkan flood which you mentioned, a team will visit. We shall look into the whole problem.

PROF. MADHU DANDAVATE: So far the Maharashtras Government has not sent you any report and, therefore, the amount sent is zero rupee. Is it correct ?

RAO BIRENDRA SINGH : The Maharashtra Government is looking after the Problem out of the margin money that it has got. The relief operation should not stop, should not stay, on account of the Central Government not sanctioning some money because the margin money is meant for this purpose. They immediately take up the work.

श्री अब्दुल रशीद काबुली : उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू-काश्मीर में हेल स्टार्म से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है और पिछले पांच साल से बराबर हो रहा है। फ्रूट्स के दरख्त वगैरह तबाह हो गए हैं मेवे के फल वगैरह तबाह हो गए हैं। क्या उसके सर्वे के लिए कोई टीम भेजी है ? उसकी तहकीकात कराकर स्टेट को रिलीफ दें।...(व्यवधान)...

شری عبدالرشید کابلی

ادھیکش مہودے۔ جموں کشمیر میں ہیل اسٹارم سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اور پچھلے پانچ سالوں سے برابر ہو رہا ہے۔ فروٹس کے درخت وغیرہ تباہ ہو گئے ہیں۔ میوے کے پھل وغیرہ تباہ ہو گئے ہیں۔ کیا اس کے سروے کے لئے کوئی ٹیم بھیجی ہے۔ اس کی تحقیقات کراکر اسٹیٹ کو رکھدیں۔

۔۔۔۔ (انٹرپشن) ۔۔

राव बीरेन्द्र सिंह : मेरी तव्वजह काश्मीर की तानिब मब्जूल करना चाहते हैं, तो फिर मुझे कुछ कहना पड़ेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : जरूर कहिए।

شری عبدالرشید کابلی ضرور کہیئے۔

राव बीरेन्द्र सिंह : जम्मू-काश्मीर जैसा कि आपने कहा, इस बात की शिकायत करता है कि हमने इमदाद माँगी थी, लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट अभी तक कुछ नहीं देती है। सरकार कायदा हमारा यह है कि जो पहले एक करोड़ 30 लाख की रकम आपके पास मार्जिन मनी है, उसमें आपने क्या काम किया है ? वह किस चीज पर खर्च किया और यदि आप उसका थोड़ा सा हिसाब दे दें तो आगे आपकी बात पर गौर करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : हिसाब किताब नहीं होता।

राव बीरेन्द्र सिंह : हिसाब किताब नहीं होता तो मांग क्यों रहे हैं श्री नामग्याल जी ने ठीक कहा। जम्मू की एक करोड़ 89 लाख की इमदाद की दरख्वास्त है, इनकी दरख्वास्त पर तब हम गौर करेंगे, जब यह पता लगे कि एक करोड़ 30 लाख रुपया जो आपके पास था,

उसका क्या हुआ। पहले यह बताइए उसको खर्च पाए हैं या नहीं, उसके बाद ही सैन्ट्रल गवर्नमेंट से मजीद मंगाइए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : इनकी डिमांड क्या थी।

شری عبدالرشید کابلی

ان کی ڈیمانڈس کیا تھیں؟

राव बीरेन्द्र सिंह : एक करोड़ 89 लाख है और आपके पास पहले ही एक करोड़ 30 लाख रुपए पड़ा हुआ है।

PROF. MADHU DANDAVATE : He is very clear. In anticipation of the storm, advance money was already given.

RAO BIRENDRA SINGH : It is margin money at the disposal of every State Government. The Maharashtra Government also has got.

I think, I have given replies to most of the points raised by the hon. Members. Mr. Balanandan mentioned Tripura, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala. I have given the figures in respect of all these States. Some hon. Members from West Bengal and Tripura came to me the other day. We had immediately taken action to get the details from the State Government, and we have received the telex message also. They have asked for an assistance of Rs. 1 crore and 5,000 tonnes of foodgrains, additional allocation. We have recommended their case for additional food allocation and we are also looking into this demand of Rs. 1 crore.

I think, hon. Members would feel satisfied that, as far as the Central Government is concerned, for drought and floods, we are doing our maximum within the means.

(*Interruptions*)

MR DEPUTY SPEAKER ; No, no. We have had the discussion. No clarification.

SHRI E. BALANANDAN . On a point of clarification, Sir.

MR DEPUTY SPEAKER : Only Mr. Balanandan and nobody else.

SHRI E. BALANANDAN : I have reqested the Minister to consider the latest request made by Kerala and West Bengal in the present context. Even though I do not dispute any statement you have made, will you consider these requests leniently ?

RAO BIRENDRA SINGH : I think that is a reflection on what I have said.

We always consider every such request sympathetically and most sympathetically.

PROF MADHU DANDAVATE : I want some clarification. I will ask him outside.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr Rajnath Sonkar Shastri.

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस प्रस्ताब पर सदन के माननीय सदस्यों में जो अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं, उस सन्दर्भ में आप सब को बधाई देता हूं। इस में कोई सन्देह नहीं कि विद्वान साथियों ने इस विषय पर अपने बड़े अमूल्य सुझाव दिये हैं और बहुत सी बातें सरकार के सामने रखीं। हमारे मन्त्री जी ने भी, यदि मैं एक सेन्टेन्स में कहूं, तो अपनी सारी बातों के साथ-साथ आंकड़ों से हम लोगों का पेट भर दिया। एक गम्भीर बात यह हुई कि किस प्रकार हम सूखे से बचें, किस प्रकार हम बाढ़ से बचें, इस विषय पर कोई गम्भीर ढंग से ध्यान नहीं दिया गया। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, मैं इस विषय की गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक बात मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे कुछ साथियों ने जो केरल के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में तथा जहां-जहां यह गम्भीर समस्या व्याप्त है, उन के बारे में सुझाव दिये हैं, संशोधन दिये हैं। हमारे मधु दण्डवते साहब ने, चित्त बसु साहब ने,

हमारे जम्मू-काश्मीर के माननीय सदस्य ने अपने संशोधन दिये हैं, मैं चाहूंगा कि इन सब संशोधन पर...(**व्यवधान**)...आप को क्या परेशानी हो रही है ? अगर भाषण देना शुरू कर दूंगा तो दो घन्टे यूं ही निकल जायेंगे । मैं निवेदन कर रहा था कि इन संशोधनों का माननीय मंत्री जी स्वीकार करें और साथ ही जो यह बाढ़ तथा सूखे की हमारे देश में समस्या है इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने की सरकार द्वारा कोशिश की जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

MR DEPUTY-SPEAKER : I will now dispose of the amendments. Mr Dandavate-are you insisting on your amendment ?

PROF MADHU DANDAVATE : He is accepting it.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is...

PROF MADHU DANDAVATE : Just a minute, Sir. Did you ask whether he is accepting my amendment ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : If he has accepted, he would have stood up and said so.

I will now put the amendment of Mr Dandavate to vote.

Amendment No. 1 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Chitta Basu, are you pressing your amendment ?

SHRI CHITTA BASU : Yes, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall put amendment No. 2 moved by Shri Chitta Basu to the vote of the House.

Amendment No. 2 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Kabuli ? Are you pressing your amendment ? When the Minister was replying, I thought you were very much satisfied.

SHRI ABDUL RASHEED KABULI : I press my amendment.

MR. DEPUTY-SPEAKER ; I shall now put Amendment No. 3 moved by Shri Abdul Rashid Kabuli to the vote of the House.

Amendment No. 3 was put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the motion moved by Shri Rajnath Sonkar Shastri to the vote of the House. The question is :

> "That this House do take note of the situation arising out of the annual floods and drought in various parts of country resulting in heavy loss of life, property and crops seriously affecting the economy of the country and the imperative need for the implementation of the short-term and long term messures to meet the situation."

The motion was negatived

MR. DEPUTY-SPEAKER : How, the House stands adjourned to re-assemble at 11 A.M. tomorrow.

21.41 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, August 12, 1983/Sravana 21, 1905 (Saka)

Printed at S. Narayan & Sons, 7117/18, Pahari Dhiraj, Delhi-6.